चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

15 दिसंबर–21 दिसंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

यूआईडी कार्ड ख़तरनाक है

देश में क़ानून का राज ख़त्म हो गया है

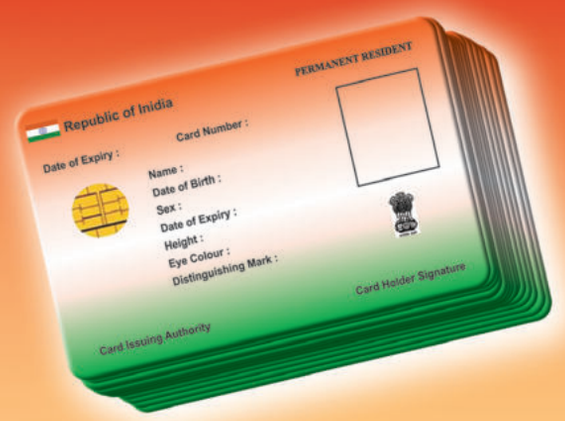

नरेंद्र मोदी सरकार को देश की सुरक्षा और भविष्य की चिंता नहीं हैं. अगर है, तो फिर वह देश की सुरक्षा से समझौता करने पर क्यों तुली है. मनमोहन सरकार से तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अगर मोदी सरकार भी वही गलतियां दोहराए, तो देश के भविष्य और सुरक्षा को लेकर सबको चौकन्ना हो जाना चाहिए. क्या यह चिंता की बात नहीं है कि सेना अध्यक्षों और खुफिया अधिकारियों पर विदेशी एजेंसियां निगरानी रखें. क्या यह चिंता की बात नहीं है मंत्रियों, सचिवों और हर महत्वपूर्ण अधिकारी के क्रियाकलापों की पूरी जानकारी विदेशी खुफिया एजेंसियों के पास हो. क्या यह एक गंभीर संकट नहीं है कि भविष्य में बनने वाले भारत के सभी सेना अध्यक्षों, खुफिया अधिकारियों, मंत्रियों, सचिवों और महत्वपूर्ण अधिकारियों की सारी जानकारियां विदेशी खुफिया एजेंसियों के पास हों. हैरानी की बात यह है कि विदेशी खुफिया एजेंसियों को यह सारी जानकारियां भारत की सरकार ही मुहैय्या करा रही है. देश पर एक स्पष्ट और आसन्न ख़तरा मंडरा रहा है और देश के विपक्षी दल और मीडिया धृतराष्ट बने बैठे हैं.

मनीष कुमार

क्या इस देश में क़ानून का राज ख़त्म हो गया है? केंद्र सरकार आधार योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साफ़-साफ़ उल्लंघन कर रही है. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि देश के नागरिकों पर आधार कार्ड जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को लेकर 23 सितंबर 2013, 26 नवंबर 2013 और 24 मार्च 2014 को एक के बाद एक ताबड़तोड़ तीन आदेश दिए, लेकिन सरकार लगातार इन आदेशों की अवमानना करने पर तुली है. इन आदेशों में साफ़-साफ़ कहा गया है कि आधार कार्ड को सरकार की किसी योजना में अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है. यह भी कहा गया कि आधार नंबर न होने की स्थिति में किसी को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक स्वैच्छिक योजना है और इसे फिलहाल स्वैच्छिक ही रहने दिया जाना चाहिए. लेकिन देश की सरकार है कि इस कार्ड को पिछले दरवाजे से हर जगह अनिवार्य करने में लगी हुई है. आधार कार्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो आदेश दिए हैं, उनमें यह साफ़ है कि इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है. लेकिन, हैरानी की बात यह है कि मोदी सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है.

आधार योजना यूपीए सरकार की योजना है. यह योजना सुरक्षा और क़ानून की दृष्टि से सवालों के घेरे में है. यूपीए सरकार के दौरान भाजपा ने इस योजना पर सवाल खड़े किए. चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने साफ़-साफ़ कहा था कि उसकी सरकार आते ही इस योजना पर पुनर्विचार किया जाएगा. चुनाव हो गए, भाजपा की सरकार भी बन गई, लेकिन सिर्फ़ एक बार यूआईडी अथॉरिटी के चेयरमैन नंदन नीलेकणी से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात क्या हुई, भाजपा का स्टैंड बदल गया. यह क्लोज-डोर मीटिंग एक जुलाई को हुई. इसमें नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और नंदन नीलेकणी मौजूद थे. अब पता नहीं, यूपीए सरकार के सुपरमैन नंदन नीलेकणी ने नरेंद्र मोदी को क्या पट्टी पढ़ाई कि पांच जुलाई को प्रधानमंत्री ने इस ख़तरनाक योजना को जीवनदान दे दिया. क्या संसद और देश को यह जानने

भाजपा के तत्कालीन प्रवक्ता प्रकाश जावेड़कर ने कहा था कि आधार योजना कों लेकर पार्टी की दो चिंताएं हैं. एक तो इसका क़ानूनी आधार और दूसरा सुरक्षा का मुद्दा. प्रकाश जावेड़कर अब मंत्री हैं. अब केंद्र में भाजपा की सरकार है. तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आधार को लेकर सरकार ने ऐसे क्या फ़ैसले लिए हैं, जिससे ये दोनों चिंताएं ख़त्म हो गईं? क्या आधार को लेकर संसद में लंबित बिल पास हो गया?

का अधिकार नहीं है कि सरकार ने एक ग़ैर-क़ानूनी योजना को हरी झंडी क्यों दी? क्या सांसदों और मीडिया को यह नहीं पूछना चाहिए कि आख़िर क्या वजह है कि यूआईडी बिल बिना पास किए यूआईडी योजना लागू क्यों हुई और नई सरकार ने इसे जारी क्यों रखा?

यही नहीं, प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ नए कार्ड जल्द से जल्द बनाने का टारगेट भी दे दिया. इस मीटिंग के ठीक नौ दिनों बाद अरुण जेटली ने बजट पेश किया और यूआईडी की धनराशि 1550 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2039 करोड़ रुपये कर दी. आश्चर्यजनक बात यह है कि मोदी-नीलेकणी की इस मुलाकात से ठीक दो दिन पहले यूआईडी को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सूचना तकनीक व क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी. इस मीटिंग का निष्कर्ष यूआईडी के ख़िलाफ़ था. इसके अलावा यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद भाजपा के तत्कालीन प्रवक्ता प्रकाश जावेड़कर ने कहा था कि आधार योजना कों लेकर पार्टी की दो चिंताएं हैं. एक तो इसका क़ानूनी आधार और दूसरा सुरक्षा का मुद्दा. प्रकाश जावेड़कर अब मंत्री हैं. अब केंद्र में भाजपा की सरकार है. तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आधार को लेकर सरकार ने ऐसे क्या फ़ैसले लिए हैं, जिससे ये दोनों चिंताएं ख़त्म हो गई? क्या आधार को लेकर संसद में लंबित बिल पास हो गया? क्या सुप्रीम कोर्ट का आख़िरी फ़ैसला आ गया? क्या हमने लोगों के बायोमैट्रिक डाटा को विदेशी कंपनियों के सुपुर्द करना बंद कर दिया? क्या हमने विदेशी खुफिया एजेंसियों से जुड़ी कंपनियों को आधार योजना से अलग कर दिया? सरकार को यह बताना चाहिए कि आख़िर उसने ऐसा कौन-सा जादू किया है कि कल तक जो योजना ख़तरनाक थी, वह आज सही हो गई.

क्या देश के अख़बारों और टीवी चैनलों के संपादकों को देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है. वे अंधों की तरह सरकारी प्रेस विज्ञप्ति रिलीज ऐसे छापते हैं, जैसे सरकार द्वारा भेजी गई हर प्रेस विज्ञप्ति आकाशवाणी हो, ब्रह्मसत्य हो. अख़बारों की इसी आदत के चलते पत्रकारिता की साख ख़त्म हो रही है. यही हाल देश की विपक्षी पार्टियों का है. क्या संसद में इस ग़ैर-क़ानूनी और ख़तरनाक योजना के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी? कांग्रेस पार्टी तो आधार योजना की जननी है, लेकिन जो लोग न भाजपा में हैं और न कांग्रेस में, वे क्यों चुप हैं? क्या यह उनका कर्तव्य नहीं है कि वे जनता के अधिकार के लिए संसद में आवाज़ उठाएं और सरकार से पूछें कि देशवासियों के पर्सनल

(शेष पृष्ठ 2 पर)

प्रधानमंत्री से दस सवाल

- सुप्रीम कोर्ट ने आधार योजना को लेकर 23 सितंबर 2013, 26 नवंबर 2013 और 24 मार्च 2014 को एक के बाद एक ताबड़तोड़ तीन आदेश दिए. कहा, देश के नागरिकों पर आधार कार्ड जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है. सरकार उक्त आदेशों की अवमानना क्यों करना चाहती है?
- चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने कहा था कि उसकी सरकार आते ही इस योजना पर पुनर्विचार किया जाएगा. यूआईडी अथॉरिटी के चेयरमैन नंदन नीलेकणी से प्रधानमंत्री की मुलाकात होते ही भाजपा का स्टैंड क्यों बदल गया?
- भाजपा के तत्कालीन प्रवक्ता प्रकाश जावेड़कर ने कहा था कि आधार योजना कों लेकर पार्टी की दो चिंताएं हैं. एक तो इसका क़ानूनी आधार और दूसरा सुरक्षा का मुद्दा. क्या उक्त चिंताएं अब ख़त्म हो गई हैं?
- आधार को लेकर संसद में बिल लंबित है फिर यह योजना क्यों जारी है?
- देशवासियों के पर्सनल सेंसिटिव डाटा को विदेश भेजा जा रहा है या नहीं ?
- आधार के नागरिक इस्तेमाल को सैन्य इस्तेमाल से क्यों जोड़ दिया गया?
- सरकार क्यों नहीं बताती कि इस योजना पर कितना पैसा खर्च होगा?
- पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक़, क्या आधार योजना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कराने जैसा और नागरिकों की संप्रभुता और निजता के अधिकार पर हमला नहीं है?
- आधार योजना लागू करने का काम सरकारी एजेंसियों की बजाय विदेशी कंपनियों के हाथों में क्यों है?
- क्या ऐसी कंपनियां खुफिया एजेंसियों द्वारा नहीं चलाई जा रही हैं?

यूआईडी से देश की सुरक्षा को ख़तरा पेज-03

आधार कार्ड पर पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है पेज-04

दिल्ली विधानसभा चुनाव और मुसलमान पेज-06

साई की महिमा पेज-12

देश में क़ानून का राज ख़त्म हो गया है

पृष्ठ एक का शेष

सेंसिटिव डाटा विदेश भेजने का काम क्यों जारी है? क्या देश के सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे पूछें कि आधार के नागरिक इस्तेमाल को सैन्य इस्तेमाल से क्यों जोड़ दिया गया, जबकि पिछली सरकार के दौरान विदेश, गृह एवं सूचना तकनीक की संसदीय स्थायी कमेटी आधार और बायोमैट्रिक जानकारियों के क्लाउड स्टोरेज के ख़तरे से आगाह कर चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. संसदीय कमेटियों ने इसे ख़तरनाक करार दिया है. दुनिया के दूसरे देशों में यह योजना रोक दी गई है. इस विषय के जानकार और विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आधार योजना जारी है और वह भी ग़ैर-क़ानूनी तरीके से. अब देखना यह है कि सर्वशक्तिमान सरकार के ख़िलाफ़ सच बोलने वाला देश में कोई बचा है भी या नहीं.

यही काम कांग्रेस की सरकार ने किया था. तब भाजपा के यशवंत सिन्हा के नेतृत्व वाली संसदीय कमेटी ने इसे ख़त्म करने की सलाह दी थी. चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार ने कहा था कि सरकार बनने के बाद भाजपा इस योजना को कूड़ेदान में फेंक देगी. लेकिन, आज उसी भाजपा ने आधार योजना को लागू कराने के लिए सारे नियम- क़ानून ताख पर रख दिए हैं. आधार कार्ड पर खरबों रुपये खर्च हो चुके हैं. आगे कितना खर्च होगा, इसका कोई पता नहीं है. आरटीआई के तहत भी यह नहीं बताया जाता कि इस योजना में कितना पैसा खर्च होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड के नाम पर ग़ैर-क़ानूनी तरीके से देश के लोगों की पर्सनल बायोमैट्रिक इन्फॉर्मेशन्स इकट्ठा की जा रही हैं. इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि उक्त सारी जानकारियां विदेशी कंपनियों को सौंपी जा रही हैं. ऐसी कंपनियां, जिनका रिश्ता अमेरिका और फ्रांस की खुफिया एजेंसियों से है. देश की सरकार को तो ईनाम मिलना चाहिए कि संविधान और कोर्ट के रहते हुए वह एक ऐसी योजना लागू करने में सफल हो जाती है, जो न सिर्फ़ ग़ैर-क़ानूनी है, बल्कि जिससे विदेशी खुफिया एजेंसियों के पास देश के लोगों की जानकारियां पहुंच जाने का ख़तरा भी है.

चौथी दुनिया लगातार आपको आधार कार्ड के ख़तरे से आगाह करता रहा है. जो ख़तरा पहले था, आज भी वही ख़तरा बना हुआ है. उक्त विदेशी कंपनियां देश के लोगों के बायोमैट्रिक डाटा को क्लाउड तकनीक के ज़रिये स्टोर करेंगी यानी इकट्ठा करेंगी. फरवरी 2014 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइबर सिक्योरिटी पर एक रिपोर्ट आई. इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई कि आधार योजना न सिर्फ़ राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है, बल्कि साथ ही नागरिकों की संप्रभुता और निजता के अधिकार पर हमला भी है. क्योंकि, जिस तरह से लोगों के बायोमैट्रिक डाटा को क्लाउड टेक्नोलॉजी के तहत स्टोर किया जा रहा है, उस पर देश की सरकार का कोई अधिकार नहीं है. देश का क़ानून उस पर लागू नहीं हो सकता है. अगर लोगों की जानकारियां कॉपी भी हो गईं या कोई उन्हें हैक करके प्राप्त कर लेता है, तो उसके ख़िलाफ़ भारत कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा. अब तो यह बात देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि जो डाटा एक बार देश के बाहर चला गया, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता. डिजिटल डाटा की कॉपी बनाना न सिर्फ़ आसान है, बल्कि इसमें समय भी नहीं लगता. यह कैसी सरकार है, जो क़ानून और संविधान के बाहर जाकर योजनाएं लागू कर रही है? और, देश का विपक्ष है, जिसमें सिर्फ़ अभद्र भाषा के नाम पर संसद में हंगामा करने की अक्ल शेष है. यूआईडी जैसे संवेदनशील मामले में ये सब स्कूली बच्चों की भांति अनुशासित हो जाते हैं, मुंह से आवाज़ ख़त्म हो जाती है. क्या जनता अब यह समझ ले कि देश की संसद और उसके अंदर मौजूद सांसद विदेशी कंपनियों के गुलाम बन गए हैं? क्या यही संदेश देश की संसद देना चाहती है कि यहां राष्ट्र की सुरक्षा और जनता के अधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं है?

आइए, अब जरा देखते हैं कि यूपीए सरकार ने किस तरह देश की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों के साथ समझौता किया और किस तरह मोदी सरकार उसी ख़तरनाक समझौते को मजबूत कर रही है. इस आधार योजना की खासियत यह है कि इसका काम सरकारी एजेंसियों से नहीं कराया जा रहा है. सरकार ये सारा काम देशी-विदेशी कंपनियों के हाथों में दे रही है. कार्ड बनाने से लेकर उसके ऑपरेशन तक का काम निजी कंपनियों के पास है. इनमें हर किस्म की कंपनियां हैं. कुछ कंपनियों की कहानी तो यह है कि समझौता करने के बाद वे किसी और कंपनी के साथ विलय हो गईं. यह एक अलग डराने वाला खेल है. लेकिन, फिलहाल हम देखते हैं कि यूपीए के सुपरमैन नंदन नीलेकणी ने क्या-क्या गुल खिलाए हैं. यूआईडी और एसेंचर कंपनी के बीच हुए समझौते का अनुच्छेद 15.1 कहता है कि इस अनुबंध के तहत एसेंचर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड या एसेंचर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड की टीम खरीददार या किसी तीसरे पक्ष या भारत के किसी भी निवासी की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सकती है. कहने का मतलब यह कि इस करार के तहत विदेशी कंपनियां देश के लोगों के बायोमैट्रिक डाटा का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं.

इस समझौते में यूआईडी के ज़रिये देश के राष्ट्रपति को खरीददार बनाया गया है. अब सवाल यह है कि यूआईडी अथॉरिटी को किसने यह अधिकार दिया कि वह भारत के नागरिकों की तरफ़ से यह समझौता कर ले? यह सवाल इसलिए उठता है, क्योंकि इस अथॉरिटी को लेकर जो बिल संसद में लाया गया, वह अभी तक पास नहीं हुआ. समझौते के अनुच्छेद 15.1 में यह भी कहा गया कि एसेंचर कंपनी इस डाटा को सात सालों तक अपने पास रख सकती है. सात सालों में तो भारत के लोगों की बायोमैट्रिक जानकारियों की इतनी कॉपियां बन जाएंगी कि कोई यह भी पता नहीं लगा पाएगा कि ओरिजनल यानी असली किसके पास है. इसी तरह का समझौता एल-1 आईडेंटिटी सोल्युशन ऑपरेटिंग कंपनी के साथ कर लिया गया. इस कंपनी की वेबसाइट बताती है कि उसकी खासियत यह है कि उसमें अमेरिका की सैन्य एवं खुफिया एजेंसियों के सबसे अनुभवी लोग काम करते हैं. अब इस कंपनी का विलय फ्रांस की कंपनी साफ्रान में हो गया है. साफ्रान के रिश्ते चीन से भी हैं. बस गनीमत यही है कि यूआईडी से जुड़े डाटा पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं.

अब जरा देखिए मोदी सरकार का कारनामा. दिल्ली के मंत्रालयों में अधिकारी समय पर पहुंचें, इसके लिए उन्होंने आधार को पिछले दरवाजे से यहां अनिवार्य बना दिया है. दिल्ली के मंत्रालयों में अब आधार कार्ड के ज़रिये उपस्थिति दर्ज कराने का प्रावधान किया जा रहा है. मतलब यह कि वर्तमान और भविष्य के सर्वोच्च अधिकारियों की सारी जानकारियां विदेश पहुंच चुकी हैं. और, जिनकी नहीं पहुंची हैं, सरकार उनके लिए स्टाल बनाकर उनके बायोमैट्रिक डाटा इकट्ठा कर रही है. विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले अधिकारी नाराज़ हैं. लेकिन, जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का ख्याल नहीं है, तो इन अधिकारियों की नाराज़गी की चिंता भला किसे होगी. यह व्यवस्था लागू कराने वाले राम सेवक शर्मा यूपीए सरकार के दौरान यूआईडीएआई के डायरेक्टर जनरल थे. फिलहाल वह डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सचिव हैं. वह यूआईडी से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट हैं. लेकिन कमाल की बात यह है कि वह आज भी गूगल का ईमेल इस्तेमाल करते हैं. समझने वाली बात यह है कि गूगल द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि गूगल मेल का इस्तेमाल लोग अपनी निजता का समर्पण करके ही कर सकते हैं. हो सकता है कि राम सेवक शर्मा के लिए राइट टू प्राइवेसी ज़्यादा महत्वपूर्ण न हो, लेकिन देश की जनता के लिए तो यह महत्वपूर्ण है. आप किस बात के एक्सपर्ट हैं, जो देश में अपना एक जी-मेल जैसा मेल सर्वर नहीं बना सकते. यह तो लानत भेजने वाली बात है. इस योजना को लागू करने का नतीजा यह है कि राम सेवक शर्मा ने देश की सेना से जुड़ी संस्थाओं में इसे लागू कराने के लिए चिट्ठी लिखकर भेज दी, जिसे उन्होंने अर्जेंट यानी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है. अब सवाल यह है कि इसे सेना से क्यों जोड़ा गया? सिटिजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के गोपाल कृष्ण का कहना है कि यह योजना शुरुआत से ही एक सैन्य योजना है. इसे सबसे पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने शुरू किया था. बाद में नाटो ने इसे अपनाया. सिविलियन रास्ते से इस योजना को डिफेंस में पहुंचना ही था. यूपीए सरकार के दौरान एडमिरल निर्मल वर्मा ने अपना कार्ड बनवाया था और अपने बायोमैट्रिक्स जमा कराए थे. आज एडमिरल वर्मा कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर हैं. मतलब यह कि भारत के हाई कमिश्नर की निगरानी के लिए खुफिया एजेंसियों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिरल वर्मा की सारी जानकारियां अमेरिकी कंपनी एसेंचर के पास हैं. क्या यह चिंताजनक विषय नहीं है? सरकार को यह बताना पड़ेगा कि देश के नागरिकों के पास निजता का कोई अधिकार है भी या नहीं. अगर है, तो लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां विदेशी कंपनियों और शत्रु देशों के पास भेजने का फ़ैसला यूआईडीएआई ने किस अधिकार पर लिया?

अगर मोदी सरकार देश की सुरक्षा और भविष्य को लेकर जरा भी संवेदनशील है, तो वह आधार योजना पर पुनर्विचार करे. अगर नहीं, तो कम से कम इतना उपकार ज़रूर कर दे कि देश की जनता और संसद को बताया जाए कि इस योजना को किस क़ानून के तहत लागू किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के पीछे कौन-सी वजह है? इससे पहले यह बताया जाए कि लोगों की आंखों की पुतलियों, अंगूठा निशान और बाकी बायोमैट्रिक जानकारियां किस क़ानून के तहत इकट्ठा की जा रही हैं? सरकार यह भी बताए कि लोगों के बायोमैट्रिक डाटा हम किन-किन देशों और कंपनियों को सौंपने का पाप कर रहे हैं. साथ ही उन कंपनियों के इतिहास के बारे में भी बताया जाए, जिन्हें खुफिया एजेंसियों के लोग चला रहे हैं. सरकार को यह बताना चाहिए कि वह आने वाले बीस सालों में इन कंपनियों को कितना फ़ायदा पहुंचाने का वादा कर चुकी है. बड़ी-बड़ी बातें करना आसान है, समाधान ढूंढना कठिन है. क्या हम भारत में एक मेल सर्वर नहीं बना सकते? क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते, जिसमें देशवासियों के बायोमैट्रिक डाटा विदेश न भेजने पड़ें? इन तमाम सवालों के जवाब अगर सरकार के पास नहीं हैं, तो विपक्ष ही देश की जनता को सच्चाई बताए. अगर विपक्ष को भी नहीं पता है, तो संविधान और देश में क़ानून का राज ख़त्म करने के पाप में सत्ताधारी दल और विपक्ष, दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 41
दिल्ली, 15 दिसंबर-21 दिसंबर, 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

मंत्रालय में चाय पर चर्चा

नरेंद्र मोदी द्वारा अपने चुनाव प्रचार में चाय पर चर्चा शुरू करने के बाद से ही चार पर चर्चा या बहस की परंपरा काफी तेज हो गई है. वास्तव में मोदी सरकार के कुछ सदस्य इस अवधारणा को आगे ले जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम ने वित्त मंत्रालय में चाय पर चर्चा की तर्ज पर नॉर्थ ब्लॉक पॉलिसी चर्चा शुरू कर दी है. यह प्रयास प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने और अर्थशास्त्रियों, बाबुओं एवं शिक्षाविदों को एक साथ लाने के लिए है. पहले सत्र को 1087 बैच के आईएएस अधिकारी एवं विश्व बैंक में भारत की ओर से निदेशक टीवी सोमानाथान संबोधित करेंगे. इस चर्चा के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी माना जा रहा है कि यह मंत्रालय चाय के बहाने नियमित रूप से इस इंटरेक्टिव सेशन को जारी रखना चाहता है. पर्यवेक्षकों के अनुसार, यह कोई नई पहल नहीं है. तीन साल पहले भी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने इसे शुरू किया था, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चला. लेकिन, शायद मोदी के प्रयोग की वजह से चाय पर चर्चा का यह सत्र लंबे समय तक चले. ■

ओडिशा के बाबुओं की नींद उड़ी

भले ही एक नए प्रमुख ने पद संभाल लिया हो, लेकिन उसे जो समस्या विरासत में मिली है, वह पुरानी है. कॉरपोरेट दलाल शुभांकर नायक से केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जब्त कागजात ने नई कहानी शुरू कर दी है. यह ओडिशा में कई नेताओं एवं बाबुओं की नींद उड़ा सकता है. सूत्रों के मुताबिक़, सीबीआई को उन जब्त दस्तावेज़ों में कई नौकरशाहों के नाम मिले हैं, जिनके ख़िलाफ़ जांच हो सकती है. सीबीआई उक्त नामों के बारे में चुप्पी साधे हुए है, लेकिन बाबू हलकों में लगाई जा रही अटकलों के मुताबिक़, दस्तावेज़ों में दो हाई-प्रोफाइल अधिकारियों के नाम हैं, जिनमें एक आईएएस अधिकारी है और दूसरा शीर्ष पुलिस अधिकारी. कई अन्य अधिकारियों के भी नाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही दो नाम सामने आ रहे हैं. माना जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के उक्त अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, वहीं पुलिस अधिकारी राज्य में ही बतौर डीआईजी सेवारत हैं. पर्यवेक्षकों के मुताबिक़, ये तो केवल चंद नाम हैं, आगे जांच में कई और नाम सामने आ सकते हैं. ■

कैडर बंटवारे पर विवाद

तेलंगाना के मुख्य सचिव राजीव शर्मा और आंध्र प्रदेश में उनके समकक्ष कृष्णा राव ने हाल में कैडर बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की. यह मुलाकात प्रत्यूष सिन्हा समिति द्वारा कैडर बंटवारे को लेकर तैयार सूची व आवंटन के संदर्भ में थी. यह सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी. तेलंगाना राज्य का गठन हुए क़रीब छह महीने हो गए हैं, लेकिन इन दो राज्यों के बीच कैडर बंटवारे का मुद्दा विवादास्पद और जटिल बना हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी पैनल द्वारा प्रस्तुत आईएएस, आईपीएस एवं वन सेवा के अधिकारियों की सूची से नाखुश थे. उन्होंने पूछा था कि कैडर बंटवारे के नियमों को बदल क्यों दिया गया. उन्होंने राज्यों से इस बारे में स्पष्टीकरण की मांग की. जाहिर है, अपने गठन के बाद से ही पैनल बार-बार मानदंड बदलता रहा है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी गई पहली सूची को भी इसी तरह अस्वीकार करा दिया गया था. अब फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी. ■

dilipcherian@gmail..com

स्नोडेन ने ही अमेरिकी और ब्रिटिश जासूसी कार्यक्रम का सनसनीखेज ब्यौरा मीडिया को लीक किया था. अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए द्वारा संचालित एक्स की स्कोर जासूसी कार्यक्रम 2008 की एक प्रशिक्षण सामग्री में वह नक्शा भी शामिल था, जिसमें दुनिया भर में लगे सर्वर का ब्यौरा था. उस नक्शे के मुताबिक, उनमें से एक अमेरिकी जासूसी सर्वर भारत की राजधानी नई दिल्ली के किसी समीपवर्ती इलाके में लगा हुआ प्रतीत होता है. समझने वाली बात यह है कि जिन कंपनियों को यूआईडी ने हमारी जानकारियां सुपुर्द की हैं, वे वही कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में निगरानी प्रणाली स्थापित करने में माहिर मानी जाती हैं.

यूआईडी से देश की सुरक्षा को ख़तरा

मनीष कुमार

जितनी भी बायोमैट्रिक जानकारियां हैं, उनकी देखरेख और ऑपरेशन उन कंपनियों के हाथों में है, जिनका रिश्ता ऐसे देशों से है, जो जासूसी कराने के लिए कुख्यात हैं और उन कंपनियों के हाथों में है, जिन्हें विदेशी खुफिया एजेंसियों के रिटायर्ड अधिकारी चलाते हैं. इसका क्या मतलब है? क्या हम जानबूझ कर अमेरिका और विदेशी एजेंसियों के हाथों अपने देश को ख़तरे में डाल रहे हैं? हाल के दिनों में एक खुलासा हुआ था कि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी एनएसए जिन देशों के इंटरनेट और फोन रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है, उनमें पहला नंबर भारत का है. भारत का टेलीफोन और इंटरनेट डाटा इकट्ठा करने के लिए एनएसए ने अपने दो कार्यक्रमों का सहारा लिया है. मजेदार बात यह है कि अमेरिकी सरकार के खुफिया निदेशालय ने भी एक तरह से जासूसी कराने के आरोपों को स्वीकार किया था. निदेशालय ने कहा था कि वह सार्वजनिक तौर पर इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि यह उसकी खुफिया नीति का ही एक हिस्सा है.

समझने वाली बात यह है कि ये कंपनियां कई देशों में सक्रिय हैं. इनके पास वे तमाम तकनीक उपलब्ध हैं, जिससे ये किसी भी देश की इंटरनेट कंपनियों के डाटा एकत्र कर सकती हैं, सर्वर हैक कर सकती हैं, फोन सुन सकती हैं. इन कंपनियों की पहुंच कई देशों में है और ये किस तरह और किस स्तर पर काम कर सकती हैं, इसी का खुलासा स्नोडेन ने किया था.

कांग्रेस सरकार को अमेरिका के इस दुस्साहस, ऐसी निगरानी और जासूसी के ख़िलाफ़ कड़ा विरोध जताना चाहिए था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा. यूपीए सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद विरोध करने की बजाय अमेरिकी हरकत को सही ठहराने के लिए उल्टी-पुल्टी दलीलें देने लग गए. सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह जासूसी नहीं है, यह तो महज कंप्यूटर अध्ययन और कॉलों के पैटर्न का विश्लेषण है. अगर यह जासूसी नहीं है, तो सलमान खुर्शीद को बताना चाहिए कि जासूसी क्या होती है? वैसे अमेरिका के जासूसी प्रकरण पर उसकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (एनएसए) के साथ काम करने वाले एडवर्ड स्नोडेन ने पिछले दिनों कई खुलासे किए. उन्होंने बताया कि आज के इन्फार्मेशन वारफेयर में भारत कई देशों के निशाने पर है. इसलिए भारत के योजना आयोग ने एर्नेस्ट एंड यंग, साफ्रान ग्रुप, एसेंचर, इन-क्यू-टेल एवं मोंगो डीबी जैसी कंपनियों से करार करके देश की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ मजाक किया है. ये कंपनियां उन देशों की हैं, जिनका गठजोड़ पूरी दुनिया पर निगरानी के लिए नेटवर्क तैयार कर रहा है.

स्नोडेन ने ही अमेरिकी और ब्रिटिश जासूसी कार्यक्रम का सनसनीखेज ब्यौरा मीडिया को लीक किया था. अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए द्वारा संचालित एक्स की स्कोर जासूसी कार्यक्रम 2008 की एक प्रशिक्षण सामग्री में वह नक्शा भी शामिल था, जिसमें दुनिया भर में लगे सर्वर का ब्यौरा था. उस नक्शे के मुताबिक, उनमें से एक अमेरिकी जासूसी सर्वर भारत की राजधानी नई दिल्ली के किसी समीपवर्ती इलाके में लगा हुआ प्रतीत होता है. समझने वाली बात यह है कि जिन कंपनियों को यूआईडी ने हमारी जानकारियां सुपुर्द की हैं, वे वही कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में निगरानी प्रणाली स्थापित करने में माहिर मानी जाती हैं. दूसरे विश्व युद्ध के बाद और भारत की आज़ादी से पहले एक नेटवर्क विकसित हुआ था. इसके गठन का एकमात्र उद्देश्य दूसरे देशों की निगरानी करना था. इसमें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए, इंग्लैंड के गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टैब्लिशमेंट, ऑस्ट्रेलिया का सिग्नल डायरेक्टोरेट और न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो आदि शामिल हैं. अब इस गुट में कई और देश भी शामिल हो चुके हैं.

ऐसे माहौल में भारत को स्वयं को सुरक्षित करने के लिए क़दम उठाने चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल उल्टे फ़ैसले लेते हैं. ऐसी क्या वजह है कि सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है? जबकि यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति भी इसका विरोध कर चुकी है. समिति ने विशिष्ट पहचान अंक जैसे ख़ुफ़िया उपकरणों द्वारा नागरिकों पर सतत नज़र रखने और उनके जैवमापक रिकॉर्ड तैयार करने पर आधारित तकनीकी शासन की पुरजोर मुखालफत की और इसे बंद करने का सुझाव दिया. फिर भी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि क्या अब तक एकत्र किए गए बायोमैट्रिक डाटा को प्राधिकरण ने किसी विदेशी कंपनी के साथ शेयर किया या दिया है? अगर ये जानकारियां विदेशी एजेंसियों के हाथ लग चुकी हैं, तो इसका एक मतलब यह है कि हम उनकी निगरानी में आ चुके हैं और दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का कोई मतलब नहीं है, जिसमें उसने कहा कि ये जानकारियां किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं.

समझने वाली बात यह है कि ये कंपनियां कई देशों में सक्रिय हैं. इनके पास वे तमाम तकनीक उपलब्ध हैं, जिससे ये किसी भी देश की इंटरनेट कंपनियों के डाटा एकत्र कर सकती हैं, सर्वर हैक कर सकती हैं, फोन सुन सकती हैं. इन कंपनियों की पहुंच कई देशों में है और ये किस तरह और किस स्तर पर काम कर सकती हैं, इसी का खुलासा स्नोडेन ने किया था. विदेशी एजेंसियों की कारगुजारी और आधार कार्ड योजना की गड़बड़ियां एक ख़तरे को जन्म देती हैं. यह कार्ड ख़तरनाक है, इससे नागरिकों की निजता (प्राइवेसी) का हनन होगा और आम जनता जासूसी की शिकार हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार, सभी एकत्र बायोमैट्रिक जानकारियां सुरक्षित करनी पड़ेंगी. विदेशी कंपनियों के साथ कौन-कौन से खुफिया करार किए गए, उन्हें जनता को बताना पड़ेगा. कितना पैसा बर्बाद हुआ, यह भी जनता को पता चलना चाहिए और उसे वापस लाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई निजी कंपनी का मालिक और मीडिया द्वारा बनाया गया महापुरुष देश की जनता और सरकार को मूर्ख न बना सके. ■

manishbph244@gmail.com

यूआईडी कार्ड नाज़ियों की याद दिलाता है

अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में यूएस होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम है. यहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के नरसंहार से जुड़ी चीजें हैं. इस म्यूजियम में एक मशीन रखी है, जिसका नाम है, होलेरिथ डी-11. इस मशीन को आईबीएम कंपनी ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बनाया था. यह एक पहचान पत्र की छंटाई करने वाली मशीन है. तो सवाल यह उठता है कि इस मशीन का होलोकॉस्ट म्यूजियम में क्या काम? दरअसल, यहूदियों के नरसंहार से इस मशीन का गहरा रिश्ता है. हिटलर ने 1933 में जर्मनी में जनगणना कराई थी. यह जनगणना आईबीएम कंपनी ने की थी. इस कंपनी ने जर्मनी में न सिर्फ़ जनगणना की, बल्कि जातिगत जनगणना की, यहूदियों की गणना की और साथ में एक पहचान पत्र भी दिया था. म्यूजियम में रखी यह मशीन पहचान पत्र को बांचने का काम करती थी. इसी मशीन ने यहूदियों की पहचान की थी, उनका ठिकाना बताया था. अगर यह मशीन न होती, तो नाज़ियों को यहूदियों के नाम-पते की जानकारी न मिलती. नाज़ियों को यहूदियों की सूची आईबीएम कंपनी ने दी थी. आईबीएम और हिटलर के इस गठजोड़ ने इतिहास के सबसे ख़तरनाक जनसंहार को अंजाम दिया. यूआईडी योजना हमें हिटलर और यहूदियों के संहार के उसी भयानक दौर की याद दिलाती है. 1933 और 2014 में एक बड़ा फ़र्क़ भी है. हिटलर के पास तो यहूदियों के घरों के पते थे, लेकिन यूआईडी के मामले में तो कोई छिप भी नहीं सकता. यूआईडी के साथ तो बैंक एकाउंट और मोबाइल फोन भी जोड़ा जा रहा है. ऐसी हालत में किसी का छिपना भी संभव नहीं है. क्या मोदी सरकार या कोई राजनीतिक पार्टी यह बात दावे के साथ कह सकती है कि भारत में यूआईडी का ग़लत इस्तेमाल नहीं होगा? जो हाल यहूदियों का जर्मनी में हुआ, वैसी स्थिति भारत में पैदा हो सकती है, ऐसा ख़तरा हमेशा बना रहेगा. सरकार जिस तरह से इस कार्ड को लागू करना चाहती है, उससे तो किसी भी व्यक्ति का छिपना मुश्किल हो जाएगा. इस कार्ड के लागू होते ही फोन या एटीएम के इस्तेमाल मात्र से किसी का भी ठिकाना पता किया जा सकता है. क्या भारत सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि अगर कभी नाजी या उससे भी ख़तरनाक किस्म के लोग सत्ता में आ गए, तो इस कार्ड का इस्तेमाल दंगा, हिंसा और हत्या के लिए नहीं किया जाएगा? इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता है. क्या यूआईडी या नेशनल पापुलेशन रजिस्ट्रार वही कर रहे हैं, जो जर्मनी में किया गया? सवाल यह भी उठता है कि अगर देश के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ इस तरह के ख़तरनाक सवाल उठा रहे हैं, तो उसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती? इस कार्ड को लेकर संसद में बहस क्यों नहीं हुई? इस कार्ड को बनाने से पहले संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? इस कार्ड को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जिन पर खुली बहस की ज़रूरत है. ■

वह सच, जो छिपा दिया गया

चौथी दुनिया ने पहले भी इस कार्ड को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी, जिससे यह साबित हुआ कि किस तरह यूआईडीएआई ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कार्ड बनाने के लिए तीन कंपनियों को चुना-एसेंचर, महिंद्रा सत्यम-मोर्फो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन. इन तीनों कंपनियों पर ही इस कार्ड से जुड़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं. जब इन तीनों कंपनियों पर ग़ौर करते हैं, तो डर-सा लगता है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन का उदाहरण लेते हैं. इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, जिनका अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैन्य संगठनों से रिश्ता रहा है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से है, जो 25 देशों में फेस डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट आदि जैसी चीजें बेचती है. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सारे काम इसी कंपनी के पास हैं. यह पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक बनाकर देती है. इस कंपनी के डायरेक्टरों के बारे में जानना ज़रूरी है. इसके सीईओ ने 2006 में कहा था कि उन्होंने सीआईए के जॉर्ज टेनेट को कंपनी बोर्ड में शामिल किया है. जॉर्ज टेनेट सीआईए के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने ही इराक के ख़िलाफ़ झूठे सबूत इकट्ठा किए थे कि उसके पास महाविनाश के हथियार हैं. अब कंपनी की वेबसाइट पर उनका नाम नहीं है, लेकिन जिनके नाम हैं, उनमें से किसी का रिश्ता अमेरिका के आर्मी टेक्नोलॉजी साइंस बोर्ड, तो किसी का रिश्ता आर्म्ड फोर्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, आर्मी नेशनल साइंस सेंटर एडवाइजरी बोर्ड और ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जैसे संगठनों से रहा है. इस सवाल का जवाब नंदन नीलेकणी और सरकार को देना चाहिए कि यूआईडी वर्ल्ड बैंक की ई-ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव (ईटीआई) का हिस्सा है या नहीं? यह प्रोजेक्ट 23 अप्रैल, 2010 को वाशिंगटन में शुरू किया गया. सरकार को यह बताना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का मक़सद क्या है, जिसे दुनिया के कई देशों में लागू किया जा रहा है. वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट में एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन, आईबीएम, इनटेल और माइक्रोसॉफ्ट की भी भागीदारी है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन की यह हक़ीक़त सरकार ने जनता से क्यों छिपाकर रखी कि इस कंपनी के बोर्ड में अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी रह चुके हैं. यूआईडी का विरोध सरकार के अंदर से हो रहा है. सरकार के नज़दीकी भी अब इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने लगे हैं. कई सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड न्यायाधीश, अधिकारी, बुद्धिजीवी एवं विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन संसद में इसकी चर्चा तक नहीं हुई और न विपक्ष इस पर कोई दबाव बना रहा है. ■

यूपीए सरकार के दौरान यूनीक आईडेंटिटी कार्ड यानी यूआईडी को लेकर पता नहीं कितने हवाई किले बनाए गए. अख़बारों में, टीवी पर, सेमिनारों में और कई विशिष्ट लोगों के ज़रिए यह समझाया गया था कि यह अब तक का सबसे सटीक पहचान पत्र बनेगा. इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है. संसद में यूआईडी को लेकर बिल लंबित रहा और इधर कार्ड बनने लगे. अब तक छह करोड़ से ज्यादा यूआईडी कार्ड बन चुके हैं. चुनाव के बाद मोदी सरकार आई. मोदी सरकार भी यूपीए सरकार के बनाए रास्ते पर चल पड़ी.

आधार कार्ड पर पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है

संसद में यूआईडी को लेकर बिल लंबित रहा और इधर कार्ड बनने लगे. अब तक छह करोड़ से ज्यादा यूआईडी कार्ड बन चुके हैं. चुनाव के बाद मोदी सरकार आई. मोदी सरकार भी यूपीए सरकार के बनाए रास्ते पर चल पड़ी. ये भी नहीं सोचा कि अगर यूआईडी की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सटीक है तो अब तक क़रीब एक करोड़ कार्ड बेकार कैसे हो गए हैं? किसी में पता गलत है तो किसी में पहचान गलत है. अधिकारी और मीडिया इसे देश की जनता की ही ग़लती बता रहे हैं. जिस देश में 48 फ़ीसदी लोग अनपढ़ हैं, जो स्वयं अपना फॉर्म नहीं भर सकते तो ग़लतियां तो होंगी ही. इस योजना को बनाने वालों को यह पहले से पता होना चाहिए था कि देश की लगभग आधी आबादी अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकती है.

मनीष कुमार

क्या मोदी सरकार को ये पता नहीं है कि आधार कार्ड का कोई क़ानूनी आधार ही नहीं है? यह देश का अकेला ऐसा कार्यक्रम है, जिसे संसद में पेश करने से पहले ही लागू करा दिया गया. असलियत यह है कि यूपीए सरकार इस क़ानून को संसद में पास भी नहीं करा सकी, क्योंकि संसदीय कमेटी ने इस योजना पर ही सवाल खड़ा कर दिया था. संसदीय कमेटी ने कहा, आधार योजना तर्कसंगत नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है. आधार के ख़िलाफ़ केस करने वाले स्वयं कर्नाटक हाईकोर्ट के जज रहे हैं. जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है. इस पिटीशन पर देश के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई जजों ने सहमति दिखाई है.

पहले इतिहास का एक पन्ना पलटते हैं. क़रीब सौ साल पहले मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था. शायद देश के राजनीतिक दलों को यह याद नहीं है कि गांधी ने यह सत्याग्रह क्यों किया? 22 अगस्त, 1906 को दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एशियाटिक लॉ एमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लागू किया. इस क़ानून के तहत ट्रांसवल इलाक़े के सारे भारतीयों को अपनी पहचान साबित करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपने फिंगर प्रिंट देने थे, जिससे हर भारतीय का परिचय पत्र बनना था. इस परिचय पत्र को हमेशा साथ रखने की हिदायत दी गई. न रखने पर सज़ा भी तय कर दी गई. 19वीं शताब्दी तक दुनिया भर की पुलिस चोरों और अपराधियों की पहचान के लिए फिंगर प्रिंट लेती थी. गांधी जी को लगा कि ऐसा क़ानून बनाकर सरकार ने सारे भारतीयों को अपराधियों की श्रेणी में डाल दिया है. गांधी जी ने इसे काला क़ानून बताया. जोहान्सबर्ग में तीन हज़ार भारतीयों को साथ लेकर उन्होंने मार्च किया और शपथ ली कि कोई भी भारतीय इस क़ानून को नहीं मानेगा और अपने फिंगर प्रिंट नहीं देगा. यही महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह की कहानी है. अगर आज गांधी जी होते तो यूआईडी पर सत्याग्रह ज़रूर करते. झूठे वायदे करके, सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर सरकार देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती. मोदी सरकार गांधी जी का नाम तो बहुत जपती है लेकिन उनके आदर्शों के प्रति उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है.

यूआईडी की शुरुआत को लेकर एक हैरतअंगेज बात बताता हूं. देश में एक विशिष्ट पहचान पत्र के लिए विप्रो नामक कंपनी ने एक दस्तावेज तैयार किया. इसे प्लानिंग कमीशन के पास जमा किया गया. इस दस्तावेज का नाम है स्ट्रेटजिक विजन ऑन द यूआईडीएआई प्रोजेक्ट. मतलब यह कि यूआईडी की सारी दलीलें, योजना और उसका दर्शन इस दस्तावेज में है. बताया जाता है कि यह दस्तावेज अब ग़ायब हो गया है. विप्रो ने यूआईडी की ज़रूरत को लेकर 15 पेज का एक और दस्तावेज तैयार किया, जिसका शीर्षक है, डज इंडिया नीड ए यूनीक आइडेंटिटी नंबर. इस दस्तावेज में यूआईडी की ज़रूरत को समझाने के लिए विप्रो ने ब्रिटेन का उदाहरण दिया. इस प्रोजेक्ट को इसी दलील पर हरी झंडी दी गई थी. हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने अपनी योजना को बंद कर दिया. उसने यह दलील दी कि यह कार्ड खतरनाक है, इससे नागरिकों की प्राइवेसी का हनन होगा और आम जनता जासूसी की शिकार हो सकती है. अब सवाल यह उठता है कि जब इस योजना की पृष्ठभूमि ही आधारहीन और दर्शनविहीन हो गई तो फिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह इसे लागू करने के लिए सारे नियम-क़ानूनों और विरोधों को दरकिनार करने पर आमादा है. क्या इसकी वजह नंदन नीलेकणी हैं, जो यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री के करीबी और यूआईडीएआई के चेयरमैन थे. क्या यह विदेशी ताक़तों और मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पर किया जा रहा है? देश की जनता को इन तमाम सवालों के जवाब जानने का हक़ है, क्योंकि यह काम जनता के हज़ारो करोड़ रुपये से किया जा रहा है, जिसे सरकार के ही अधिकारी अविश्वसनीय, अप्रमाणिक और दोहराव बता रहे हैं.

पहले यूपीए और अब मोदी सरकार वही गलतियां कर रही है जिसके बारे में दुनिया की तमाम एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं. क्या सुरक्षा एजेंसियों को अब तक ये मालूम नहीं है कि इस योजना के तहत ऐसे लोग भी पहचान पत्र हासिल कर सकते हैं, जिनका इतिहास दाग़दार रहा है. एक अंग्रेजी अख़बार ने विकीलीक्स के हवाले से अमेरिका के एक केबल के बारे में ज़िक्र करते हुए यह लिखा कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन के आतंकवादी इस योजना का दुरुपयोग कर सकते हैं. कुछ कश्मीरी आंतकियों के पास से यूआईडी बरामद भी किए गए हैं. फिर भी किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही है. अजीब स्थिति है. अब पता नहीं नंदन नेलकणी ने पहले मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी को कौन पट्टी पढ़ाई है कि दोनों ही प्रधानमंत्री यूआईडी के दीवाने बन गए.

यूआईडीएआई ने न सिर्फ़ प्राइवेसी को ही नज़रअंदाज़ किया है, बल्कि उसने अपने पायलट प्रोजेक्ट के रिजल्ट को भी नज़रअंदाज़ कर दिया है. इतनी बड़ी आबादी के लिए इस तरह का कार्ड बनाना एक सपने जैसा है. अब जबकि दुनिया के किसी भी देश में बायोमेट्रिक्स का ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो भी होगा, वह प्रयोग ही होगा. यूआईडीएआई के पायलट प्रोजेक्ट के बारे में एक रिपोर्ट आई है, जो बताती है कि सरकार इतनी हड़बड़ी में है कि उसने पायलट प्रोजेक्ट के सारे मापदंडों को दरकिनार कर दिया. मार्च और जून 2010 के बीच 20 हज़ार लोगों के डाटा पर काम हुआ. अथॉरिटी ने बताया कि फाल्स पोजिटिव आईडेंटिफिकेशन रेट 0.0025 फीसदी है. फाल्स पोजिटिव आईडेंटिफिकेशन रेट का मतलब यह है कि इसकी कितनी आशंका है कि यह मशीन एक व्यक्ति की पहचान किसी दूसरे व्यक्ति से करे. मतलब यह कि सही पहचान न बता सके. अथॉरिटी के डाटा के मुताबिक़ तो हर 15,000 कार्ड के बाद एक कार्ड में गड़बड़ी निकलेगी. समस्या यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बायोमेट्रिक पहचान की किसी देश ने कोशिश नहीं की. कोरिया के सियोल शहर में टैक्सी ड्राइवरों के लिए ऐसा ही लाइसेंस कार्ड बना, जिसे टोल टैक्स एवं पार्किंग वगैरह में प्रयोग किया गया. एक साल के अंदर ही पता चला कि 5 से 13 फीसदी ड्राइवर इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. नतीजा यह निकला कि ऐसा सिस्टम लागू करने के कुछ समय बाद हर व्यक्ति को इस परेशानी से गुज़रना पड़ता है और एक ही व्यक्ति को बार-बार कार्ड बनवाने की ज़रूरत पड़ती है. सच्चाई यह है कि इस तरह के कार्ड के लिए हमारे पास न तो फुलप्रूफ टेक्नोलॉजी है और न अनुकूल स्थितियां. 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है और न इंटरनेट की व्यवस्था है पूरे देश में. ऐसे में अगर इस कार्ड को पढ़ने वाली मशीनों में गड़बड़ियां आएंगी तो वे कैसे वक्त पर ठीक होंगी? प्रधानमंत्री और सरकार की ओर से दलील दी जा रही है कि यूआईडी से पीडीएस सिस्टम दुरुस्त होगा, ग़रीबों को फायदा पहुंचेगा.

यूपीए सरकार के दौरान यूनीक आईडेंटिटी कार्ड यानी यूआईडी को लेकर पता नहीं कितने हवाई किले बनाए गए. अख़बारों में, टीवी पर, सेमिनारों में और कई विशिष्ट लोगों के ज़रिए यह समझाया गया था कि यह अब तक का सबसे सटीक पहचान पत्र बनेगा. इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है. संसद में यूआईडी को लेकर बिल लंबित रहा और इधर कार्ड बनने लगे. अब तक छह करोड़ से ज्यादा यूआईडी कार्ड बन चुके हैं. चुनाव के बाद मोदी सरकार आई. मोदी सरकार भी यूपीए सरकार के बनाए रास्ते पर चल पड़ी. ये भी नहीं सोचा कि अगर यूआईडी की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सटीक है तो अब तक क़रीब एक करोड़ कार्ड बेकार कैसे हो गए हैं? किसी में पता गलत है तो किसी में पहचान गलत है. अधिकारी और मीडिया इसे देश की जनता की ही ग़लती बता रहे हैं. जिस देश में 48 फ़ीसदी लोग अनपढ़ हैं, जो स्वयं अपना फॉर्म नहीं भर सकते तो ग़लतियां तो होंगी ही. इस योजना को बनाने वालों को यह पहले से पता होना चाहिए था कि देश की लगभग आधी आबादी अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकती है. यही वजह है कि यूआईडीएआई को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि यूआईडी नंबर के लिए ग़लत पता लिखा है. इस घटना से दूसरा सवाल उठता है. क्या कोई ग़लत पते भर कर यूआईडी बना सकता है. अगर बना सकता है तो भविष्य में भी ग़लत पते पर यूआईडी बनते रहेंगे. सवाल कार्ड बनाने वाले अधिकारियों और यूआईडीएआई के नंदन नीलकेणी से पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है. समस्या सिर्फ़ यही नहीं है. दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में कुछ बुजुर्ग यूआईडी बनवाने पहुंचे. उन्होंने हाथों को जब मशीन पर रखा तो मशीन ने उनके हाथों की रेखाओं को पढ़ने से इंकार कर दिया. पता चला कि 65 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों के सूखे हाथों की रेखाओं को मशीन पढ़ ही नहीं सकती. नंदन नीलेकणी साहब इस कार्ड की टेक्नोलॉजी के बारे में कई बार व्याख्यान कर चुके हैं. यह कितनी सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया जा रहा है, अख़बारों में इसके बारे में कसीदे हर दिन छपते हैं. हक़ीक़त यह है कि यूआईडी बनवाने की हसरत रखने वाले बुजुर्ग बड़ी संख्या में उदास होकर लौट रहे हैं. ■

manishbph244@gmail.com

यूआईडी ने देशवासियों को कैदी बना दिया.

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश के किस क़ानून के आधार पर लोगों के बायोमैट्रिक्स को एकत्र किया जा रहा है? देश में मौजूद सारे क़ानून खंगालने के बाद पता चलता है कि ऐसा क़ानून सिर्फ़ जेल मैन्युअल में है. ऐसा सिर्फ़ क़ैदियों के साथ किया जा सकता है और इसमें भी एक शर्त है कि जिस दिन वह क़ैदी रिहा होगा, उसके बायोमैट्रिक्स से जुड़ी फाइलें जला दी जाएंगी, लेकिन इस योजना के तहत सरकार लोगों की सारी जानकारियां एकत्र कर रही है और विदेश भेजने पर तुली है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दे दिया है कि प्राधिकरण लोगों के बायोमेट्रिक डाटा किसी को नहीं दे सकता है. यह जनता की अमानत है और इसे दूसरी एजेंसियों के साथ शेयर करना मौलिक अधिकारों का हनन है. अब यहां एक टेक्निकल सवाल उठता है. प्राधिकरण ने तो लोगों की सारी बायोमेट्रिक जानकारियां सिर्फ़ शेयर नहीं की हैं, बल्कि उन्हें विदेशी कंपनियों के सुपुर्द कर दिया है.

आधार की विशिष्टता काल्पनिक है

चौथी दुनिया साप्ताहिक अख़बार ने सबसे पहले आधार कार्ड से होने वाले ख़तरों का खुलासा किया था. हमने यह खुलासा किया था कि किस तरह आधार कार्ड सीआईए और अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों के पास हमारी और आपकी सारी जानकारी पहुंचाने की साजिश है. समय के साथ-साथ चौथी दुनिया की सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग रही है. सूचना का अधिकार क़ानून के तहत निकली एक जानकारी के मुताबिक, यह बताया गया है कि बायोमीट्रिक सिस्टम 100 फ़ीसद एक्यूरेट नहीं है और दूसरी बात यह कि आधार कार्ड की विशिष्टता भी काल्पनिक है. यह जानकारी योजना आयोग के साथ करार करने वाली एर्नेस्ट एंड यंग प्राइवेट लिमिटेड और नेटमैजिक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दी है. इस सूचना के साथ ही आधार कार्ड का आधार ख़त्म हो जाता है. इस कार्ड को लेकर नंदन नीलेकणी ने जो बड़े-बड़े दावे किए थे, वे सब झूठे साबित हुए हैं. नंदन नीलेकणी ने इस योजना की शुरुआत में दावा किया था कि यह अब तक का सबसे सटीक व अति विशिष्ट कार्ड है और इसकी नकल नहीं की जा सकती. नंदन नीलेकणी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने देश को गुमराह क्यों किया? केंद्र सरकार ने जब आधार कार्ड की योजना लॉन्च की, तो उसकी शान में जमकर कसीदे काढ़े गए थे. बड़े-बड़े दावे हुए कि आधार कार्ड बनने के बाद लोगों को तरह-तरह के पहचान पत्र दिखाने के झंझट से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन यूपीए सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में धांधली चरम पर है. चंद रुपये खर्च करके कोई भी आधार कार्ड बनवा सकता है. हाल में एक साइट के स्टिंग ऑपरेशन के जरिये यह खुलासा हुआ है कि अवैध बांग्लादेशी चंद रुपये देकर आसानी से आधार कार्ड बनवा लेते हैं और भारत के मान्यता प्राप्त नागरिक बन जाते हैं और फिर मतदान में हिस्सा लेने के लिए वैध हो जाते हैं. जबकि यूपीए सरकार के मंत्री और इस प्रोजेक्ट के सर्वेसर्वा नंदन नीलेकणी ने भरोसा दिलाया था कि कोई भी अवैध प्रवासी हमारे देश का फर्जी पहचान पत्र नहीं बनवा पाएगा और न उसका कोई डुप्लीकेट बन सकता है. अब आधार कार्ड का तकनीकी और क़ानूनी आधार ही सवालों के घेरे में है. इससे जुड़ी संस्थाओं ने तकनीकी खामियां मानकर उन सारे दावों की पोल खोल दी, जो नंदन नीलेकणी ने अब तक बेचते आए हैं. इस खुलासे के बाद सरकार और प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो गया है.

नोएडा में सबसे ज़्यादा घोटाला प्लॉट आवंटन में किया गया. प्लॉट आवंटन में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी मुलायम और मायावती के कार्यकाल में हुई. नियमों को ताक पर रखकर अनाप-शनाप तरीके से आवासीय एवं व्यवसायिक प्लॉट आवंटित कर दिए गए. इसमें अफसरों एवं नेताओं ने करोड़ों-अरबों रुपये कमाए. 1994 में नोएडा में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी करने के आरोप में तत्कालीन सीईओ नीरा यादव और डिप्टी सीईओ राजीव कुमार को सीबीआई की अदालत ने 2012 में तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी.

नेताओं, नौकरशाहों और दलालों के गठजोड़ की उपज है यादव सिंह

उत्तर प्रदेश बना भ्रष्टाचार की लंका

प्रभात रंजन दीन

यादव सिंह के अड्डों पर हुई तलाशी के दो-चार दिनों पहले एक प्रख्यात कॉरपोरेट प्रतिष्ठान के नोएडा एवं दिल्ली स्थित ठिकानों पर आयकर और प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों ने छापा मारकर सैकड़ों करोड़ रुपये नकद व महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बरामद किए थे. बरामद की गई नकदी और दस्तावेज़ों के लिंक यादव सिंह से मिले और फौरन यादव सिंह को दबोच लिया गया. पैसे कमाने वाले और पैसे खपाने वाले मिले हुए हैं. नेता, अफसर और दलाल मिलकर देश का धन लूट रहे हैं और व्यवसायिक प्रतिष्ठान उस धन को खपाने का ज़रिया बने हुए हैं. कौन हटा देगा इस देश से भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार हटाने के लिए नेता, नौकरशाह, दलाल और पूंजीपशुओं की जकड़न तोड़नी होगी. कौन तोड़ेगा इसे? यह सवाल देश के आम आदमी का है.

यादव सिंह प्रकरण उजागर हुआ और पूरे देश ने जाना कि भ्रष्टाचार किस कदर हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार मासूम बनी रही. नोएडा के भ्रष्ट इंजीनियर यादव सिंह को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निलंबित करना ज़रूरी नहीं समझा, जबकि अब तक उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी. ख़बर लिखे जाने तक न तो उसका निलंबन हुआ था और न गिरफ्तारी. सरकार की मौलिक कार्यप्रणाली यही है, बाकी सब धोखेबाजी है. आयकर विभाग के छापों में अरबों की काली कमाई पकड़े जाने के बावजूद राज्य सरकार भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं करती. पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव रही हों या अखंड प्रताप सिंह या मौजूदा भ्रष्ट नौकरशाहों की जमात, सपा सरकार ऐसे ही लोगों को संरक्षण देती रही है. बसपा ने भी ऐसे ही कीर्तिमान बनाए हैं. यादव सिंह तो भ्रष्टाचारी तंत्र का एक पुर्जा है, जिसे बसपा सरकार ने पाला-पोसा और सपा सरकार ने निलंबन का करंट लगाकर उसे साधा और फिर काम पर लगा दिया. प्रदेश में बसपा की सरकार रही हो या सपा की, यादव सिंह ने अपनी पसंद के मुताबिक अपनी तैनातियां कराईं. यह भी कह सकते हैं कि व्यवस्था ने अपनी सुविधा के मुताबिक यादव जैसे खटमल को धन रिसने वाली जगहों पर तैनात किया. इसीलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण कामों पर यादव सिंह का एकाधिकार था. सपा सरकार ने कुछ दिनों के लिए भृकुटी तानी, लेकिन जब यादव ने तनी भृकुटी का आशय समझ लिया, तो सब ठीक हो गया.

सपा के एक वरिष्ठ नेता की सक्रिय पहल पर यादव सिंह को 17 माह में ही बहाल कर दिया गया. निलंबन के बाद उसे पहले नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा और फिर यमुना एक्सप्रेस-वे जैसी तीन महत्वपूर्ण अथॉरिटी का मुख्य अभियंता बना दिया गया. एनसीआर क्षेत्र की ये तीनों सबसे प्राइम पोस्टिंग मानी जाती हैं, जिन पर वह अकेले पद-स्थापित था. उल्लेखनीय है कि सत्ता में आते ही सपा सरकार ने यादव सिंह पर विभागीय जांच बैठाकर उसे निलंबित कर दिया था. उस पर नोएडा के सेक्टर-39 थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था और सीबीसीआईडी जांच भी कराई गई थी, लेकिन नवंबर 2013 में यादव सिंह का निलंबन अचानक वापस हो गया. सीबीसीआईडी जांच भी समाप्त हो गई. सीबीसीआईडी ने यादव सिंह पर लगे आरोप सत्य से परे पाए और जांच बंद कर दी. व्यवस्था का सत्य यही है. सिस्टम इस कदर सड़ा हुआ है कि योग्यता एवं ईमानदारी उपेक्षा का शिकार है और जूनियर इंजीनियर पद से नौकरी शुरू करने वाला एक भ्रष्ट शख्स मुख्य अभियंता जैसे शीर्ष पद पर पहुंच जाता है. औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तो उसने खुद इंजीनियर इन चीफ का पद सृजित कराया और उस पर आसीन हो गया. नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दोनों ही उसके मातहत कर दी गईं. उसके बाद दोनों अथॉरिटी से जितने भी काम दिए गए, सभी यादव सिंह के इशारे पर दिए गए.

लोग कहते हैं कि यादव सिंह के कारनामे उजागर होने के बाद सफेदपोशों के नाम भी उजागर होंगे, लेकिन यह केवल कहने-सुनने की बातें हैं. असलियत यही है कि सफेदपोशों (असली) के नाम कभी उजागर नहीं होंगे. सपा सरकार में यादव सिंह की तैनाती करोड़ों रुपये के चंदे के बूते हुई. अब इसे चंदा कहें या रिश्वत. भ्रष्टाचार विधा के कलाकार यादव सिंह की तैनाती इतनी ज़रूरी थी कि उसके लिए नौकरशाहों, इंजीनियरों एवं ठेकेदारों ने करोड़ों रुपये का चंदा इकट्ठा किया था. चंदे का पूरा ब्यौरा दिल्ली के पंजाब नेशनल बैंक के एक लॉकर से मिला है. दिल्ली, गाज़ियाबाद और नोएडा से ही उसके दर्जनों लॉकर सील किए गए हैं. एक लॉकर से 40 कंपनियों के दस्तावेज़ भी मिले हैं. वे कंपनियां कौन हैं और उनका यादव सिंह के काले धन से क्या लेन-देन था, इसका गहराई से खुलासा शायद ही कभी हो पाए. इन्हीं कंपनियों में से किसी एक के निदेशक से एक डायरी भी जब्त की गई, जिसमें तमाम देनदारों-लेनदारों के नाम-नंबर दर्ज हैं, लेकिन इसका भी खुलासा न अभी हुआ है और न कभी होगा. 40 कंपनियों में से केवल चार के निदेशकों का नाम सार्वजनिक किया गया, जो मामूली थे, जिनके उजागर होने से सिस्टम पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता.

नोएडा में सबसे ज़्यादा घोटाला प्लॉट आवंटन में किया गया. प्लॉट आवंटन में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी मुलायम और मायावती के कार्यकाल में हुई. नियमों को ताक पर रखकर अनाप-शनाप तरीके से आवासीय एवं व्यवसायिक प्लॉट आवंटित कर दिए गए. इसमें अफसरों एवं नेताओं ने करोड़ों-अरबों रुपये कमाए. 1994 में नोएडा में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी करने के आरोप में तत्कालीन सीईओ नीरा यादव और डिप्टी सीईओ राजीव कुमार को सीबीआई की अदालत ने 2012 में तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी. उन्हीं नीरा यादव को मुलायम की सरकार में मुख्य सचिव बनाया गया था. नीरा यादव तो रिटायर हो चुकीं, लेकिन वही स्वनामधन्य राजीव कुमार अखिलेश सरकार में प्रमुख सचिव की हैसियत से ताकतवर नौकरशाह के रूप में पद-स्थापित हैं. घोटालों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सरकारें नाकाम इसलिए रही हैं, क्योंकि वे स्वयं इनमें शामिल रही हैं. उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ. इसी वजह से प्रदेश की जांच एजेंसियों ने अपना औचित्य खो दिया, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं रही. आएदिन करोड़ों-अरबों रुपये के घोटाले सामने आते हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहता है. पुलिस ने अपनी प्रासंगिकता खो दी और सीबीसीआईडी जैसी जांच एजेंसियों की छवि घपलों-घोटालों को क्लीन चिट देने वाली संस्था की होकर रह गई है. लोकायुक्त संगठन ने अपना थोड़ा वजूद बनाया भी, तो अखिलेश सरकार ने उसे भोथरा कर दिया. राज्य के भ्रष्ट नेताओं एवं नौकरशाहों की फेहरिस्त लंबी-चौड़ी और मोटी होती जा रही है, क्योंकि कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है.

ऊर्जा घोटाला, पत्थर घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, मनरेगा घोटाला, मिड-डे मील घोटाला, नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाला, लैकफेड घोटाला, आयुर्वेद घोटाला, ताज कॉरीडोर घोटाला, खनन घोटाला, आय से अधिक संपत्ति घोटाला, खाद्यान्न घोटाला आदि में एक-दो गिरफ्तारियां छोड़कर क्या हुआ! सरकार ने प्रदीप शुक्ला जैसे भ्रष्ट नौकरशाह को जेल से छुड़वा लिया. बाबू सिंह कुशवाहा पर सपा सरकार ने कृपा दृष्टि नहीं हुई, इसीलिए वह जेल में हैं. बसपा के कार्यकाल में मायावती ने सपा के कार्यकाल के घोटालों पर आंखें मूंद ली थीं, तो सपा सरकार ने बसपा के कार्यकाल के घोटालों पर आंखें मूंद लीं. नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में आईएएस राजीव कुमार को सीबीआई अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी, हाईकोर्ट के आदेश से सजा स्थगित है, लेकिन अखिलेश सरकार की उन पर खास कृपा है. आईएएस संजीव शरण पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रहते हुए होटलों के लिए जमीन आवंटन में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप हैं. आईएएस राकेश बहादुर पर भी अरबों रुपये के नोएडा ज़मीन घोटाले में आरोप लगे थे. मायावती सरकार ने राकेश बहादुर को निलंबित कर दिया था, लेकिन अखिलेश सरकार ने उनका ओहदा बढ़ा दिया. आईएएस सदाकांत, ललित वर्मा एवं के धनलक्ष्मी के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन वे सपा सरकार के खास हैं.

मायावती सरकार के समय हुए यूपी लेबर एंड कंस्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड (लैकफेड) घोटाले में तत्कालीन मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके निजी सचिव सीएल वर्मा का नाम आया, लेकिन उनका क्या हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के चीफ इंजीनियर रहे अरुण कुमार मिश्र द्वारा किए गए सबसे बड़े ट्रॉनिका सिटी घोटाले में क्या हुआ? 1400 करोड़ रुपये का घोटाला करने वाले ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के निदेशक एवं मुख्य अभियंता बने उमा शंकर का क्या हुआ? यादव सिंह की तरह उमाशंकर पर भी न केवल बसपा सरकार की कृपा बरसती थी, बल्कि मौजूदा सपा सरकार में भी कृपा बरस रही है. 2009 से मार्च 2012 तक छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को पीडब्ल्यूडी ने छह अरब सात करोड़ 51 लाख रुपये के काम आवंटित किए. सिर्फ़ सोनभद्र में ही 145 करोड़ रुपये के कार्य आवंटित हुए. अखिलेश सरकार में भी उमाशंकर की कंपनी को तीन अरब सात करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक के कार्यों का अनुबंध किया गया. लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए गए राजकीय निर्माण विभाग के पूर्व प्रबंध निदेशक सीपी सिंह का क्या हुआ? अरबों रुपये का घोटाला करने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अवैध कमाई के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) भी कुख्यात है. एलडीए के अफसरों से लेकर इंजीनियर तक अकूत संपत्ति के मालिक हैं. भ्रष्टाचार के बोलबाले के कारण पिछले कई महीनों से एलडीए में कोई उपाध्यक्ष और सचिव नहीं है. अकूत धन का स्रोत-स्थल होने के कारण मंत्रियों और सपा के एक शीर्ष नेता की आपस में ठनी हुई है. मंत्री चाहते हैं, उनका आदमी तैनात हो, तो नेता चाहते हैं कि उनका आदमी. उपाध्यक्ष को हटाने और तैनात कराने की हैसियत रखने वाले एलडीए सचिव अष्टभुजा तिवारी तबादले पर जा चुके हैं, लेकिन पद खाली पड़ा है, इसी प्रत्याशा में कि अष्टभुजा उसी पद पर फिर सवार होंगे. प्रदेश में सैकड़ों भ्रष्ट इंजीनियरों के ख़िलाफ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच चल रही है, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं होती. क़रीब सौ से अधिक नौकरशाहों के ख़िलाफ़ विजिलेंस शाखा जांच कर रही है. तक़रीबन दो दर्जन अफसरों के ख़िलाफ़ जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ न तो मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मिलती है और न कार्रवाई आगे बढ़ती है. इसी में अफसर रिटायर होकर जाते भी रहते हैं. आईएएस तुलसी गौड़ हों या केके त्रिपाठी, ये सब रिटायर हो चुके हैं. जिन अफसरों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की मंजूरी की फाइल सत्ता के गलियारे में खोई हुई है, उनमें तुलसी गौड़, केके त्रिपाठी, आईएफएस नीरज कुमार, डीपी गुप्ता, पीपीएस श्याम लाल, राहुल मिठास, पीसीएस शंकर लाल पांडेय, आरएम दयाल, लालमणि पांडेय, सुरेश चंद्र गुप्ता के नाम शामिल हैं. मायावती के कार्यकाल में हुए स्मारक घोटाला मामले में भी आईएएस हरभजन सिंह, रवींद्र सिंह एवं मोहिंदर सिंह विजिलेंस जांच के दायरे में हैं. हरभजन एवं मोहिंदर सिंह रिटायर भी हो चुके हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार के सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) में जांच के मामले ठंडे बस्ते में डालने के लिए ही भेजे जाते हैं. विजिलेंस शाखा अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को भेज देती है और सरकार उस पर बैठ जाती है. इसके पहले भी विजिलेंस शाखा आईएएस आरए प्रसाद, पीएन मिश्रा, सीएन दुबे, गुरुदीप सिंह, एमके गुप्ता, सत्यजीत ठाकुर, गिरिराज वर्मा, आरके सिंह, बृजेंद्र यादव, सुनंदा प्रसाद, वीके वार्ष्णेय, ललित वर्मा, डीएस यादव, एके उपाध्याय, आरके भटनागर एवं एके टंडन जैसे वरिष्ठ नौकरशाहों के ख़िलाफ़ जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है, लेकिन कार्रवाई ढाक के तीन पात ही रही. पूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त एवं मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह के ख़िलाफ़ भी सरकार ने विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी और फिर अपना ही आदेश वापस ले लिया था. सपा ने सत्ता में आने के लिए भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाया था, पर अपनी सरकार बनने के बाद उसने धारा बदल दी. शराब माफिया रहे पोंटी चड्ढा (जिसकी बाद में हत्या हो गई) का नाम पंजीरी घोटाले में भी आया था. शराब घोटाले में भी वह शामिल था. सपा उसे सबक सिखाने का ऐलान करती थी, पर सत्ता में आते ही शराब की लॉटरी फिर उसी माफिया की फर्म के नाम खुल गई. पोंटी चड्ढा को मायावती का भी वरदहस्त हासिल था. अब उसकी कंपनी को न केवल सत्ताधारी दल का संरक्षण मिल रहा है, बल्कि बाकायदा सत्ताधारी दल का एक कद्दावर व्यक्ति पार्टनर के रूप में भी मिल गया है.

बहरहाल, यादव सिंह पर छापे की कार्रवाई के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पिछली सरकार के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स और ज़मीन आवंटनों की दोबारा जांच का रास्ता खुला है. बसपा शासनकाल में बड़े पैमाने पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के ज़रिये बिल्डरों को ज़मीन दी गई थी. नोएडा फेज तीन और एक्सप्रेस-वे पर कई नामी बिल्डरों को ज़मीन आवंटित हुई थी और मात्र 10 फ़ीसद रकम लेकर भूखंड दे दिए गए थे. क़रीब 12 हज़ार करोड़ रुपये का केवल बकाया सामने आ रहा है, घोटाले की अरबों की रकम इसके अलावा है. नोएडा फार्म हाउस आवंटन को लोकायुक्त की तरफ़ से हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन यादव सिंह प्रकरण सामने आने के बाद फार्म आवंटन घोटाला एक बार फिर ताजा हो गया है. 2009-10 में 155 फार्म हाउस आवंटन योजना आई थी. मायावती सरकार के कार्यकाल में नोएडा अथॉरिटी ने सरकार के क़रीबी व्यवसायिक घरानों, बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों को कौड़ियों के दाम पर फार्म हाउस दे दिए थे. अथॉरिटी ने 129 कंपनियों और 29 लोगों को सस्ते दामों पर प्लॉट दिए थे. प्लॉट पाने वालों में मायावती के क़रीबी शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उसकी पत्नी का नाम भी शामिल है. बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश दास की पत्नी अलका दास को भी एक भूखंड दिया गया था. मायावती के क़रीबी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को और उनके बेटे की कंपनियों के नाम पर भी कई भूखंड दिए गए थे. एक ही परिवार के 11 लोगों को सस्ते दामों पर फार्म हाउस मुहैया कराए गए थे. ऐसी कई कंपनियों को फार्म हाउस आवंटित कर दिए गए थे, जिनका रजिस्ट्रेशन आवंटन के बाद हुआ. एक ही कंपनी को कई-कई प्लॉट दे दिए गए. ■

मायावती और सपा का क़रीबी

यादव सिंह एक जाति के होने के सहारे मायावती का क़रीबी बना था और अवैध धन कमाने के हुनर के चलते वह समाजवादी पार्टी का भी क़रीबी बन गया. उसे सत्ता के क़रीब लाने में एक सजातीय आईएएस अफसर की बड़ी भूमिका थी. खूबी यह कि मायावती के खास रहे यह आईएएस अफसर आज अखिलेश के भी खास हैं. धन का ही प्रभाव है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह ने अपना ज़्यादातर करियर इंजीनियरिंग की डिग्री के बगैर ही काट लिया, लेकिन उसे प्रमोशन पर प्रमोशन दिए जाने में कोई अड़चन नहीं आई. 1980 में यादव सिंह ने नोएडा अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया. 1995 में उसे प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर तरक्की दे दी गई, जबकि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए बीटेक होना ज़रूरी होता है. जाटव यादव सिंह को मायावती ने 2011 में नोएडा अथॉरिटी का इंजीनियर इन चीफ बना दिया. 2012 में सपा सत्ता में आई, तो यादव सिंह को 954 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में निलंबित कर दिया गया, लेकिन 2012 में फिर बहाल कर दिया गया. फिर सपा सरकार ने प्रभावित होकर यादव सिंह को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे, तीनों प्राधिकरणों का चीफ इंजीनियर बना दिया. करोड़ों की अवैध संपत्ति बचाने या छिपाने के लिए यादव सिंह ने सारी दौलत अपनी पत्नी के नाम कर दी थी और कागजी तौर पर तलाक ले रखा था. तलाक के बावजूद वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा था. ■

अब बने भ्रष्ट अफसरों को बर्खास्त करने का क़ानून

भ्रष्ट अधिकारियों को फौरन बर्खास्त करने का क़ानून बनाने का प्रस्ताव संसद के गलियारे में खो गया है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जब अन्ना का आंदोलन परवान पर था, तब तत्कालीन केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित अधिकारियों को बर्खास्त करने का क़ानून बनाने का प्रस्ताव लाई थी. इसके लिए बाकायदा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने संविधान के अनुच्छेद-311 में आवश्यक संशोधन का सुझाव दिया था. लेकिन, सरकार समिति की सिफारिशों का अध्ययन ही करती रह गई और संसद में पेश करना भूल गई. तत्कालीन यूपीए सरकार के नेता घोटालों में इतने मशरूफ थे कि प्रस्ताव पेश करने की उन्हें फुर्सत नहीं मिली और सरकार चली भी गई. अब मौजूदा सरकार का दायित्व है कि वह उस प्रस्ताव को सदन में लाए और क़ानून बनाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

> दिल्ली के लगभग एक करोड़ 20 लाख मतदाताओं में 11 फ़ीसद मतदाता मुस्लिम हैं. लिहाजा हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी सभी राजनीतिक दल मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा ने इसके लिए बीते 11 नवंबर से दिल्ली में एक बड़ी मुहिम शुरू की है. पार्टी का फोकस विशेष रूप से ओखला, चांदनी चौक, सीलमपुर, जाफ़राबाद और नागलोई जैसे क्षेत्रों पर है, जहां मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं. भाजपा नेता–कार्यकर्ता मुसलमानों के घर–घर जाकर उनसे पार्टी में शामिल होने की अपील कर रहे हैं. साथ ही उन्हें समझा रहे हैं कि मोदी केवल हिंदुओं के नहीं, बल्कि सभी भारतीयों के नेता हैं.

दिल्ली

विधानसभा चुनाव और मुसलमान

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इन तैयारियों के बीच, सभी राजनीतिक दलों की नज़र मुस्लिम वोटों पर भी है. भाजपा जहां एक ओर मुसलमानों के घर–घर जाकर उन्हें पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मुसलमानों के अधिकतर वोट उसे मिलने जा रहे हैं. लेकिन, दिल्ली में 11 फ़ीसद हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिम मतदाताओं के मन में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, यह जानने के लिए चौथी दुनिया टीम ने विभिन्न इलाकों में दौरा कर लोगों से बातचीत की. पेश है, उसी पर आधारित यह रिपोर्ट...

डॉ. क़मर तबरेज़

दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ़ हो चुका है और कुछ ही दिनों में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा भी हो सकती है. इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. अगली सरकार किसकी होगी, इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है. पिछली बार दिसंबर 2013 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे, तो यहां अरविंद केजरीवाल का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन इस बार मोदी की जय–जयकार हो रही है. कांग्रेस न तो तब कहीं मुकाबले में थी और न अब है. इसलिए आम लोगों में बात सिर्फ़ दो ही दलों की हो रही है यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी. कुछ लोग यह मान रहे हैं कि पिछली बार तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल हो गई थी, लेकिन इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. हालांकि, यह भी सच्चाई है कि पिछली बार जब पूरी दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल का बुखार चढ़ा हुआ था, उस समय भी चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था और सरकार बनाने के लिए उसे कांग्रेस का समर्थन लेना पड़ा था. इसलिए पूरे विश्वास से यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस समय जब पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, तो भाजपा दिल्ली में अगली सरकार बनाने में सफल हो ही जाएगी. अगर पिछले चुनाव की बात करें, तो 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 4 दिसंबर, 2013 को हुए मतदान में भाजपा को 31, आप को 28 और कांग्रेस को केवल 8 सीटें मिली थीं. इस प्रकार कोई भी पार्टी बहुमत लाने में असफल रही थी. कांग्रेस से समर्थन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल तो हो गई थी, लेकिन 49 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल देश को जीतने के चक्कर में दिल्ली छोड़कर भाग गए थे.

दिल्ली के लगभग एक करोड़ 20 लाख मतदाताओं में 11 फ़ीसद मतदाता मुस्लिम हैं. लिहाजा हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी सभी राजनीतिक दल मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा ने इसके लिए बीते 11 नवंबर से दिल्ली में एक बड़ी मुहिम शुरू की है. पार्टी का फोकस विशेष रूप से ओखला, चांदनी चौक, सीलमपुर, जाफ़राबाद और नागलोई जैसे क्षेत्रों पर है, जहां मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं. भाजपा नेता–कार्यकर्ता मुसलमानों के घर–घर जाकर उनसे पार्टी में शामिल होने की अपील कर रहे हैं. साथ ही उन्हें समझा रहे हैं कि मोदी केवल हिंदुओं के नहीं, बल्कि सभी भारतीयों के नेता हैं. दिल्ली भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आतिफ रशीद की मानें, तो अब तक 20 हज़ार मुस्लिम मतदाता भाजपा में शामिल हो चुके हैं. लेकिन, इन दावों के विपरीत आम मुसलमान की सोच भाजपा के प्रति अब भी पूरी तरह से बदली नहीं है. ओखला विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले शौकत अली का कहना है कि भाजपा तो किसी भी तरह सरकार बनाने के क़ाबिल नहीं है, क्योंकि जहां–जहां उसकी सरकार है, वहां आरएसएस का दिमाग़ चढ़ा हुआ है. रही बात कांग्रेस की, तो वह फिर भी ठीक है, लेकिन इस समय उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं है, जो जनता के निचले वर्ग की बात सुन सके. ऐसी स्थिति में एक आम आदमी पार्टी रह जाती है, जो ग़रीब आदमी से मिलकर उसका दु:ख–दर्द सुनती है. लेकिन, यह भी बता दूं कि वह केवल दु:ख–दर्द सुनती है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकालती. हो सकता है, इसकी वजह यह हो कि उसे 49 दिनों के अलावा कुछ करने का मौक़ा नहीं मिला. इसलिए उसे एक बार फिर मौक़ा देकर देखना चाहिए.

यह बात सच है कि जिस समय देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय कुछ मुसलमानों और खासकर मुस्लिम नौजवानों ने भाजपा के पक्ष में वोट डाले थे. मुसलमानों के इस वर्ग को नरेंद्र मोदी से काफ़ी उम्मीदें थीं और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने भी अपने सभी भाषणों में देश के 125 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलने और सबके विकास की बात कही, लेकिन दूसरी ओर लव–जिहाद या अन्य मुस्लिम विरोधी गतिविधियों पर वह मौन साधे रहे, जिसके चलते मुसलमानों का भाजपा समर्थक तबका भी इस पार्टी को लेकर संदेह की स्थिति में आ गया. दिल्ली के भी कुछ मुसलमान भाजपा को इसी नज़रिये से देखते हैं. इस लिहाज से ओखला विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं का रुझान आम आदमी पार्टी की ओर अधिक दिखाई देता है. हालांकि, यह भी सच है कि पिछली बार यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इरफान उल्ला खां को केवल 17 फ़ीसद वोट मिले थे और वह हार गए थे. जबकि जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ मोहम्मद खां को 36 फ़ीसद से अधिक वोट मिले थे. इरफ़ान दूसरे स्थान पर भले ही रहे, लेकिन उनकी हार 27 हज़ार वोटों के भारी अंतर से हुई थी. लिहाज़ा, इस बार आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव जीत ही जाएगी, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है.

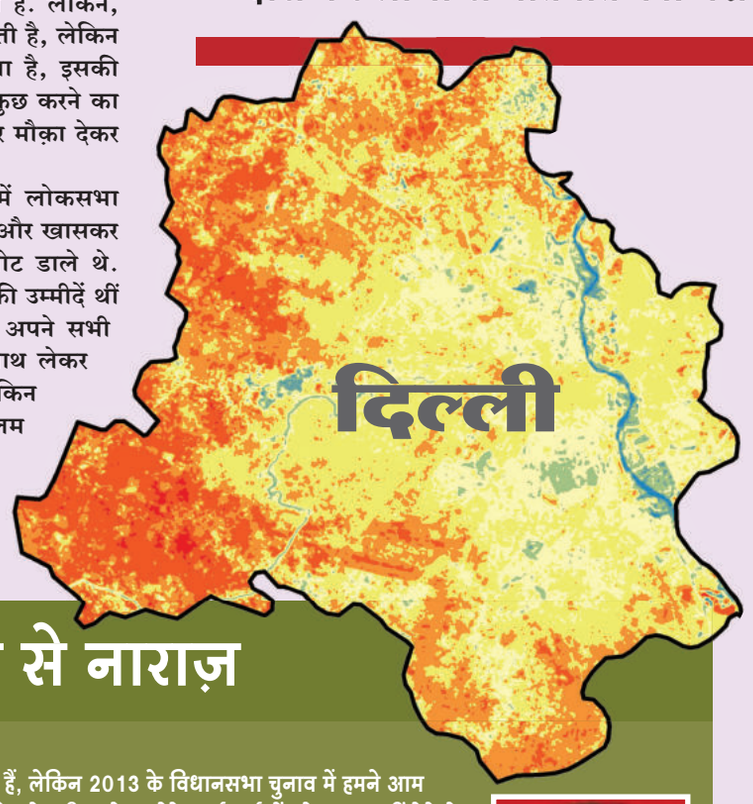

ओखला के विपरीत बाबरपुर, चांदनी चौक और मटिया महल विधानसभा क्षेत्रों के मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की ओर अधिक दिखाई देता है. हालांकि, इन क्षेत्रों में मुसलमानों का एक वर्ग आम आदमी पार्टी के भी पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस समर्थकों के मुकाबले उनकी संख्या कम है. बाबरपुर में मुसलमानों की आबादी लगभग 48 फ़ीसद है. पिछले चुनाव में यहां मुसलमानों का वोट कांग्रेस, बसपा, पीस पार्टी और आम आदमी पार्टी में विभाजित हो गया था, जिसके चलते भाजपा के उम्मीदवार नरेश गौड़ जीत गए थे. दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के जाकिर खां को 25.81, तीसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के गोपाल राय को 22.37, चौथे नंबर पर रहे पीस पार्टी के फुरकान कुरैशी को 8.71 और पांचवें नंबर पर रहे बसपा के भूरे खां को कुल 4.37 फ़ीसद वोट मिले थे. बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शाहीन उर्फ बब्लू कहते हैं कि कांग्रेस के विनय कुमार इस बार यहां से टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर कांग्रेस उन्हें यहां से उतारती है, तो वह बुरी तरह हारेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस की ओर से जाकिर को दोबारा टिकट मिलता है, तो वह चुनाव जीत जाएंगे. बब्लू कहते हैं कि फुरकान कुरैशी भी बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं. वह जनता के किसी काम के नहीं हैं, लेकिन पैसे वाले हैं. अगर कांग्रेस उन्हें यहां से लड़ाती है, तो वह भी जीत सकते हैं.

सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग पांच हज़ार घर मुसलमानों के हैं, जिनमें लगभग 15 हज़ार मतदाता हैं. ज़ाहिर है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह एक बड़ा वोट बैंक है. यहां के अधिकतर मुसलमान पहले कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन पिछली बार अधिकतर ने आम आदमी पार्टी को वोट दिए. शायद यही वजह थी कि पिछली बार यहां से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वीना आनंद लगभग 38 फ़ीसद वोट पाकर जीतने में कामयाब हुई थीं, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई. इस बार यहां के मुसलमान क्षेत्रीय विधायक से नाराज़ नज़र आ रहे हैं. उनकी शिकायत है कि वीना आनंद ने क्षेत्र और ख़ासकर यहां के मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया. स्थानीय निवासी अलीम अख्तर चौथी दुनिया से कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने इस आशा के साथ आम आदमी पार्टी को वोट दिया था कि यह नई पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग साबित होगी. वादे भी इसने बड़े लंबे–चौड़े किए थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह भी अन्य दलों जैसी निकली. यहां पिछले 15 वर्षों से जल बोर्ड का मीठा पानी नहीं आता. यहां की सड़कें अपने जनप्रतिनिधि की शिकायत खुद बयान करती नज़र आती हैं. प्रतिदिन सुबह बिजली गायब हो जाती है और तीन–चार घंटे नहीं आती. 2013 के चुनाव से पहले हमने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हमें क्या दिया? यहां हर समाज के लिए चौपालें बनाई गईं, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कालोनी, न्यू रंजीत नगर को चौपाल तो क्या, बारात घर या एक सामुदायिक केंद्र तक नहीं दिया गया. यहां के पार्क कूड़ाघर बने हुए हैं. बिजली–पानी से हम महरूम होकर रह गए हैं. ऐसी स्थिति में हम किससे उम्मीद करें, कौन–सी पार्टी को वोट दें? हम स्वयं असमंजस में हैं, इसलिए भविष्य का फ़ैसला भविष्य में ही करेंगे.

> **मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में से एक सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल एक लाख 60 हज़ार मतदाताओं में 60 फ़ीसद मुसलमान हैं. वे यहां किसी भी उम्मीदवार की हार-जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यहां कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद पांच बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं. इस बार भी सीलमपुर के मुसलमानों का रुझान चौधरी मतीन अहमद की ओर दिखाई देता है.**

मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में से एक सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल एक लाख 60 हज़ार मतदाताओं में 60 फ़ीसद मुसलमान हैं. वे यहां किसी भी उम्मीदवार की हार–जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यहां कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद पांच बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं. इस बार भी सीलमपुर के मुसलमानों का रुझान चौधरी मतीन अहमद की ओर दिखाई देता है. आम आदमी पार्टी का चूंकि यहां कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए यहां मुस्लिम वोटों के विभाजन की कोई संभावना नहीं है. दूसरी ओर, अगर मुसलमानों के कुछ वोट भाजपा की ओर चले जाते हैं, तो भी कोई खास तब्दीली होती नज़र नहीं आती. सीलमपुर से संबंध रखने वाले हकीम फहीम बेग का कहना है कि यहां (सीलमपुर) का मुसलमान चौधरी मतीन अहमद से संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है. मुसलमानों का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है और अगर वह चौधरी मतीन अहमद को वोट देगा, तो केवल उनके जाने–पहचाने मुस्लिम चेहरे होने के कारण. सीमापुरी में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है. पिछली बार यहां के अधिकतर मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और इस बार भी वे इसी पार्टी के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं. सीमापुरी में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले मोहम्मद इजरायल ने बताया कि वह आप के लिए वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि आप की 49 दिनों की सरकार के दौरान ग़रीब आदमी ख़ुशहाल हो गया था. उस दौरान आरटीओ में धांधली ख़त्म हो गई थी, अस्पतालों में सफाई रहती थी, दवाएं मुफ्त मिलने लगी थीं और पानी–बिजली की क़ीमतें कम हो गई थीं. कांग्रेस ने तो सिर्फ़ कहा, लेकिन मुसलमानों की बेहतरी के लिए 15 सालों में कुछ नहीं किया. हमारे बच्चों को अच्छी तालीम चाहिए, जो आम आदमी पार्टी की सरकार में संभव है.

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली के मुसलमानों का वोट इस बार भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बंटने की पूरी संभावना है. अब उनकी पसंद का झुकाव किस तरफ़ ज़्यादा होगा और किस तरफ़ कम, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. ■

मुसलमान कांग्रेस से नाराज़

पिछले 40 वर्षों से हम कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया. कारण यह कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोटे कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देते थे. मैं दिल्ली में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष रहा हूं. मैंने न केवल पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सेवा की, बल्कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों और बाहर जाकर भी पार्टी का प्रचार-प्रसार किया, लेकिन कांग्रेस ने हमारी कौम के लिए कुछ नहीं किया. इसकी एक मिसाल यह है कि मैं पिछले 10 वर्षों से अपने क्षेत्र के लिए कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहा हूं. दिल्ली सरकार एवं क्षेत्रीय सांसद के कार्यालय और घर के चक्कर काटते-काटते थक चुका हूं. केंद्र और राज्य में यानी दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अफ़सोस कि कामयाबी हाथ नहीं लगी. इसके लिए मैंने राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन उनके इर्द-गिर्द बैठी मंडली ने उनसे मिलने का समय नहीं दिया. हां, कांग्रेस की शीला सरकार ने दिल्ली में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा देने की घोषणा ज़रूर की, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें, तो न स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जा रही है, न वहां उर्दू शिक्षक हैं, न सरकारी विभागों में उर्दू में लिखे आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं और न उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ा गया. 2013 के विधानसभा चुनाव में पटेल नगर क्षेत्र से कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक को फिर टिकट दिया, तो हमने खुलकर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद उसी को उम्मीदवार बनाया गया, तो हमने अपना वोट एक बिल्कुल नई पार्टी को दे दिया और वह पटेल नगर विधानसभा सीट से सफल भी हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की विधायक भी हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं. हमें एक बार फिर वोट के लिए पुनर्विचार करना है और कौन-सी पार्टी कौन-सा उम्मीदवार ला रही है, यह सब देखकर हम अंतिम निर्णय लेंगे. *-मुख्तार अहमद, पटेल नगर, दिल्ली.*

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

ग़ैर-भाजपाई दलों की प्रतिष्ठा दांव पर

चुनाव प्रचार में जहां राष्ट्रीय पार्टियां बहुत आगे हैं, वहीं स्थानीय दल एवं निर्दलीय उम्मीदवार भी उनसे कम नज़र नहीं आ रहे. देर शाम तक प्रचार कार्य चल रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले दिनों एक जनसभा में कहा कि जब झारखंड का गठन हुआ था, उस समय यहां के सिर्फ़ तीन ज़िले उग्रवाद की चपेट में थे, लेकिन भाजपा की ग़लत नीतियों के चलते आज प्रदेश के सभी ज़िले उग्रवाद की चपेट में हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास विकास की कोई सोच या नीति नहीं है और वह सिर्फ़ कांग्रेस की नीतियों एवं योजनाओं के नाम बदल कर अपने नाम का ढिंढोरा पीट रही है.

मंगलानंद

झारखंड विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है. खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इस सूबे की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ राष्ट्रीय दलों के स्टार प्रचारकों का आगमन बदस्तूर जारी है. केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहते. क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, राजद, जदयू एवं टीएमसी के

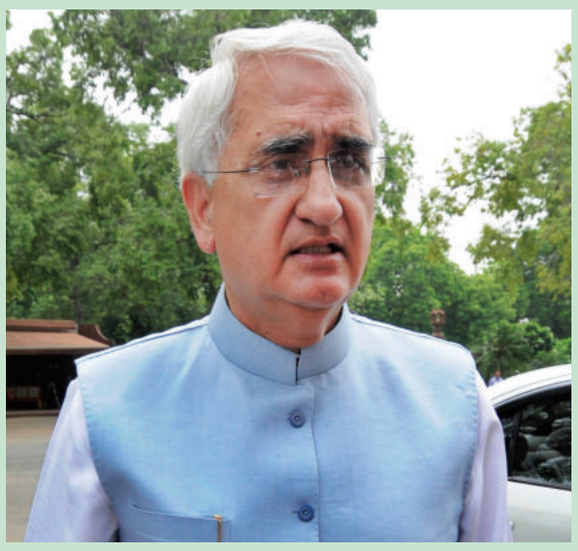

नेता धड़ाधड़ चुनावी घोषणाओं की बरसात कर रहे हैं. वे तरह-तरह के वादे कर रहे हैं. चुनाव को लेकर इस बार जनता के साथ-साथ नेताओं का उत्साह भी चरम पर है. नेताओं की गाड़ियां मुहल्लों की गली-कूचे तक जा रही हैं. स्थानीय भाषाओं के माध्यम से अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाई जा रही है. मतदाता भी सबके वादे-नारे ध्यान से सुन रहे हैं और अपना ताना-बाना बुन रहे हैं.

महुआ की सक्रियता और भाजपा की मुश्किल

झामुमो की प्रत्याशी महुआ माझी ने बंगालियों के बीच लोकप्रिय रांची के वर्तमान भाजपा विधायक सीपी सिंह के लिए परेशानी बढ़ा दी है. अर्से से राजनीति से दूर रहने वाले बंगाली समुदाय के लिए यह चुनाव परीक्षा की घड़ी है. महुआ माझी के चुनाव मैदान में आने के बाद से शहर की बंगाली महिलाएं अचानक सक्रिय हो गई हैं. क़रीब दो दशक पूर्व स्वर्गीय ज्ञानरंजन के दौर में बंगाली समुदाय की महिलाएं राजनीति में सक्रिय हुआ करती थीं. उसके बाद से यह समुदाय सिर्फ़ भाजपा को वोट देता आ रहा है. इस बार का चुनावी समीकरण निश्चित तौर पर भाजपा के लिए चिंता का विषय बन चुका है. साहित्य जगत से जुड़ी महुआ को झामुमो से टिकट मिलने की वजह से बंगाली समुदाय के साहित्यिक लोग भी इस बार राजनीति में रुचि ले रहे हैं. वर्धवान कंपाउंड, थइपखना, पीस रोड, लालपुर, कोकर के अलावा डोरंडा, कडरू, ऑफिस पाड़ा एवं हिनू जैसे इलाकों में बंगाली समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है. आम तौर पर यह वर्ग मतदान तो करता है, पर राजनीतिक गतिविधियों से खुद को दूर रखता है. कांग्रेस के नेता ज्ञानरंजन के समय ऐसी स्थिति नहीं थी. यहां कांग्रेस महिला सेवादल के एक शिविर में इंदिरा गांधी खुद शामिल हुई थीं. बाद में यह समुदाय राजनीति से दूर हो गया. इस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता भी समाज पर कोई असर नहीं छोड़ सके. इस बार महुआ माझी चुनाव मैदान में भाजपा को टक्कर दे रही हैं. महुआ के लिए अच्छी बात यह है कि वह सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी हैं और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

चुनाव प्रचार में जहां राष्ट्रीय पार्टियां बहुत आगे हैं, वहीं स्थानीय दल एवं निर्दलीय उम्मीदवार भी उनसे कम नज़र नहीं आ रहे. देर शाम तक प्रचार कार्य चल रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले दिनों एक जनसभा में कहा कि जब झारखंड का गठन हुआ था, उस समय यहां के सिर्फ़ तीन ज़िले उग्रवाद की चपेट में थे, लेकिन भाजपा की ग़लत नीतियों के चलते आज प्रदेश के सभी ज़िले उग्रवाद की चपेट में हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास विकास की कोई सोच या नीति नहीं है और वह सिर्फ़ कांग्रेस की नीतियों एवं योजनाओं के नाम बदल कर अपने नाम का ढिंढोरा पीट रही है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच रही है कि कोई ग़रीब भूखे पेट न सोए, गेहूं-चावल सस्ता मिले. इसके लिए खाद्य सुरक्षा का क्रांतिकारी क़ानून बनाया गया. प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का हो, यह व्यवस्था भी कांग्रेस ने की. सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर बिजली, पानी एवं सड़कों पर खास ध्यान दिया जाएगा और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा. उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि जो लोग भटक गए हैं, वे मुख्य धारा में लौटकर लोकतंत्र और भारत को मजबूत करें.

रांची विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हिंदपीढ़ी एवं कर्बला चौक पर सभाएं करके जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि रांची के विकास के लिए सुरेंद्र सिंह को वोट दें. सुरेंद्र रांची की जनता के हक़ की लड़ाई लड़ते रहे हैं, इसलिए सोनिया गांधी ने उन्हें टिकट दिया है. उन्होंने मोदी सरकार पर यूपीए द्वारा किए गए कार्यों की वाहवाही लूटने का आरोप लगाया. हटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक दुबे ने कहा कि क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे. वह जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभा के दौरान लोगों के बीच अपनी बात रख रहे थे. उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड गठन के बाद 10 वर्षों तक शासन करके भ्रष्टाचार और अपराध को सींचा. इसी वजह से आज सूबे की यह हालत है. उधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा की नज़र झारखंड की खनिज संपदा पर है. वह इसे लूटना चाहती है. सोरेन ने रांची विधानसभा क्षेत्र से झामुमो की प्रत्याशी महुआ माझी के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी झूठे सपने दिखाकर प्रधानमंत्री बने हैं और अब उसी अंदाज़ में यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं. झामुमो मोदी का रथ रोकेगा, क्योंकि भाजपा आदिवासी-मूलवासी को देखना नहीं चाहती. भाजपा से जुड़े आदिवासी नेताओं को काम करने नहीं दिया जाता. प्रधानमंत्री महिलाओं के हितों के बारे में भाषण देते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचते. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूंजीपतियों के बिचौलिए हैं. हेमंत ने कहा कि मोदी इन दिनों विदेश यात्राएं करके व्यापारियों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

उनकी महानता को छोटा मत कीजिए

बिहार

सुकांत

मंडल मसीहा विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस साल बिहार में रथ यात्रा निकाल कर याद किया गया. उनकी स्मृति में एक पखवाड़े तक बिहार के विभिन्न इलाकों में रथ यात्रा निकाली गई, जिसका समापन पटना में लोक स्वराज्य प्रतिबद्धता दिवस के रूप में हुआ. राजधानी पटना में उस दिन भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें जनता दल (यू) के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह सहित राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद थे. समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, पर अस्वस्थता के कारण भाग नहीं ले सके. नीतीश कुमार संपर्क यात्रा से उसी दिन लौटे थे और हरारत के कारण उनका अस्वस्थ हो जाना स्वाभाविक था. हालांकि, उनकी अनुपस्थिति आयोजक एवं जद (यू) के युवा विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह को खल गई होगी. विनोद कुमार सिंह ने पार्टी की बड़ी सेवा की और उसे एक सामाजिक समूह से नए सिरे से जोड़ने की कोशिश की. वीपी सिंह जब भ्रष्टाचार को लेकर राजीव गांधी के ख़िलाफ़ अभियान चलाने के लिए सत्ता त्याग कर सड़क पर आ गए, तो उन्हें राजर्षि कहा गया. वीपी आम भारतीय की उम्मीद के प्रतीक बन गए थे. वह भारतीय राजनीति का बड़ा नाजुक दौर था. वीपी सामने आए और उन्होंने नायकत्व ग्रहण किया. आमजन अब भी उन्हें उच्च आदर्शों के लिए बड़े आदर से याद करते हैं. और, अब विनोद सिंह अपनी दलीय सीमा के तहत ही उनके आदर्शों के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं. दलीय सीमा इसलिए, क्योंकि पूरे आयोजन में दल का ही बोलबाला रहा. यह कोशिश वीपी सिंह के विराट व्यक्तित्व को छोटा नहीं कर रही है!

बिहार में पिछले कई महीनों से जन्मतिथि-पुण्यतिथि के आयोजनों का दौर चल रहा है. चूंकि सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा राजनीतिक दलों में होड़ लगी है, न जाने किस जन्मतिथि-पुण्यतिथि से कितना वोट बढ़ जाए! विश्वनाथ प्रताप सिंह का देहांत 27 अक्टूबर, 2008 को हुआ था. उन्हें लेकर छोटे-मोटे आयोजन तो देखे-सुने जाते रहे हैं, पर एक पखवाड़े तक राज्यव्यापी अभियान पहली बार शुरू किया गया. कहने को तो जनता दल (यू) के विधान पार्षद विनोद सिंह ने यह अभियान चलाया. वीपी सिंह के आदर्शों को लेकर आमजन की चेतना जगाने के लिए यह सब किया गया. लेकिन, क्या इस अभियान के पीछे मात्र यही निर्मल-भाव था? लगता है, बात कुछ और हो सकती है, कुछ दल की और कुछ विनोद सिंह की. राज्य में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारियां शुरू हो गई हैं. विभिन्न जातीय समूहों को जगाने और उन्हें अपने साथ गोलबंद करने की कवायद जारी है. राजनीति अब जमात की रही नहीं, वह जाति तक तो चली ही गई है. पर, कई मामलों (और शायद अधिकांश मामलों) में यह जाति का बाना त्याग कर कुनबों तक सीमित हो गई है. ऐसे में कुछ राजनेता कम से कम जाति के बारे में तो सोचते हैं, यही क्या कम है! वस्तुत: तीखी जातीय गोलबंदी (वोटबंदी) के बीच ऐसा अभियान अस्वाभाविक भी नहीं है.

बिहार के सामाजिक समूहों की राजनीतिक निष्ठाएं काफी साफ़ होती जा रही हैं. पिछले कई वर्षों से मंडल राजनीति के नायकों से बिहार के अगड़े समाज की न केवल दूरी रही है, बल्कि यह जातीय दलबंदी में तब्दील होती चली गई. यह दूरी (या दलबंदी कह लीजिए) मंडल राजनीति के नायकों के प्रशासनिक व राजनीतिक निर्णयों और इन सामाजिक समूहों के राजनीतिक आचरण में अभिव्यक्त होती रही है. इसीलिए पिछले कई वर्षों से मंडलवादी राजनीति के निष्ठावान नेता बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह को बड़े तामझाम के साथ उनकी जयंती-पुण्यतिथि मनाकर याद करते आ रहे हैं. नवादा- मुंगेर से लेकर पटना-दिल्ली तक उन्हें याद करने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन किए जाते हैं. नीतीश कुमार एवं अन्य बड़े नेता इन आयोजनों में शामिल हुए हैं. श्री बाबू के स्वजातीय मतदाताओं को उनके शुभचिंतक होने का भरोसा दिलाते रहे हैं. वस्तुत: वीपी सिंह को भी इसी ख्याल से याद किया गया लगता है. इससे पहले वीपी सिंह को लेकर ऐसे आयोजनों से बिहार के लोग रूबरू नहीं हुए थे. यहां यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि उक्त सभी आयोजन पार्टी स्तर पर नहीं होते. जद (यू) के नेताओं को आगे करके यह काम किया जाता है. इस मामले में जद (यू) में एकरूपता है कि कुछ खास आदर्श व्यक्तित्वों की जयंती-पुण्यतिथि वह आयोजित करता है, बाकी जयंती या पुण्यतिथि, किसी भी व्यक्तित्व की क्यों न हो, पार्टी नहीं मनाती, उसके नेता मनाते हैं. मंडल मसीहा वीपी सिंह के साथ भी यही हुआ, श्री बाबू के साथ भी यही हुआ.

वोट के लिए नाम भुनाने की कछुआ-खरगोश दौड़ में चाल, चरित्र और चेहरे की शुचिता को लेकर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है. बिहार में अपने आदिपुरुष कैलाशपति मिश्र की जयंती भुला देने वाली भाजपा एक बार फिर उन्हें लेकर काफी संवेदनशील हो गई. उसने पिछले दिनों कैलाशपति मिश्र की स्मृति में पूरे राज्य में पूरे सप्ताह का अभियान चलाया. उनके नाम पर पटना में एक बड़ा आयोजन किया गया. भाजपा डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती दलीय स्तर पर तो नहीं मनाती, पर अपने किसी नेता को आगे करके यह काम अंजाम देती है. भाजपा में दलित नायकों को लेकर भी बहुत उत्साह कहीं नहीं दिखता. औरों की बात जाने दीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक की जयंती बिहार में भाजपा नहीं मनाती. जब बंगारू लक्ष्मण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अंबेडकर को याद करने की परंपरा राष्ट्रीय स्तर पर बनी थी, जो राज्य तक ढंग से नहीं उतर सकी. हां, कुछ नेताओं के स्तर पर यह आयोजन होता रहा.

लेकिन, भाजपा पिछले कुछ वर्षों से कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने लगी है. कर्पूरी जी बिहार के जिस सामाजिक समूह (अति पिछड़ा) के रहे हैं, वह पिछले कुछ वर्षों से एक सशक्त वोट बैंक के तौर पर उभरा है. गत दो-तीन चुनावों में इस समूह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है. अब फिर चुनाव आ रहा है और इस वोट बैंक पर लालू-नीतीश के साथ-साथ भाजपा की भी गहरी नज़र है. लोकसभा चुनाव के दौरान इस वोट बैंक में नरेंद्र मोदी की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण भाजपा ने खासी सेंधमारी की थी और उससे चुनाव परिणाम में संख्यात्मक तौर पर फ़र्क़ पड़ा था. इतना तो तय है कि अति पिछड़ों का समूह लालू-नीतीश के साथ अपनी सहज एकता पाता है, जबकि भाजपा से उसे कई स्तर पर हिचक है और इसका कारण भाजपा का समर्थक सामाजिक समूह है. भाजपा ने अब कर्पूरी जयंती का आयोजन प्रखंड स्तर तक करने का निर्णय लिया है. इसके पीछे नए-नए सामाजिक समूहों को पार्टी से जोड़ने और भावी विधानसभा चुनाव में उन्हें वोटों में तब्दील करने की मंशा है. यह देखने और समझने में अभी वक्त लगेगा कि भाजपा को इससे कितना लाभ मिलता है.

वस्तुत: राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए राजनीति के सिवाय किसी और का कोई महत्व नहीं है. भारतीय समाज के आदर्श व्यक्तित्वों को राजनीति में जातीय वोट बैंक का उपकरण बनाने की हरसूरत कोशिश की जा रही है. सरदार पटेल, नेहरू, लोहिया एवं जेपी जैसे युगांतकारी राजनेताओं की बात तो दूर, सामाजिक एवं ऐतिहासिक नायकों के साथ भी यही हो रहा है. देश की राजनीति हमारे नायकों को वोट जुगाड़ू प्रतिमा में बदल रही है. वीपी सिंह के साथ भी यही हो रहा है. राजनीति में कोई तो ऐसा आए, जो हमारे नायकों की महानता को वोट की राजनीति से बाहर रखे. लगता है, इसके लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी, लंबी प्रतीक्षा.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

फरवरी में आने वाले बजट में सुधार की बातें वित्त मंत्री कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक नीति देखने को नहीं मिली है. पिछला बजट बहुत ही डरपोक किस्म का था. मौजूदा वित्त मंत्री को कुछ साहसिक क़दम उठाने होंगे. इसमें केवल निवेश ही नहीं, बल्कि रोज़गार के अवसर भी शामिल हों. कृषि क्षेत्र अभी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है और कृषि क्षेत्र को रियायतें या फ़ायदे देने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए. आप कृषि, विनिर्माण क्षेत्र या बुनियादी ढांचे के लिए जो भी करना चाहते हैं, अभी करें.

अब वक्त काम करने का है...

संसद, विशेष रूप से राज्यसभा, जहां विपक्षी बड़ी संख्या में हैं, सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है. उत्तर प्रदेश से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति (साध्वी ऋतंभरा की अनुयायी) ने राजनीतिक रूप से कुछ अस्वीकार्य टिप्पणी की है. जाहिर है, वह सरकार चलाने के लिए आवश्यक चीजों का महत्व नहीं जानती हैं. ऐसी सूचना आ रही थी कि कांग्रेस और भाजपा के बीच आर्थिक मामलों या प्रक्रियात्मक मामलों से जुड़े बिलों, जो विवादास्पद नहीं हैं, को पारित कराने के लिए एक समझौता हुआ था. दुर्भाग्य से इसमें भी ठहराव आ गया है. लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति इस सबमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. हां, संसदीय मामलों के मंत्री कांग्रेस के साथ मिलकर समाधान निकाल सकते हैं. यह शर्म की बात होगी कि पिछले सत्र की तरह यह सत्र भी बिना काम किए निकल जाए.

इस बीच राजनीतिक मोर्चे पर 1989 में सत्ता में रही पार्टी जनता दल के विभिन्न गुट एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं. सभी जानते हैं कि इनमें से किसी के बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं है. यह केवल व्यक्तित्व आधारित और क्षेत्र आधारित पार्टी है. जैसे, हरियाणा में चौटाला, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, बिहार में लालू–नीतीश और कर्नाटक में देवगौड़ा. मैं नहीं जानता कि यह सब कितनी दूर जाएगा, लेकिन यह शुभ संकेत है कि ऐसी राजनीति फिर से ज़िंदा हो रही है. ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रभावी विपक्ष होने की अपनी ज़िम्मेदारी को त्याग रही है. खड़गे एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में वह उतने मुखर नहीं हैं.

अगला चुनाव पांच साल दूर है, लेकिन ग़ैर–कांग्रेस व ग़ैर–भाजपा दलों को कुछ ठोस करने के लिए एक साथ मिल जाना चाहिए. वामदल निश्चित रूप से अव्यवस्थित हैं, उन्हें आत्मविश्लेषण करना चाहिए और अपनी सभी ग़लतियां सुधारने की कोशिश करनी चाहिए. मेरी राय में वामदल भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण तत्व हैं, कम से कम पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में. ये जहां भी हैं, वहां वाम आंदोलन फिर से प्रभावी हो सकता है. उनके पास युवा हैं, उन्हें आगे आकर नेतृत्व की ज़िम्मेदारियां संभालनी चाहिए, ताकि फिर से वाम आंदोलन जीवित हो.

संपूर्ण रूप से देखें, तो भारत ग़रीबों का देश है. आबादी का आधा हिस्सा ग़रीब है. बाकी को भी अमीर नहीं कह सकते. अमीरों की संख्या बहुत ही कम है. उनकी संख्या आबादी का एक छोटा–सा अंश है. जब तक सरकार या विपक्षी दल (जब वे सरकार में आते हैं) ग़रीबों के लिए कुछ नहीं करते, तब तक इस राजनीति का कोई मतलब नहीं है. हमारे ज़्यादातर नेता और राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाली मशीन बनकर रह गए हैं. चुनाव जीतने के बाद वे उसी की जगह पर होते हैं, जिसे वे पराजित करते हैं. अगर यही सब कुछ केंद्र में भाजपा के साथ होता है, तो यह एक दु:खद बात होगी. वे तीस साल बाद स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं. वे कुछ ठोस परिणाम दिखा सकते हैं. अगर वे भी अन्य सरकारों की तरह काम करते हैं, तो जल्द ही अपनी चमक खो देंगे.

प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं, भारत के लिए सद्भावना पैदा कर रहे हैं. यह अच्छी बात है. ऑस्ट्रेलिया से आप अपने परमाणु कार्यक्रम में मदद के लिए यूरेनियम आदि पाने की उम्मीद कर सकते हैं. ओबामा गणतंत्र दिवस के मौक़े पर यहां आ रहे हैं. एक समय में दो खास बातें हो रही हैं. पहली बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर आ रहा है. दूसरी यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान दोबारा भारत आ रहे हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. यह सब अच्छा है, लेकिन भारत को लाभ लेने के लिए काम भी करने होंगे. अमेरिका के लिए कुछ अधिक वीजा देने से मदद नहीं मिलने वाली है.

फरवरी में आने वाले बजट में सुधार की बातें वित्त मंत्री कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक नीति देखने को नहीं मिली है. पिछला बजट बहुत ही डरपोक किस्म का था. मौजूदा वित्त मंत्री को कुछ साहसिक क़दम उठाने होंगे. इसमें केवल निवेश ही नहीं, बल्कि

> **प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं, भारत के लिए सद्भावना पैदा कर रहे हैं. यह अच्छी बात है. ऑस्ट्रेलिया से आप अपने परमाणु कार्यक्रम में मदद के लिए यूरेनियम आदि पाने की उम्मीद कर सकते हैं. ओबामा गणतंत्र दिवस के मौक़े पर यहां आ रहे हैं. एक समय में दो खास बातें हो रही हैं. पहली बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर आ रहा है. दूसरी यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान दोबारा भारत आ रहे हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. यह सब अच्छा है, लेकिन भारत को लाभ लेने के लिए काम भी करने होंगे.**

रोज़गार के अवसर भी शामिल हों. कृषि क्षेत्र अभी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है और कृषि क्षेत्र को रियायतें या फ़ायदे देने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए. आप कृषि, विनिर्माण क्षेत्र या बुनियादी ढांचे के लिए जो भी करना चाहते हैं, अभी करें. परिणाम आने में पांच या दस साल लग सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप काम ही न करें. आप सत्ता में आ गए हैं, कृपया अपना बेहतर दें. यह देश के हित में है. देश एक सतत चीज है. चुनाव तो हर पांच साल बाद आते हैं. इसलिए सत्ता में कौन आता है, इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता. वक्त निर्माण का है. परिणाम कुछ वर्षों के बाद आएगा, लेकिन सभी प्रयास शीघ्र किए जाने चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

लाजवाब टीम और धारदार लेखन

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

चौथी दुनिया में मैंने अधिकांशतया सुरेंद्र जी के तरीके को ही अपनाने की कोशिश की. ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड रिपोर्ट पर ध्यान दिया तथा जो लिख सकते थे, उनसे लिखवाया. ख़बरों का चुनाव इस आधार पर होता था कि वे दैनिक अख़बारों का विस्तार न लगें. उनमें गंभीरता हो, विश्लेषण हो, जानकारी हो, निष्पक्षता हो और निर्भीकता भी हो. कोशिश थी कि रिपोर्ट में राजनीति के साथ सामाजिक व आर्थिक पहलू भी पाठक के सामने आएं. चौथी दुनिया टीम के मामले में काफी भाग्यशाली माना जा सकता है. कमर वहीद नकवी ने डेस्क की सारी ज़िम्मेदारी संभाल ली थी, तो राम कृपाल ने संयोजन और सामान्य योजना की. आलोक पुराणिक, विनोद चंदोला, राजीव कटारा और अजय चौधरी डेस्क में मेहनत करते थे. वीरेंद्र सेंगर व अरविंद ने रिपोर्टर का काम काफी मेहनत से किया. जोसेफ गाथिया भी कुछ दिनों तक रहे और जब तक रहे, अच्छे रिपोर्टर का काम करते रहे. राज्यों में परशुराम शर्मा व शीतल ने अच्छा काम किया. रामपाल भदौरिया ने सामान्य प्रशासन संभाला. लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र नाथ योगी ने अनुशील नामक छात्र को हमारे पास भेजा. उसने चौथी दुनिया का मास्ट डिजाइन करने में बड़ी मेहनत की, प्रारंभिक ले–आउट भी उसी ने बनाया था, इसमें नकवी दिशा निर्देश कर रहे थे. पहले अंक में बनाया गया जयप्रकाश नारायण का स्केच अद्भुत था. अनुशील सचमुच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था.

यहां मेरा प्रयास चौथी दुनिया का प्रशस्ति गान नहीं है, लेकिन चौथी दुनिया ने रविवार व दिनमान की शैली का मिश्रण किया और इस प्रयास में चौथी दुनिया की अपनी शैली विकसित हो गई. यह शैली थी साहस, धारदार पत्रकारिता और वैचारिक सोच से ओत–प्रोत रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण. यदि रिपोर्ट की संख्या गिनने बैठें, तो बहुत–सी मिलेंगी, पर जिस तरह चौथी दुनिया ने किसान आंदोलन को कवर किया था, वह इतिहास में न उससे पहले हुआ और न अब तक हुआ है. जिस तरह दंगों की रिपोर्टिंग हुई, वह अपने आप में अनूठी थी. चौथी दुनिया की हेड लाइन थी, लाइन में खड़ा किया, गोली मारी और लाशें बहा दीं. हाशिमपुरा–मलियाना में हुए इस अमानवीय हत्याकांड को देश के किसी अख़बार में उजागर करने की हिम्मत नहीं हुई. यह रिपोर्ट चौथी दुनिया टीम की सच्ची पत्रकारिता की जगमगाती हुई मिसाल है. इसे वीरेंद्र सेंगर ने सबसे पहले खोजा था.

चौथी दुनिया में हम सब इस सिद्धांत पर भरोसा करते थे कि यदि रिपोर्ट सही है, तो उसके साथ रिपोर्टर और अख़बार को खड़ा होना चाहिए. हमने उस समय की राजनैतिक स्थिति, भ्रष्टाचार और नेताओं के आचरण को आधार बनाकर साफ़ और निर्भीक रिपोर्ट करवाई. सच हमेशा एक तरफ़ खड़ा होता है. उन दिनों यह सत्ताधीशों के ख़िलाफ़ खड़ा था और इतनी साफ़गोई से खड़ा था कि प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आम हवा बना गया. चौथी दुनिया देश के हिंदी इतिहास में पहला साप्ताहिक अख़बार तो था ही, दैनिक अख़बारों में भी यह पहला था, जिसने ग्लेज़ पेपर पर संपूर्ण यानी चार और आठ पेज चार कलर में छापे. तब तक हिंदी में अख़बार न्यूज प्रिंट पर पहला और चौथा पेज कलर छापते थे. साहित्य, कला, संस्कृति और व्यंग्य में चौथी दुनिया ने कई कीर्तिमान स्थापित किए. नरेंद्र कोहली का उपन्यास इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था कि नकवी को लगा कि यह नए तरह का नशा बन रहा है. उसे सोच–समझ कर छापना बंद करना पड़ा. चंचल लगातार व्यंग्य लेखन करते थे और अच्छे व्यंग्यकार के रूप में उन्होंने स्थान बनाया. चौथी दुनिया ने लगातार विश्व के देशों के बारे में शृंखला छापी, जिसे बहुत दिनों तक आनंद स्वरूप वर्मा ने लिखा.

जो चौथी दुनिया के साथ थे, उन्होंने बाद में अपना जो स्थान बनाया, वह आज यह स्थापित कर गया कि चौथी दुनिया ने सही पत्रकारिता की दिशा पकड़ी थी. आज राम कृपाल नवभारत टाइम्स के संपादक हैं. कमर वहीद नकवी पहले आजतक के मुख्य कार्यकारी निर्माता रहे यानी मुख्य संपादक. नकवी आजतक में इस समय निदेशक समाचार हैं. कुछ दिनों के लिए नकवी ने आजतक छोड़ दिया था. तब अजय चौधरी ने आजतक का संयोजन किया, पर उनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई. आलोक पुराणिक केवल व्यंग्यकार के रूप में ही स्थापित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने व्यापार संबंधी लेखों में भी महारथ हासिल की. राजीव कटारा देश के प्रसिद्ध खेल पत्रकार हैं. विनोद चंदोला इस समय बीजिंग रेडियो की हिंदी सर्विस के संपादक हैं. कई साल पहले विनोद चंदोला आए और उन्होंने कहा कि आपके साथ काम करने के लिए मैं बीजिंग छोड़कर आ सकता हूं. वीरेंद्र सेंगर अमर उजाला के दिल्ली इंचार्ज हैं तथा अरविंद जनसत्ता एक्सप्रेस के राजनीतिक संपादक हैं.

अजीत अंजुम इन दिनों अनुराधा प्रसाद की बीएजी फिल्म के सर्वेसर्वा हैं. जोसेफ गाथिया बच्चों से संबंधित एक बड़ी संस्था चला रहे हैं. मैं हरि नारायण सिंह को नहीं भूल सकता. वह रविवार में सहायक थे, चौथी दुनिया में उप–संपादक बनकर आए. हरि बहुत मेहनती थे. हरि बाद में प्रभात ख़बर में न्यूज एडिटर बनकर गए तथा उसके बाद रांची से निकलने वाले दैनिक हिंदुस्तान में स्थानीय संपादक बन गए. चौथी दुनिया में फ्रीलांस करने वाले कई पत्रकार राष्ट्रीय अख़बारों में सहायक संपादक बन गए. कई आज बड़े फिल्म निर्माता हैं. यहां मैं संजय सलिल का जिक्र करना चाहूंगा. वह मेरे साथ हेड लाइन में आए और तेजी से तरक्की करते हुए आजतक सुबह के प्रमुख हो गए. इन दिनों वह जागरण टीवी की स्थापना कर रहे हैं तथा उनका इरादा टीवी चैनलों की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने का है. इन सब लोगों ने जहां पत्रकारिता में अपना ऊंचा स्थान बनाया, वहीं मुझे भी यह सौभाग्य दिया कि मैं कह सकूं कि मैंने इनके साथ काफी दिनों तक कार्य किया है.

मैं चौथी दुनिया के बारे में ज़्यादा लिखना नहीं चाहता, पर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि रामनाथ गोयनका, अवीक सरकार और कमल मोरारका जैसे मालिक हों, तो अख़बारों में काम करने का पत्रकारों को मजा आता है. इसमें अवीक सरकार के साथ मेरा सीधा संबंध बहुत नहीं रहा, पर यदि वह आज़ादी न देते, तो रविवार, रविवार न होता और यदि कमल मोरारका आज़ादी न देते, तो चौथी दुनिया, चौथी दुनिया न होता. कमल मोरारका ने हिंदी पत्रकारिता से हाथ खींच लिया, शायद इसके पीछे मैं हूं, जिसने लोकसभा में जाने के बाद चौथी दुनिया में रुचि लेना बंद कर दिया था. उन्होंने चौथी दुनिया मेरे लिए निकाला और मैं उनका साथ नहीं दे पाया. मेरे सामने बड़ा सवाल था, यदि मैं अपने नाम के अनुरूप पत्रकारिता करता हूं, तो मुझे हर हफ्ते जनता दल के ख़िलाफ़ लिखना पड़ेगा, जिससे उस समय की बनी सरकार परेशानी में पड़ जाती और यदि मैं जनता दल सरकार की चापलूसी करता, तो मैं पाठकों के साथ दगाबाजी करता. इसीलिए मैं सांसद बनते ही चौथी दुनिया का सलाहकार संपादक बन गया, पर मैंने लगातार इलेस्ट्रेटेड वीकली और धर्मयुग में कॉलम लिखना जारी रखा. और वे कॉलम उस समय भी गवाह थे, आज भी गवाह हैं कि मैंने कभी लिखने का सौदा नहीं किया. एक पत्रकार के लिए सबसे गर्व की बात यही है कि उसे जब भी लोग याद करें, पत्रकार के रूप में याद करें. और अपने इस सौभाग्य पर, पाठकों के आशीर्वाद पर मेरा सिर हमेशा झुका रहेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

संसद को देशद्रोह के कलंक से बचाइए

हमें सांसदों पर टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में अब फ़ैसला कर लेना चाहिए. हम लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देख रहे हैं और खासकर मौजूदा लोकसभा की. सांसद चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों, कांग्रेस से जुड़े हों या अन्य दलों से जुड़े हों, वे विषय उठाते नज़र नहीं आते और इस बात में सच्चाई लगती है कि अगर अख़बार या टेलीविजन ख़बर न दें, तो सांसद अपनी जानकारी का दायरा ही नहीं बढ़ाते.

एक जमाना था, जब संसद में मधु लिमये, जार्ज फर्नांडिस, नाथ पाई, भूपेश गुप्ता, ज्योतिर्मय बसु और राज नारायण जैसे सांसद हुआ करते थे. उन दिनों संसद में नौज़वान सांसदों में किशन पटनायक का भी जिक्र करना आवश्यक है, क्योंकि किशन पटनायक हमेशा पूरी तैयारी के साथ संसद में जाते थे. उन दिनों उन विषयों के ऊपर संसद में बहसें होती थी, जिनका रिश्ता देश की तकलीफों से, देश के दर्द से और देश के विकास से है. पक्ष और विपक्ष की बहसों का स्तर इतना ऊंचा होता था कि सांसद एक–दूसरे की जानकारी में कुछ न कुछ जोड़ते थे और देश को भी पता चलता था कि हमारी सचमुच हालत यह है. क्योंकि, ये सारे जितने नाम मैंने लिए, वे देश के हालात का खोजपरक विश्लेषण करते थे.

उन दिनों सांसद अपनी खुद की पार्टी का किस पूंजीपति से रिश्ता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय देश का किसमें फ़ायदा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देते थे. चंद्रशेखर जी ने जब राज्यसभा में बिड़ला के ख़िलाफ़ अभियान शुरू किया था, तो यह माना जाता था कि बिड़ला जी के पास संसद के अस्सी सांसदों का समर्थन है, जिन्हें वह हर महीने कुछ न कुछ उपहार दिया करते थे. कांग्रेस पार्टी का भी बिड़ला घराने से अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर जी ने बिड़ला के ख़िलाफ़ मामला उठाया. सांसदों का अध्ययन करना उन दिनों उनकी योग्यता मानी जाती थी. संसद के पुस्तकालय में अक्सर सांसद पुस्तक पढ़ते या जानकारी लेते हुए मिल जाते थे.

और एक आज का वक्त है, संसद की लाइब्रेरी में पत्रिकाएं पढ़ते हुए तो कुछ सांसद दिख जाते हैं, लेकिन गंभीर विषयों की जानकारी देने वाली पुस्तकें लगभग आलमारी में आराम फरमा रही होती हैं. हालत यह हो गई है कि बहुत सारे सांसदों को राष्ट्रगान तक नहीं याद है और जनता से जुड़े हुए सवाल याद करने का उनके पास वक्त नहीं है. इसका सीधा उदाहरण शून्यकाल के बाद लोकसभा और राज्यसभा का टीवी देखना है. संसद में सांसद उपस्थित नहीं रहते. संसद में क्या हो रहा है, उसमें हिस्सा नहीं लेते. उनकी न कोई अपनी राय होती है, न कोई अपना अध्ययन होता है. यह वह संसद है, जो 125 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का फ़ैसला करती है, क्योंकि संसद इस देश की सत्ता का सर्वोच्च न्यायालय है.

इस स्थिति में, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ख़िलाफ़ सरकार जा रही है और संसद खामोश है, इसका एक ही अर्थ निकलता है कि सांसदों को सुप्रीम कोर्ट की चिंता का भी नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी नहीं पता. और, देश में पिछले साढ़े पांच सालों से जिस तरह विदेशों के लिए सरकार के सहयोग से काम हो रहा है, उसके बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है, सांसदों को यह क्यों नहीं पता कि हमारे देश के सारे प्रमुख लोगों के राज, उनकी जानकारियां, उनकी कमजोरियां यानी सब कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों के पास पहुंचाने का काम पिछली सरकार ने भी किया और यह सरकार भी कर रही है? सांसदों को यह क्यों नहीं पता कि हमारे देश से जुड़ी एक–एक जानकारी हमारे पड़ोसी मुल्कों के पास पहुंच रही है और उसमें सरकार का सबसे बड़ा हाथ है? हमारे सांसद इतिहास में हुई अक्षम्य चूकों से कोई सबक नहीं लेते. उन्हें यह भी नहीं पता कि किस तरह हज़ारों लोगों की जानें इसी तरह के कामों की वजह से पहले जा चुकी हैं.

हम पिछले तीन सालों से आधार कार्ड को लेकर सरकार और देश को आगाह करते रहे हैं. इस चेतावनी का कोई अर्थ कांग्रेस सरकार ने नहीं समझा और न अब नरेंद्र मोदी की सरकार समझ रही है. हमारे देश का राज सूचना तंत्र के ज़रिये सबसे पहले चीन के पास पहुंचता है और आज की तारीख में चीन हमारा मित्र देश नहीं है. हमारे देश के संपूर्ण सूचना तंत्र के सर्वर चीन में हैं. हमारे देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सूचना तंत्र का लगा है, वह सारा चीन में बना है और हर एक में अगर कोई एक छोटा–सा जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाए, तो जो बातचीत प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्षों के बीच में हो रही है, वह बातचीत भी चीन के पास कंप्यूटर के ज़रिये पहुंच जाती है. दूसरी तरफ़ आधार कार्ड के ज़रिये इस देश के हर नागरिक की जानकारी अमेरिका के पास रोज पहुंच रही है और अमेरिका में बैठी हुई हिंदुस्तान को राजनीतिक रूप से कंट्रोल करने वाली इकाइयां उनका विश्लेषण कर रही हैं. दुर्भाग्य की बात है कि ये सारे काम भारत सरकार की राय से चल रहे हैं.

क्या इस संसद में एक भी ऐसा सांसद नहीं है, जो इस ख़तरे को भांप सकें? और, सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति के ऊपर तभी अपनी नज़र डाल पाता है, जब यह सवाल उसके सामने लाया जाए. सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल है, इसलिए उसने पहली टिप्पणी इस आधार कार्ड के विरोध में कर दी है और इसे अनिवार्य न बनाए जाने के बारे में कहा है. लेकिन, भारत सरकार हर जगह आधार कार्ड को अनिवार्य बना रही है. क्या मौजूदा सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की प्रशासनिक आदेशों के ज़रिये अवमानना कर रही है? अब इसका फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है. पर हां, सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं, जो देश के हित के ख़िलाफ़ सारी जानकारियां विदेशों को दे रहे हैं और वे जानकारियां पाकिस्तान व चीन जैसे देशों से ज़रूर शेयर हो रही होंगी, क्योंकि आजकल कंपनियां आंकड़े बेचती हैं. और, हमारे देश के हर नागरिक से संबंधित आंकड़े न केवल बाज़ार को नियंत्रण करने वाली कंपनियों के पास जा रहे हैं, ताकि वे आर्थिक रूप से हमें नियंत्रित कर सकें, बल्कि ये आंकड़े हमारे उन दुश्मनों के पास भी जा रहे हैं, जो हमारे यहां कार्रवाई करने की योजना बनाते हैं. इतना ही नहीं, ये आंकड़े उनके पास भी जा रहे हैं, जो देश

> **क्या इस संसद में एक भी ऐसा सांसद नहीं है, जो इस ख़तरे को भांप सकें? और, सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति के ऊपर तभी अपनी नज़र डाल पाता है, जब यह सवाल उसके सामने लाया जाए. सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल है, इसलिए उसने पहली टिप्पणी इस आधार कार्ड के विरोध में कर दी है और इसे अनिवार्य न बनाए जाने के बारे में कहा है. लेकिन, भारत सरकार हर जगह आधार कार्ड को अनिवार्य बना रही है. क्या मौजूदा सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की प्रशासनिक आदेशों के ज़रिये अवमानना कर रही है? अब इसका फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है. पर हां, सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं, जो देश के हित के ख़िलाफ़ सारी जानकारियां विदेशों को दे रहे हैं और वे जानकारियां पाकिस्तान व चीन जैसे देशों से ज़रूर शेयर हो रही होंगी, क्योंकि आजकल कंपनियां आंकड़े बेचती हैं.**

में हिंदू–मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं. और, अब उन्हें हिंदुस्तान में आकर कुछ नई खोज करने की ज़रूरत नहीं होगी. वे जहां हैं, वहीं बैठकर यह तय कर सकते हैं कि किस हिस्से को उन्हें अपना निशाना बनाना है.

भारत की महान संसद के महान सांसदो, आपके ऊपर इतिहास यह आरोप लगाएगा कि आपने इस देश को आर्थिक रूप से तो गुलाम बनवा ही दिया, बल्कि आपने इस देश के हर नागरिक की जानकारी विदेशों में आर्थिक कंपनियों और हमारे पड़ोसी देशों, जिनसे हमारे रिश्ते साफ़ नहीं हैं, को देकर एक तरह से देशद्रोह का काम किया है. मैं फिर आग्रह करता हूं लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से कि वे इस महत्वपूर्ण निहितार्थ को समझें और संसद में यह सवाल उठाएं कि आख़िर ये सारी चीजें जारी रहने के पीछे ताकतें कौन–सी हैं और इसे फौरन रोकने की बात करें. अगर आप नहीं रोकते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा, जब कोई यह कहने में हिचकिचाएगा नहीं कि हमारी संसद देशद्रोही है. ■

editor@chauthiduniya.com

क्या भाजपा मुंबई को शंघाई बना पाएगी ?

मेघनाद देसाई

बाल ठाकरे द्वारा मध्य मुंबई और फिर उत्तर व दक्षिण मुंबई में मराठियों का समर्थन जुटाने के साथ कांग्रेस अपना प्रभाव खोने लगी. राजनीति के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र फोर्ट से बदल कर परेल और लालबाग और फिर उत्तरी इलाका बनता चला गया. मुरली देवड़ा दक्षिण मुंबई में कांग्रेस की ताकत के अंतिम कड़ी थे. उन्होंने पैसे का प्रवाह हमेशा सुचारू रूप से बनाए रखा था. देवड़ा के मन में शीर्ष पद के लिए कोई लालसा नहीं थी. उनका अपना प्रभाव था और उन्हें उसे साबित करने के लिए किसी टॉप पोजीशन की ज़रूरत नहीं थी. वह एक बेहतरीन बॉम्बे वाला थे और भाषा उनकी लोकप्रियता में बाधा नहीं थी.

मुरली देवड़ा की मौत एक दु:खद घटना है. वह एक बेहतर राजनीतिज्ञ तो थे ही, साथ ही एक बहुत दयालु व्यक्ति भी थे. वह एक ऐसे कांग्रेसी नेता थे, जिन्हें अपने क्षेत्र और अपनी सीमा के बारे में पता था, उनकी जड़ें बहुत गहरी थीं. वह मुंबई में हर एक समुदाय से खुद को जोड़ सकते थे, लेकिन आम चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार ने राष्ट्रीय स्तर पर और मुंबई में पार्टी की किस्मत पर एक प्रश्नचिन्ह लगा दिया. बंबई पिछले 25 वर्षों में मुंबई बन गया है. यह सिर्फ़ नाम का एक परिवर्तन नहीं है, बल्कि राजनीति और संस्कृति का भी एक परिवर्तन है. एक समय था, जब यह बंबई था, द्वीप का आधा दक्षिणी हिस्सा राज्य और उसकी राजधानी को कमांड करता था. कांग्रेस ने हमेशा बंबई को अपने मजबूत गढ़ों में से एक माना. इसकी खुद की एक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी थी. बंबई में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और यहीं पर 1944 में गांधी–जिन्ना वार्ता हुई थी.

कांग्रेस ने बंबई के साथ अपना कनेक्शन बंबई के पैसे वालों और बुद्धिजीवियों के ज़रिये बढ़ाया. केएफ नरीमन को अब एक पर्यटक बिंदु से अधिक और किसी रूप में नहीं जाना जाता है, लेकिन उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कांग्रेस का नेतृत्व किया था. एक पारसी रूप में उन्होंने बंबई की महानगरीय संस्कृति का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया था. प्रतिष्ठित बैरिस्टर भूला भाई देसाई मुंबई कांग्रेस के एक और स्तंभ थे. पारसियों, वकीलों, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों का संयोजन ही मुंबई में कांग्रेस की ताकत थी. मुख्य रूप से गुजराती और पारसी ही थे और साथ में एसके पाटिल, जिनके सहारे कांग्रेस बंबई के मराठीभाषी समुदाय में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकी. इसके अलावा इन लोगों ने अपने व्यवसाय को भी ऊंचाई तक पहुंचाया. पाटिल ने फिल्म उद्योग से भी (जो तब तक बॉलीवुड नहीं कहा जाता था) अपनी दोस्ती बढ़ाई. यह उद्योग तब चेंबूर एवं अंधेरी में स्टूडियो के साथ जुहू एवं बांद्रा में फल–फूल रहा था. नेहरू जब लोकसभा में वीके कृष्ण मेनन को लाना चाहते थे, तब उत्तर बंबई निर्वाचन क्षेत्र में उनके लिए फिल्मी सितारों ने प्रचार–प्रसार किया था.

फिर भी, कांग्रेस की पकड़ तबसे ढीली होनी शुरू हुई, जब पंडित जवाहर लाल नेहरू संयुक्त महाराष्ट्र की मांग को बल नहीं दे पाए. 1957 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुक़सान उठाना पड़ा, तबसे उसने अपने नेतृत्व का महानगरीय चेहरा छोड़ना शुरू कर दिया और मराठी बोलने वाले नेताओं को आगे लाना शुरू किया. मोरारजी देसाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया गया. कांग्रेस भाग्यशाली थी कि उसे एक बौद्धिक नेता वाईबी चव्हाण मिले और बाद में शरद पवार जैसे नेता लाइन में थे, लेकिन कांग्रेस के पास बंबई में कोई जननेता नहीं था. उसके मुख्यमंत्रियों की ताकत बंबई की बजाय राज्य के सुदूर इलाकों में थी. बंबई सिर्फ़ एक कैश काउ (पैसे देने वाली जगह) बनकर रह गई थी.

> **शिवसेना ने दक्षिण मुंबई की उपेक्षा करके मुंबई में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया. दरअसल, उसने (कांग्रेस) एंटी बॉम्बे व्यवहार किया, जब वह महाराष्ट्र में शासन कर रही थी. 26/11 की घटना हुई दक्षिणी बॉम्बे में, जो महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री के लिए कम जानकारी वाला क्षेत्र था. बंबई ने महसूस किया कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने उसे छोड़ दिया है.**

बाल ठाकरे द्वारा मध्य मुंबई और फिर उत्तर व दक्षिण मुंबई में मराठियों का समर्थन जुटाने के साथ कांग्रेस अपना प्रभाव खोने लगी. राजनीति के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र फोर्ट से बदल कर परेल और लालबाग और फिर उत्तरी इलाका बनता चला गया. मुरली देवड़ा दक्षिण मुंबई में कांग्रेस की ताकत के अंतिम कड़ी थे. उन्होंने पैसे का प्रवाह हमेशा सुचारू रूप से बनाए रखा था. देवड़ा के मन में शीर्ष पद के लिए कोई लालसा नहीं थी. उनका अपना प्रभाव था और उन्हें उसे साबित करने के लिए किसी टॉप पोजीशन की ज़रूरत नहीं थी. वह एक बेहतरीन बॉम्बे वाला थे और भाषा उनकी लोकप्रियता में बाधा नहीं थी. वह बेहतरीन बंबइया भाषा बोलते थे, जिसे कई भाषाओं को एक साथ मिलाकर बनाया गया है.

> **कांग्रेस ने बंबई के साथ अपना कनेक्शन बंबई के पैसे वालों और बुद्धिजीवियों के ज़रिये बढ़ाया. केएफ नरीमन को अब एक पर्यटक बिंदु से अधिक और किसी रूप में नहीं जाना जाता है, लेकिन उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कांग्रेस का नेतृत्व किया था. एक पारसी रूप में उन्होंने बंबई की महानगरीय संस्कृति का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया था.**

शिवसेना ने दक्षिण मुंबई की उपेक्षा करके मुंबई में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया. दरअसल, उसने (कांग्रेस) एंटी बॉम्बे व्यवहार किया, जब वह महाराष्ट्र में शासन कर रही थी. 26/11 की घटना हुई दक्षिणी बॉम्बे में, जो महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री के लिए कम जानकारी वाला क्षेत्र था. बंबई ने महसूस किया कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने उसे छोड़ दिया है. बंबई को शंघाई बनाने के सपने पर यूपीए या महाराष्ट्र में कांग्रेस–राकांपा गठबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया. यह उम्मीद करना कुछ ज़्यादा ही होगा कि नई सरकार दक्षिण बंबई के व्यापार और वित्तीय केंद्र को पुनर्जीवित करने को लेकर बहुत कुछ करेगी. दिल्ली और मुंबई की तस्वीर बताती है कि कैसे बंबई कांग्रेस के लिए एक सौतेला बच्चा है. क्या भाजपा कुछ बेहतर करेगी? ■

feedback@chauthiduniya.com

कैसे रखें डायबिटीज पर नियंत्रण

मोनिशा भटनागर

डायबिटीज (मधुमेह) दीर्घकालीन रोग है जो अग्न्याशय(पैंक्रियास) के पर्याप्त इन्सुलिन ना बनाने या शरीर के अपने द्वारा उत्पादित इन्सुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाने के कारण होता है. दोनों ही परिस्थितियों में शरीर में ग्लूसकोज (ब्लड शुगर) की मात्रा बढ़ जाती है. इन्सुलिन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन है, जिसमें असंतुलन के कारण व्यक्ति डायबिटिक बन जाता है. डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति का पूरी तरह से ठीक हो पाना असंभव है, लेकिन यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इससे होने वाले दुष्परिणामों से बचाव किया जा सकता है. डायबिटीज का निदान ब्लड टेस्ट द्वारा रक्त में ग्लूकोस की जांच द्वारा आसानी से किया जा सकता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार डायबिटीज एशिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरी है. अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार, भारत में वर्तमान समय में 6.5 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं. तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आधुनिक युग की समस्याएं व तनाव, अचानक खानपान व रहन–सहन में आये परिवर्तन और शारीरिक श्रम की कमी के कारण डायबिटीज हमारे देश में तेजी से बढ़ रही है.

डायबिटीज के प्रकार

टाइप 1 डायबिटीज

टाइप 1 डायबिटीज बचपन में या किशोर अवस्था में अचानक इन्सुलिन के उत्पादन की कमी होने से होती है. इसमें इन्सुलिन हॉर्मोन बनना पूरी तरह बंद हो जाता है. ऐसे में शरीर में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को कंट्रोल करने के लिए रोज़ इन्सुलिन के इंजेक्शन की जरूरत होती है. इस प्रकार की डायबिटीज पर नियंत्रण के लिए इन्सुलिन लेने के अलावा कोई तरीका नहीं है. टाइप 1 डायबिटीज का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है. इसका निवारण करने के लिए अनुसंधान पूरी दुनिया में जारी है. यह सबसे अधिक बच्चों में देखी जाती है, और इसके लक्षण अचानक दिखने लगते हैं. इसके कुछ प्रमुख लक्षण है वजन में कमी आना, निरंतर भूख लगना, अधिक प्यास और अधिक पेशाब लगना, दृष्टि में परिवर्तन और लगातार थकान रहना. इससे पीड़ित बच्चों को नियमित व नियंत्रित आहार, इन्सुलिन की डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज़ नियमित रूप से लेना, रक्त ग्लूकोज वैल्यू की नियमित जांच और शरीर के किसी भी अंग में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना अति आवश्यक हैं.

टाइप 2 डायबिटीज

टाइप 2 डायबिटीज शरीर द्वारा उसमे बन रहे इन्सुलिन के अप्रभावी उपयोग के कारण होती है. दुनियाभर में डायबिटीज के 90 फीसदी मरीज इसी श्रेणी में आते हैं. इसके होने का सबसे बड़ा कारण अधिक वजन यानि मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता देखा गया है. हालांकि यह कई बार अनुवांशिक भी होती है, लेकिन मोटापा इसके खतरे को लगभग 80–85 प्रतिशत तक बढ़ा देता है. भागदौड़ भरी जीवनशैली और काम के दबाव से बढ़ते तनाव और उच्च रक्त चाप को भी डायबिटीज के प्रमुख कारणों में देखा जा रहा है. धूम्रपान व शराब इत्यादि का अधिक सेवन भी इसके खतरे को दो गुना बढ़ा देता है. इसके भी प्रमुख लक्षण टाइप 1 डायबिटीज जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें लक्षण देर से दिखने और कम चिन्हित होने के कारण, इस बीमारी का निदान बीमारी होने के काफी साल बाद तक हो पाता है. इसके लक्षणों में वजन में कमी आना, अधिक भूख, प्यास व पेशाब लगना, थकान, पिडंलियो में दर्द, देरी से घाव भरना, और हाथ–पैरों में झनझनाहट रहना शामिल हैं. इसे व्यायाम, संतुलित भोजन और दवाओं से नियंत्रण में रखा जा सकता है. इसमें टाइप 1 डायबिटीज तरह इन्सुलिन के इंजेक्शन लेना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन यदि यह उपरोक्त तरीकों से नियंत्रण में नहीं आती तो डॉक्टर के कहे अनुसार इन्सुलिन भी लेनी पड़ सकती है.

डायबिटीज शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करती है. हार्ट(दिल), किडनी(गुर्दा), आंखें, नसें और ब्लड वेसल्स आदि इस रोग से सबसे अधिक और गंभीर रूप से प्रभावित होतें हैं. दिल की बीमारी जैसे हार्ट अटैक या एंजाइना का खतरा डायबिटीज के कारण काफी बढ़ जाता है, और अनियंत्रित डायबिटीज के मरीजों में अक्सर 65 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते दिल के दौरे की समस्या होने की आशंका प्रबल हो जाती है. इसके अलावा रीनल फेलियर यानि गुर्दो की कार्यहीनता डायबिटीज से होने वाले प्रमुख दुष्प्रभावों में से एक है. आंखों में समय से पूर्व मोतिया बनना, पर्दे की खराबी(रेटिनापैथी) व अधिक खराबी होने पर अंधापन भी अनियंत्रित डायबिटीज का ही परिणाम है.

डायबिटीज का असर

डायबिटीज शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करती है. हार्ट(दिल), किडनी(गुर्दा), आंखें, नसें और ब्लड वेसल्स आदि इस रोग से सबसे अधिक और गंभीर रूप से प्रभावित होतें हैं. दिल की बीमारी जैसे हार्ट अटैक या एंजाइना का खतरा डायबिटीज के कारण काफी बढ़ जाता है, और अनियंत्रित डायबिटीज के मरीजों में अक्सर 65 साल की उम्र तक पहुंचते–पहुंचते दिल के दौरे की समस्या होने की आशंका प्रबल हो जाती है. इसके अलावा रीनल फेलियर यानि गुर्दो की कार्यहीनता डायबिटीज से होने वाले प्रमुख दुष्प्रभावों में से एक है. आंखों में समय से पूर्व मोतिया बनना, पर्दे की खराबी(रेटिनापैथी) व अधिक खराबी होने पर अंधापन भी अनियंत्रित डायबिटीज का ही परिणाम है. चेहरे या पैरो में सूजन व पैरो का सन्न होना या गैन्ग्रीन और घावों का लंबे समय तक ना भरना भी डायबिटीज के परिणाम हैं. इससे बचने के लिए ग्लूकोज (ब्लड शुगर) स्तर नियंत्रण में रखने के साथ–साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और तनाव पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है.

डायबिटीज पर नियंत्रण

रक्त में ग्लूकोस की मात्रा को कम करने या नियंत्रित रखने के लिए उपयुक्त भोजन व व्यायाम अत्यंत आवश्यक है. चीनी, गुड़, घी, तेल, व इन वस्तुओं से बनी खाने की चीज़ें जैसे पराठे, आइसक्रीम, मिठाई, मांस, अंडा, चॉकलेट आदि का सेवन बहुत सीमित मात्रा में या डॉक्टर के कहे अनुसार बिल्कुल नहीं करना चाहिए. डायबिटीज रोगियों के लिए सब्ज़ियों में मेथी, पालक, करेला, बथुआ, सरसों का साग, सोया का साग, सीताफल, ककड़ी, तोरई, टिंडा, शिमला मिर्च, भिंडी, सेम, शलजम, खीरा, ग्वार की फली, चने का साग और गाजर आदि का सेवन अच्छा रहता है. ताजा शोध के अनुसार खाने में नियमित रूप से दही का सेवन करने से भी टाइप 2 डायबिटीज में मदद मिल सकती है. इसके अलावा भोजन का समय निश्चित होना चाहिए और लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिये. डायबिटीज के रोगियों को हर 2–3 घंटे या डॉक्टर के बताये समय अंतराल पर कुछ न कुछ पौष्टिक खाना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज की दवाई वे कम मीठा खाने के कारण कई बार लंबे समय तक भूखे रहने पर शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया यानि रक्त में ग्लूकोज की असामान्य कमी या लो ब्लड शुगर हो सकती है, जिससे चक्कर, बेहोशी आदि आ सकती है. यह भी डायबिटीज के रोगी के लिए खतरनाक है. रोगी की भोजन की मात्रा डॉक्टर द्वारा रोगी के वजन व कद के हिसाब से कैलोरीज की गणना करके निर्धारित की जाती है.

करेला, मेथी दाना आदि घरेलू नुस्खों से कुछ रोगियों को थोड़ा फायदा होता है, लेकिन ऐसे में इन्ही पर निर्भर रहना और दवाओ का उपयोग करना छोड़ देना खतरनाक है. यह सही है कि नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली से डायबिटीज को नियंत्रण में रखा जा सकता है, परन्तु यह केवल गलतफहमी है की इससे डायबिटीज ठीक हो जाती है. प्रचलित बातों पर बिना डॉक्टर से सलाह किये विश्वास कर दवाइयों का सेवन करना छोड़ देना रोगी के लिए घातक भी साबित हो सकता है.

डायबिटीज पर नियंत्रण रखने का दूसरा पहलू है व्यायाम. प्रतिदिन लगभग 20 से 40 मिनट तेज चलना, तैरना, साइकिल चलाना आदि शरीर को स्वस्थ रखने में कारगर है, पर पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका शरीर व्यायाम करने योग्य है कि नहीं है. डायबिटीज की समस्या से पार पाने के लिए भोजन में उपयुक्त परिवर्तन व उचित व्यायाम और दृढ़ संकल्प जरूरी है.

संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ– साथ कुछ और जरूरी सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता है. जैसे नियमित रूप से शुगर स्तर की जांच, दवाओं का डॉक्टर के निर्देशानुसार नियमित सेवन, किसी भी तरह के घाव का तुरंत इलाज, वजन पर नियंत्रण, पैरों की अधिक देखभाल, धूम्रपान व मदिरापान का त्याग और हमेशा अपने पास कुछ मीठी एवं खाने की वस्तु रखना.

अभी तक डायबिटीज का कोई भी स्थाई उपचार नहीं है. स्वस्थ जीवनशैली और मोटापे से दूर रहकर डायबिटीज जैसी बीमारी से बचा जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

पाउलिन कुशमैन जासूसी की मिसाल

अरुण तिवारी

अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से कई महिलाओं को जासूसी के काम पर लगाया गया था. दोनों ही तरफ नेता खुफिया खबरें पाने के लिए खूबसूरत महिलाओं का इस्तेमाल किया करते थे. इसके पहले हम आपको बेले बॉयड के बारे मर्ें बता चुके हैं. जिन्होंने गृह युद्ध के दौरान सात राज्यों की तरफ से जासूसी की थी जिन्होंने अमेरिका के संघ से अलग होकर एक नया देश बना लिया था. बेले ने इन राज्यों की काफी मदद की थी जिसी वजह से इनकी कई जगहों पर जीत भी हुई थी. इस अंक में हम आपको एक ऐसी महिला जासूस के बारे में बताएंगे जिन्होंने अखंड अमेरिकी संघ की तरफ से जासूसी की थी. उनका नाम है पाउलिन कुशमैन.

पाउलिन का जन्म न्यू ऑरलियंस, लुसियाना में 10 जून 1833 को हुआ था. पाउलिन का जन्म के समय नामकरण हैरियट किया गया था. पाउलिन नाम उन्होंने बाद में अपनाया. वे नेपोलियन बोनापार्टे की रिश्तेदार थीं. उनकी मां फ्रांस की रहने वाली थीं और पिता स्पेन के व्यापारी थे. पाउलिन और छह भाईयों की शुरुआती परवरिश अमेरिका के मिशिगन में हुई. पाउलिन बचपन से दूसरों की मदद करने वाले स्वभाव की थीं. उन्हें लोगों की मदद करके सुकून मिलता था. जब वे मिशिगन में रहती थीं तो अपने घर का दरवाजा आस-पास रहने वाले आदिवासी बच्चों के लिए खोल दिया करती थीं जिससे वे बच्चे आराम से खेल सकें. 1851 में वे अपने गृहनगर लुसियाना वापस लौट गईं. यहां पर उन्होंने एक थियेटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया. इस ग्रुप का नाम था न्यू ओरलियंस वेरायटीज. बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क की तरफ का रुख किया और अपना स्टेज नाम पाउलिन कुशमैन धारण किया.

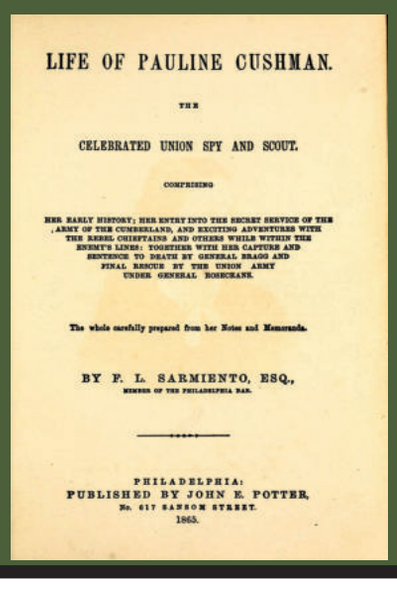

LIFE OF PAULINE CUSHMAN.

THE

CELEBRATED UNION SPY AND SCOUT.

COMPRISING

HER EARLY HISTORY; HER ENTRY INTO THE SECRET SERVICE OF THE ARMY OF THE CUMBERLAND, AND EXCITING ADVENTURES WITH THE REBEL CHIEFTAINS AND OTHERS WHILE WITHIN THE ENEMY'S LINES: TOGETHER WITH HER CAPTURE AND SENTENCE TO DEATH BY GENERAL BRAGG AND FINAL RESCUE BY THE UNION ARMY UNDER GENERAL ROSECRANS.

The whole carefully prepared from her Notes and Memoranda.

BY F. L. SARMIENTO, ESQ.,

MEMBER OF THE PHILADELPHIA BAR.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY JOHN E. POTTER,

No. 617 SANSOM STREET.

1865.

इसी दौरान जब वे एक शो में परफॉरमेंस देने के बाद उन्हें दो कॉनफेडरेड (विद्रोही राज्य) व्यक्तियों की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया कि कॉनफेडेरट प्रेसिडेंट जेफरसन डेविसाफ्टर से मुलाकात करें. उन्हें कॉनफेडरेट प्रेसिडेंट से मिलने के लिए थियेटर ग्रुप से निकाल दिया गया. यहां पर थियेटर ग्रुप से एक भूल हो गई थी जिससे थियेटर ग्रुप के मालिक वाकिफ नहीं थे. दरअसल पाउलिन के दिमाग में यह योजना चल रही थी कि वह कॉनफेडरेट नेताओं से घुलमिल जाएंगी और उनकी सारी खुफिया सूचनाओं की जानकारी यूनियन सरकार को देंगी. लेकिन यह सब किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की.

इसके बाद भी पाउलिन ने अपने प्रयास नहीं छोड़े. इस दौरान उन्होंने कई बार कॉनफेडेरेट अधिकारियो से मुलाकात की और उनके कई गोपनीय दस्तावेज भी चुपके से हथिया लिए. इस बात की जानकारी कॉनफेडेरेट अधिकारियों को लग गई. उन्हें गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई गई. ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें सजा दी जाने वाली थी उसके तीन दिन पहले ही यूनियन की सेनाओं ने हमला करके उन्हें बचा लिया. इसके बाद यूनियन के लिए पाउलिन अपनी सेवाएं देती रहीं. यही नहीं उन्होंने कई ऐसी गोपनीय जानकारियां जिनकी वजह से यूनियन की सेनाओं को जीत हासिल करने में आसानी हुई. बाद में उन्हें मेजर के पद से भी नवाजा गया और उन्हें मेजर पाउलिन भी कहा जाता था.

पाउलिन उस समय इतनी मशहूर हो चुकी थीं कि उन्हें पी टी बारनम ने उनकी तस्वीर को अपने संग्रहालय में जगह दी. बारनम का अमेरिका में संग्रहालय था. पाउलिन के बारे में एक बात और मशहूर है कि उनकी गुप्त गतिविधियों की वजह से ही उनके जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती है. लेकिन ऐसा माना जाता है कि गृह युद्ध के समय में पाउलिन अमेरिकी यूनियन की सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जासूसों में से एक थीं जो सरकार को हर उस बात से अवगत कराती थीं, जो महत्वपूर्ण होती थी. हालांकि उनके एक फर्डिनेंड सारमिंटो ने उनकी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ पाउलिन कुशमैन: द सेलेब्रेटेड यूनियन स्पाई एंड स्काउट. उन्होंने बीमारी की वजह से अपने बच्चे को खो दिया. उन्होंने 1872 मे ं दूसरी शादी की लेकिन एक साल के भीतर ही विधवा हो गईं. सूत्रों के अनुसार उन्होंने 1979 में तीसरी बार शादी की और अपने पति के साथ मिलकर होटल का कारोबार शुरू कर दिया.

उनकी मौत साठ वर्ष की अवस्था में हुई. उनकी मौत के समय पूरा सम्मान दिया गया और गृहयुद्ध में उनके प्रयासों की प्रशंसा की गई. उस समय अमेरिकी सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि कुशमैन अमेरिकी इतिहास की सबसे अच्छी जासूसों में से एक थीं और उन्हे उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा.■

अमेरिकी रक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा

युद्ध के मैदान में वापसी का संकेत

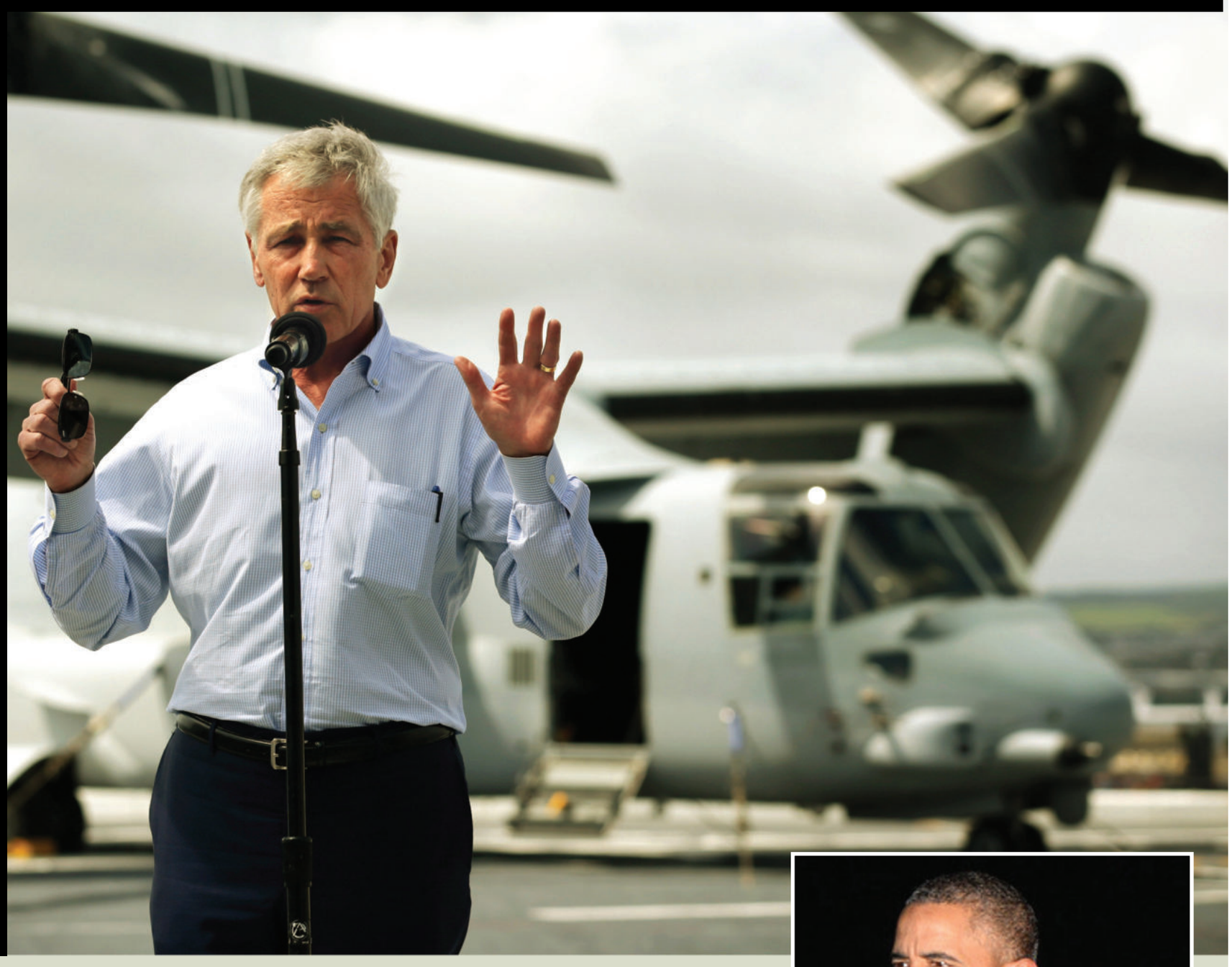

अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया. इसके बाद माहौल कुछ ऐसा बनाया गया कि उन्होंने अपनी मर्जी से पद छोड़ा है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि ओबामा ने ही उनसे इस्तीफ़ा लिया है. कुछ दिनों पहले संपन्न हुए मध्यावधि चुनाव में ओबामा की पार्टी (डेमोक्रेट्स) की हार के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि ओबामा प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी की विदाई हो सकती है. हेगल का इस्तीफ़ा काफी चौंकाने वाला रहा. अब हेगल के इस्तीफ़े को ओबामा की विदेश नीति के यू-टर्न और युद्ध के मैदान में अमेरिका की वापसी के रूप में देखा जा रहा है.

नवीन चौहान

अमेरिका 9/11 के हमले के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ रहा है. पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, साल 2014 के आख़िरी दिनों में अमेरिकी सेना की वापसी होनी थी. इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वियतनाम युद्ध में भाग ले चुके रिपब्लिकन पार्टी के चक हेगल को डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया और उन्हें अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी की ज़िम्मेदारी दी. इसके साथ ही उनसे रक्षा बजट दुरुस्त करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से हेगल और राष्ट्रपति ओबामा के बीच मतभेद गहरा गए थे. हेगल ने सीरिया में अमेरिकी नीति का विरोध किया था. सीरिया में ओबामा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुज़ैन राइस को एक पत्र लिखकर कहा था कि राष्ट्रपति ओबामा को सीरिया के राष्ट्रपति बसर-अल-असद के संबंध में अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए. इस वजह से हम कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमें किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए. धीरे-धीरे सीरिया में आईएसआईएस की पकड़ मजबूत होती गई. इस ढिलाई के लिए ओबामा ने हेगल को ज़िम्मेदार माना और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया.

राष्ट्रपति बनने के बाद ओबामा स्वयं को पीस प्रेसिडेंट के रूप में स्थापित करना चाहते थे. ओबामा एक ऐसा राष्ट्रपति बनना चाहते थे, जो अमेरिका और दुनिया में शांति लेकर आए. वह चाहते थे कि मध्य एशिया में जहां कहीं भी अमेरिकी सेना है, वह उनका कार्यकाल ख़त्म होने से पहले स्वदेश लौट आए, जिससे देश पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो, साथ ही युद्ध में मारे जाने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या में भी कमी आए. इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने चक हेगल को डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया था. उन्होंने इसके लिए एक रिपब्लिकन को इसलिए भी चुना, ताकि उन्हें इस काम में विपक्षी दल (रिपब्लिकन पार्टी) का समर्थन मिल सके. इराक के अनुभव के बाद अमेरिका में एक गुट इस बात तो लेकर नाराज़ था कि जिस तरह इराक से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद इराकी सैनिक आईएसआईएस का मुक़ाबला नहीं कर सके, कहीं वही स्थिति अफगानिस्तान में भी उत्पन्न न हो जाए. आईएसआईएस के इराक में युद्ध छेड़ने के बाद से ही मध्य एशिया के हालात ठीक नहीं हैं. ऐसे में, वहां से वापसी का निर्णय सही नहीं है.

जब मध्य और पश्चिम एशिया में उठापटक मची हुई है, ऐसे में हेगल की डिफेंस सेक्रेटरी पद से विदाई होना इस बात का संकेत है कि अमेरिकी विदेश नीति की ओवरहॉलिंग हो रही है. खासकर, मध्य और दक्षिण एशिया के संबंध में निर्णायक बदलाव हो रहे हैं. ये बदलाव क्या हैं, कब होंगे और किस तरह लागू होंगे, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बदलाव की बात इससे साबित होती है कि ओबामा ने हाल में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के बने रहने के संबंध में एक खुफिया आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. इस खुफिया आदेश में कहा गया है कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस नहीं जा रही है. फिलहाल 9,800 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में बने रहेंगे. मई 2014 के एक आदेश के अनुसार, अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान में ज़मीनी ऑपरेशन करने पर एक तरह से पाबंदी थी. उन्हें केवल आपातकालीन स्थितियों में ही ज़मीन पर आतंकवादियों से मुक़ाबला करने की छूट थी. लेकिन, खुफिया आदेश के अनुसार, साल 2015 के लिए ओबामा ने एक बार फिर से अमेरिकी सेना को ज़मीनी कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है. इसका सीधा-सा मतलब है कि अफगानिस्तान, सीरिया और ईराक सहित मध्य एशिया के बहुत सारे शहरों में एक बार फिर खूनी खेल शुरू होने वाला है. ओबामा की पीस पॉलिसी असफल हो गई है. पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत साल 2014 के अंत में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी होनी थी, जो अब 2016 तक के लिए टल गई है.

ओबामा की पीस पॉलिसी की वजह से ही इराक से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद आईएसआईएस ने वहां कब्जा कर लिया और वह अलकायदा की तरह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया. सीरिया और इराक में आईएसआईएस का खूनी खेल रोकने में डिफेंस सेक्रेटरी नाकाम हो गए. उनका इस्तीफ़ा इसी असफलता का नतीजा है. आईएसआईएस को लेकर व्हाइट हाउस का सीधा आदेश था कि कीप द प्रोफाइल लो एंड किल देम (उन्हें सिर उठाने न दें और ख़त्म कर दें). लेकिन हुआ इसके ठीक उलट. डिफेंस सेक्रेटरी ने आईएसआईएस को हाइलाइट कर दिया और इस बात का प्रचार किया कि हम उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं. इससे उनके हौसले और बुलंद हो गए. एक साक्षात्कार में हेगल ने कहा कि आईएसआईएस दुनिया का सबसे अमीर, अत्याधुनिक, समर्पित और क्रूर आतंकवादी संगठन है. जहां ओबामा की पॉलिसी डिग्रेड एंड डिस्ट्रॉय थी, वह उसे अपग्रेड एंड एक्सिलेंस पर ले आए और उसे (आईएसआईएस) पनपने व बढ़ने का मौक़ा दिया.

ओबामा ने खुफिया तरीके से एक आदेश पर हस्ताक्षर करके अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की भूमिका बढ़ा दी है. इसके पहले अफगानिस्तान में अशरफ घानी के नेतृत्व में नई सरकार के साथ अमेरिका का समझौता हुआ था. इस मिशन को ऑपरेशन रिसॉल्यूट सपोर्ट नाम दिया गया. समझौते के अनुसार, साल 2015 तक 9,800 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में बने रहेंगे. 2015 के अंत में उनमें से आधे अमेरिकी सैनिक स्वदेश वापस रवाना हो जाएंगे. साल 2016 के अंत में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा के लिए आवश्यक सैनिकों को छोड़कर अन्य सभी वापस लौट जाएंगे. इस मिशन का उद्देश्य तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों के ख़िलाफ़ अफगानिस्तानी सैन्य बलों की सहायता करना है. हालांकि, अफगानिस्तानी सैन्य बलों को देश की सुरक्षा का पूरा अधिकार होगा. आने वाले समय में उन्हें नाटो के ज़रिये हथियार व प्रशिक्षण देकर और मजबूत बनाया जाएगा. नए आदेश में अमेरिकी जेट बॉम्बर और ड्रोन के ज़रिये अफगान कॉम्बैट मिशनों को हवाई समर्थन देने की अनुमति दी गई है. हवाई हमले करने के नियम भी आसान बना दिए गए हैं. अमेरिकी सैनिकों को आपातकालीन स्थिति में ही ज़मीनी लड़ाई लड़नी पड़ती, लेकिन हेगल द्वारा इस्तीफ़ा देने के बाद ओबामा ने जो आदेश दिए हैं, उनसे हवाई हमलों में तो निश्चित तौर पर इजाफा होगा.

इराक के अनुभवों से यह जाना जा सकता है कि अफगानिस्तान को छोड़ना अमेरिका के लिए कितना घातक हो सकता है. इराक में अमेरिका ने सेना तो बनाई, उसे ट्रेनिंग भी दी, लेकिन ऐसा नेटवर्क स्थापित नहीं किया, जिससे पूरे देश को नियंत्रित और निर्देशित किया जा सके. अमेरिकी सेना जैसे ही इराक से हटी, वहां आतंकवादी काबिज हो गए. सरकार केवल नाम मात्र की रह गई. देश के अधिकांश हिस्से आतंकवादियों की चपेट में आ गए. अब ओबामा को यह डर सता रहा है कि कहीं अफगानिस्तान से वापस जाते ही वहां भी इराक जैसी स्थिति न हो जाए. कहीं वहां फिर से अलकायदा या आईएसआईएस का कब्जा न हो जाए. इसलिए मजबूरन ओबामा को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा. अब नीतियों में जो बदलाव हुआ है, उससे वॉर प्रेसिडेंट वॉपरियर प्रेसिडेंट बन जाएंगे. अब वह जॉर्ज बुश की तरह एक निर्दयी और दुर्दांत युद्ध में जाने वाले हैं. खुफिया दस्तावेज़ में इस बात का भी जिक्र है कि आईएसआईएस को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए किस तरह के हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

अमेरिकी नीति में बदलाव से सीधे तौर पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान प्रभावित होने वाले हैं. अफगानिस्तान से अमेरिका के लौटने की ख़बर से पाकिस्तान इस मुगालते में था कि अमेरिका के जाते ही वह सेना, आईएसआई और तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा. और, उसे एक बार फिर अपने प्रभाव वाले क्षेत्र (एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस) में बदल देगा. लेकिन, ओबामा के खुफिया दस्तावेज़ के ज़रिये अमेरिकी सेना को इस बात का ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि चाहे जैसे भी हो, आईएसआईएस का ख़ात्मा किया जाए. अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी. अमेरिकी सेना की मौजूदगी और उसके द्वारा सुरक्षा देने की वजह से भारत की पकड़ मजबूत रहेगी और पाकिस्तान किनारे होता चला जाएगा. अमेरिकन प्रेजेंस का मतलब यह है कि जब तक वह यानी अमेरिका अफगानिस्तान में रहेगा, तब तक अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों में ड्रोन हमले करता रहेगा. अमेरिका की वजह से भारत और इजरायल की नज़दीकियां भी बढ़ेंगी. इसके संकेत भी अभी से दिखाई पड़ने लगे हैं. भारत ने हाल में इजरायल के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा किया है.

अफगानिस्तान एक बार फिर से युद्ध के मैदान में तब्दील होने वाला है. कुल मिलाकर अमेरिकी विदेश नीति में मूलभूत परिवर्तन आ गया है. इस वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत एवं ईरान आदि के साथ उसके नीतिगत और कूटनीतिक रिश्ते बदलने वाले हैं. आतंकवाद के ख़ात्मे के नाम पर एक नया गठजोड़ होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका एक बार फिर से आक्रामक भूमिका में होगा. इजरायल और भारत भी उसका सहयोग करेंगे, लेकिन यह सहयोग अप्रत्यक्ष ही रहेगा. अमेरिका के साथ इस नई योजना में सऊदी अरब और तुर्की भी होंगे. इस नई योजना को कार्यान्वित करने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. ■

navinonline2003@chauthiduniya.com

कालान्तर में कन्हार गांव में आदिवासियों द्वारा पुजित प्रतिमा जो उनकी सामर्थ्य के अनुसार छोटे मंदिर में स्थापित थी. उसे अविभाजित मिर्जापुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने क्षेत्र पंचायत के पूर्व प्रमुख पंडित ठाकुर प्रसाद तिवारी के प्रयास से घोरावल के प्रख्यात देवस्थान पर लाकर जनभावना के अनुसार भव्य मंदिर का निर्माण कर जगतगुरू शंकराचार्य जी की मौजूदगी में इसमें पुन: प्राण प्रतिष्ठा कराया.

साई बाबा मुक्तिदाता हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

बालाराम मानकर नामक एक गृहस्थ साई बाबा के परम भक्त थे. जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो वो बड़े निराश हो गए और सब घरबार अपने लड़के को सौंप वे शिरडी में आकर बाबा के पास रहने लगे. उनकी भक्ति देखकर बाबा उनके जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने उन्हें बारह रुपये देकर मच्छंद्रगढ़ (जिला सातार) में जाकर रहने को कहा. मानकर की इच्छा उनका सानिध्य छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने की न थी, लेकिन बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्याणार्थ ही मैं यह उत्तम उपाय तुम्हें बतलाता रहा हूं. इसलिए वहां जाकर दिन में तीन बार प्रभु का ध्यान करो . बाबा के शब्दों पर विश्वास कर वह मच्छंद्रगढ़ चला गया और वहां के मनोहर दृश्यों, शीतल जल तथा उत्तम पवन और समीपस्थ दृश्यों को देखकर उसके चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई. बाबा द्वारा बतलाई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना प्रारम्भ कर दिया और कुछ दिनों पश्चात ही उसे दर्शन प्राप्त हो गया. बहुधा भक्तों को समाधि में ही दर्शन होते है. दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहां भेजने का कारण पूछा. बाबा ने कहा कि शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प-विकल्प उठने लगे थे. इसी कारण मैंने तुम्हें वहां भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो. तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में ही विघमान हूं और साढ़ेतीन हाथ के इस पंचतत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ नहीं हूं, लेकिन अब तुम मुझे देखकर यह धारणा बना लो कि जो तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित है और जिसके तुमने दर्शन किए. वह दोनों अभिन्न हैं या नहीं. मानकर वह स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान बांद्रा को रवाना हो गया. वह पूना से दादर रेल द्वारा जाना चाहता था. लेकिन जब वह टिकट-घर पर पहुंचा तो वहां अधिक भीड़ होने के कारण वह टिकट खरीद न सका. इतने में ही एक देहाती, जिसके कंधे पर एक कंबल पड़ा था तथा शरीर पर केवल एक लंगोटी के अतिरिक्त कुछ न था, वहां आया और मानकर से पूछने लगा कि आप कहां जा रहे हैं. मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूं. तब वह कहने लगा कि मेरा यह दादर का टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहां एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मेरा जाना आज न हो सकेगा. मानकर को टिकट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी जेब से वे पैसे निकालने लगे. इतने में ही टिकट देने वाला आदमी भीड़ में कहीं अदृश्य हो गया. मानकर ने भीड़ में पर्याप्त छानबीन की, लेकिन सब व्यर्थ ही हुआ. जब तक गाड़ी नहीं छूटी, मानकर उसके लौटने की ही प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वह अन्त तक न लौटा. इस प्रकार मानकर को इस विचित्र रुप में द्वितीय बार दर्शन हुए. कुछ दिन अपने घर ठहरकर मानकर फिर शिरडी लौट आया और श्रीचरणों में ही अपने दिन व्यतीत करने लगा. अब वह सदैव बाबा के वचनों और आज्ञा का पालन करने लगा. अन्ततः उस भाग्यशाली ने बाबा के समक्ष ही उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्याग दिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें तीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

ओ देने वाले, गरीबी न दे !

सेवा मे,
आदरणीय महामहिम भारतीय राष्ट्रपति जी,
चरण स्पर्श,

हे राष्ट्रपति जी इस समय हमारा मन मकड़ी केजाल में फंसे पतंगे की भांति अनगिनत सवाल रूपी धागों मे उलझता चला जा रहा है. क्योंकि जब हम अपनी समझदारी के तट पर खड़े होकर इस मुल्क को निहारते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि हिंदुस्तान समस्याओं केसागर मे आकंठ डूबता चला जा रहा है. इसकी आंखो से आसू नहीं बल्कि रक्त की धारा बही जा रही है. मुल्क का पूरा बदन समस्याओं के खूनी पंजो से घायल होकर लहूलुहान होता जा रहा है. अतीत की सफ़ेद चादर पर समस्याओं की काली स्याही पसरती चली जा रही है. वर्तमान के घायल शरीर पर अतीत रो रहा है. आने वाला इतिहास अपनी सांसे रोकेआशाभरी नजरों से वर्तमान की तरफ देख रहा है और वर्तमान हिंदुस्तान की इस दुर्दशा पर भारत मां विलाप कर रही है. मगर हमे समझ मे नहीं आ रहा है की आपके सामने इन समस्याओं की शुरुआत हम कहां से करें. हे, हिंदुस्तानी तख्त केबादशाह! देश केसबसे बड़े अभिभावक होने केनाते आप ही हमें बताएं कि कहां से करें हम इन समस्याओं की शुरुआत ?
क्या हम शुरू करें हिंदुस्तान केउस नन्हें मासूम की जिंदगी से जो अपने नाजुक कंधों पर कूड़ो-कचड़ों से भरा बोरा उठाए लड़खड़ाता चला जा रहा है. या शुरू करें हम भारत मां केउस जवान बेटे से जो अपने हाथों में पिस्तौल, आंखों में दरिंदगी और दिमाग में पागलपन लिए सुनसान सड़कों पर बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा है या शुरू करें. हम औलादों द्वारा उपेछित उन बुजुर्गों से जो अपने ही घरों मे बेगानों की जिंदगी जी रहे हैं या शुरू करें हम सरहद पर शहीद होने वाले शहीदों की उन विधवाओं से जो अपने मासूम बच्चे की उंगली थामे मुवाब्जे की खातिर दफ्तरों का चक्कर-पे-चक्कर लगाती हैं. या शुरू करें हम बुंदेलखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश केउन खेत-खलिहानों तथा आड़ी और डडेरों से जहां आत्मा हत्या केशिकार किसान भाई-बहनों की रूह भटक रही है या कोलकाता के सोनगाछी, मुंबई के कमतीपुरा तथा दिल्ली के जी बी रोड स्थित कोठों पर बैठी मां-बहनों की उस दर्द भरी जिंदगी से, जहां उन्हें अपने साथ-साथ अपने बच्चों का भी भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है या शुरू करें हम डरी, सहमी और डरी हुई उस जुबान से जो अपनी ही माटी पर खड़ा हो कर अपना नाम और कौम बताने से डरती है या आस्था के प्रतीक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्धारे और गिरजाघर की सीढ़ियों तथा फुटपाथ पर बैठे उन भिखारी भाई-बहनों से, जो अपनी आंखों मे आशा तथा हाथों मे टिन का कटोरा पकड़े चंद सिक्के की खातिर हर आने-जाने वालों के सामने बाबू रहम करो, माई-बाप दया करो की रट लगा रहे हैं, या शुरू करें हम अपने वतन की खातिर जां निशार करने वाले शहीदों के उन पवित्र स्मारकों से, जो खुले आसमान तले सोए पड़े इंसान को देखकर अपनी पत्थर रूपी जुबान से शायद यही कह रहा है-हाय! क्या हमने इसी दिन के लिए अपनी जानो की कुर्बानियां दी थीं या शुरू करें हम दिल्ली स्थित उस राजघाट से जहां आजादी के 67 सालों बाद भी बापू की आत्मा अपनी करोड़ों औलादों की दुर्दशा को देखकर सिसक-सिसक कर रो रही है या शुरू करें हम उन युवा भाई-बहनों से, जो अपने हाथों को काम न मिलने केकारण आत्महत्या कर रहे हैं या फिर शुरू करें हम अपने गांव तेम्हुआ में दर्दनाक मौत मरे हुए लोगों के साथ दर्द से कराहती तथा भूख से चिल्लाती मुल्क के उन करोड़ों टूटी-फुटी झोपड़ियों से, जिनकेगले से हर वक्त यह आवाज आ रही है-

ओ देने वाले, गरीबी न दे!
मौत दे दे, मगर बदनसीबी न दे!!

आपका अपना
-दिलीप अरुण, सीतामढ़ी, बिहार.
मो-09334405517

राजनेताओं का बंगला प्रेम

पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह दिल्ली स्थित सरकारी बंगला को खाली न कर अपने पिता चौधरी चरण सिंह की विरासत के बहाने सराकरी बंगले को पाने के लिए काफी मशक्त की पर वह नाकाम रहे. अजित सिंह पहले नेता नहीं है जिन्होंने सांसद या मंत्री बनने की हैसियत से मिले सरकारी बंगले को खाली करने में आना कानी की हो. इसके पहले मनमोहन सरकार ने काशीराम के नाम तील बंगले आवंटित कर मायावती को उनके समर्थन की कीमत अदा की जो सभी जानते हैं. नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम पर पहले से ही सरकारी बंगले पर कब्जा रखा गया है. आखिर कितने नेताओं के नाम पर सरकारी बंगलों को स्मारकों में तब्दील किया जाता रहेगा. शहीदों के स्मरण के लिए एक स्मारक बनाया जाता है, तो राजनेताओं के लिए अलग-अलग स्मारक क्यों? इसलिए मोदी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.

-गौरव निर्मोही, दरभंगा, बिहार.

राज ठाकरे की हकीकत

पिछले दिनों जब पूरे देश में सूर्य उपासना का महान पर्व छठ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था, तब मुझे एकाएक राज ठाकरे याद आ गए. राज ठाकरे जिन्होंने हमेशा छठ पूजा का विरोध किया है. राज ठाकरे जिसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार महाराष्ट्र में बसे बिहार एवं यूपी के लोगों की निर्मतापूर्वक पिटाई की है. जिस मराठी मानुष के नाम पर अपने चाचा से अलग होकर राजनीतिक महात्वाकांक्षा को साधने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन राजठाकरे ने किया, आज उसी मराठी मानुष ने राजठाकरे को उनकी हैसियत बता दी. महाराष्ट्र विधानसभा के कुल 288 सीटों में से केवल 1 सीट पर मनसे ने जीत हासिल की. राज ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी सामान्तर सरकार चलाते थे. जिसकी मौन स्वीकृति वहां की तत्कालीन सरकार ने उन्हें दे रखी था. उस तत्कालीन सरकार को भी जनता ने विपक्ष में बैठा दिया. भारत एक लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान के प्रस्तावना में ही इस बात का उल्लेख है. लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो संविधान की भावना से खिलावाड़ करते हैं, जनता अपने वोट की ताकत से उनको सबक सिखाती है. राज ठाकरे जैसे व्यक्ति को अपनी गोद में बैठाकर सरकार चलाने वालों को भारत की महान जनता विपक्ष में धकेलने से परहेज नहीं करती है.

-संजय कुमार, समस्तीपुर, बिहार.

सरकार का रिपोर्ट कार्ड

कवर स्टोरी-अखिलेश सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, कुछ में है दम बाकी सब बेदम(01 दिसंबर-07 दिसंबर 2014) पढ़ा. प्रभातरंजन दीन ने की स्टोरी काफी विचारोत्तेजक है. अखिलेश सरकार को अपने मंत्रियों पर ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें नसीहत देनी चाहिए कि वो भी काम करने वाले मंत्रियों की तरह अपना कार्य करें. यह भी तय हैं कि 2017 का यूपी का विधानसभा चुनाव सपा के मंत्रियों के कामकाज पर लड़ा जाएगा, क्योंकि अब बाकी मुद्दों को छोड़कर विकास सबसे ऊपर है. अखिलेश सरकार के कामकाज को लेकर कई बार सवाल खड़ा हो चुके हैं. सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव खुद ही अखिलेश सरकार के कामकाज पर कई बार सवाल खड़ा कर चुके हैं. इसलिए अखिलेक सरकार विश्राम की मुद्रा से बाहर आए और अपने विकास कार्यों को गति दे. अगर अखिलेश सरकार का यही रवैया रहा है, तो उसे आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है.

-रेखा तिवारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

सराहनीय संपादकीय

जब तोप मुकाबिल हो-आपदा प्रबंधन देश की सबसे बड़ी ज़रूरत(01 दिसंबर-07 दिसंबर 2014) पढ़ा. काफी तथ्यपरक है. संतोष भारतीय ने जब तोप मुकाबिल हो अपने संपादकीय में जम्मू-कश्मीर में आई भीषण बाढ़ में आपदा प्रबंधन की जो तस्वीर पेश की है वह बहुत चिंता का विषय है. संतोष भारतीय ने अपने संपादकीय के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में बाढ़ की तबाही की जो तस्वीर पेश की है. वह काफी दयनीय है. इस विनाशकारी बाढ़ में गांव-गांव के तबाह हो गए और कितनी संख्या में लोग मारे गए इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है. यह शायद देश में आपदा प्रबंधन की बड़े स्तर पर न होना दर्शाता है. यह बिल्कुल सही है कि सरकार को चाहिए कि देश में ऐसी भीषण आपदाओं से निपटने के लिए बड़े स्तर पर आपदा प्रबंधन स्थापित करे.

-वशिष्ठ नारायण शर्मा, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

विंध्य क्षेत्र में शिव

राजकुमार शर्मा

विंध्याचल मंण्डल को आदिकाल से ब्रह्ममांड का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र होने की मान्यता प्राप्त है. मानव की सभ्यता का विकास यहां के सोन, विंध्य की पहाड़ियों जंगलों, नदियों के मध्य हुआ. अदिकाल से यहां बसने वाले मानव में प्रकृति की चेतना के साथ शिव-शक्ति की आराधना का का भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है. जिसका महत्वपूर्ण कारण पौराणिक सांस्कृतिक नगरी काशी के सानिध्य में होने के कारण इस क्षेत्र को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है. विंध्यमंडल के घोरावल तहसील को प्राचीन काल से ही दक्षिण-काशी के रूप में जाना जाता रहा है. अनेक शिवभक्त सावन के महीने में विंध्य क्षेत्र से कांवड़ भर कर घोरावल स्थित शिवद्वार में जलाभिषेक करके पुण्य के भागी बनते हैं. इस स्थान पर अतिप्राचीन शिव-पार्वती की प्रतिमा का आलिंगनबद्ध मुद्रा में पाया जाना विद्वानो और धर्माचार्यों के लिए आज भी खोज का विषय बना हुआ है. विंध्य की गांगेय सस्कृति में अनेक संस्कृतियों ने जन्म लिया. इसी पावन धरा पर मानव सभ्यता के विकास की कहानी गढ़ी गई, मानव आदिम युग से निकल कर अन्न,फल, वनस्पतियों से परिचित हो कर मानव की श्रेणी में खड़ा हुआ. प्रयाग से होकर विंध्य क्षेत्र पहुचने वाली गंगा और विंध्य के समतल पठारी मैदानों में उपजी वनस्पतियों मानव को मांसाहार के आदिम युग से निकाल कर वनस्पति युग का एहसास कराया और सांस्कृतिक चेतना के अंकुर लगाए. मानव के समग्र विकास का स्थलीय रहा यह समूचा क्षेत्र पुरातत्व के साथ ही पर्यटन के मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थल के रूप में अपनी पहचान बना लिया है. विंध्य के इन क्षेत्रों में आज भी भूगर्भ से जिस तरह बहुमूल्य कलाकृतियां, मूर्तियां, शिलालेख मिल रहे हैं इससे अतीत की संपन्नता परिलक्षित हो रही है. काले पत्थर में तरासी गई शिव-पार्वती की आलिंगनबद्ध प्रतिमा के किनारे गणेश जी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु, सिंह वाहिनी दुर्गा सहित कई अन्य चित्र निर्मित हैं, जो मनोहरी कलाकृति के नमूना के रूप में विख्यात हैं. मुख्यमूर्ति में शिव-शक्ति की संयुक्त अवस्था में चित्रण उत्कृष्ट शिल्पकारी एवं पच्चीकारी का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करता है. मूर्ति के जानकारों का मानना है कि इस अनूठी कलाकृति का निर्माण दशवीं शताब्दी में हुआ होगा. मूर्ति के निकलने के बाद ही क्षेत्र के आदिवासियों ने प्रतिमा को अपने आराध्य के रूप में पूजना शुरू कर दिया. इस प्रतिमा पर एक लोटा जल चढ़ा कर जो भी आदिवासी अपनी मन्नत मांगता था, वह पूरी होती थी. धीरे-धीरे प्रतिमा की प्रसिद्धि बढ़ी. गांव में ही एक चउतरा बना कर आदिवासी इसकी पूजा करने लगे. इलाके के लोगों में सुख समृद्धि का चमत्कारिक विकास हुआ. कालान्तर में कन्हार गांव में आदिवासियों द्वारा पुजित प्रतिमा जो उनकी सामर्थ्य के अनुसार छोटे मंदिर में स्थापित थी. उसे अविभाजित मिर्जापुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने क्षेत्र के पूर्व प्रमुख पंडित ठाकुर प्रसाद तिवारी के प्रयास से घोरावल के प्रख्यात देवस्थान पर लाकर जनभावना के अनुसार भव्य मंदिर का निर्माण कर जगतगुरू शंकराचार्य जी की मौजूदगी में इसमें पुन: प्राण प्रतिष्ठा कराया. यहां कैमूर की सुविस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित आदिमानवों द्वारा उकेरे गए शैल-चित्र आदिम सभ्यता की जीवंतता आज भी प्रदर्षित करते हैं. जिसे पुरातात्विक सर्वेक्षणों के अनुसार दसवीं शताब्दी का माना जाता है. इतिहासकारों के अनुसार भी दसवीं सदी को इस क्षेत्र के अभ्युत्थान का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है. धार्मिक दृष्टि से इस समय यह क्षेत्र दक्षिण-काशी के नाम से अभिहित किया गया है. इस क्षेत्र में अदिमानव के अनेक अवशेष भी प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र के अद्वितीय होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

मगन दास ने उसे गले से लगा लिया. जब वह चलने लगी, तो उसकी ओर देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी. पौ फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थीं, मगन दास की आंखें खुलीं. रंभा आटा पीस रही थी. उस सन्नाटे में चक्की की घुमर–घुमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और उससे सुर मिलाकर वह प्यारे ढंग से गाती थी, झुलनियां मोरी पानी में गिरी...मैं जानूं पिया मौको मनैहैं...उलटी मनावन मोको पड़ी...एक साल गुज़र गया.

संघर्ष का अनूठा दस्तावेज़

समीक्ष्य कृति : फ़रिश्ते निकले (उपन्यास)
रचनाकार : मैत्रेयी पुष्पा
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य : 395 रुपये, **पृष्ठ :** 253

महेंद्र अवधेश

साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा सदियों से कहा जाता है. लेकिन, असल में यह उससे भी कहीं बढ़कर है. यह कोई सामान्य आईना नहीं है, जो सिर्फ़ आपको आपके चेहरे की आकृति, रंग से परिचित कराता हो, बल्कि साहित्य वह आईना है, जो चेहरे के पीछे छिपे चेहरे पर रोशनी डालता है. वह बताता है कि देखिए, खूबसूरत तस्वीर की बदसूरत असलियत. वरिष्ठ साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा का नवीनतम उपन्यास–फ़रिश्ते निकले हमें समाज के उन तमाम स्वनामधन्य खूबसूरत चेहरों की ओर ले जाता है, जिनके दामन में छल, प्रपंच, धूर्तता, झूठ, मक्कारी की कई परतें चिपकी पड़ी हैं. फ़रिश्ते निकले महज एक उपन्यास नहीं है, बल्कि यह मुख्य पात्र बेला बहू के सहारे उकेरी गई समाज की वह असली तस्वीर है, जिसमें घुटन, अपमान, अन्याय व शोषण के रंग हैं और जिन्हें बेपर्दा किया है बेला बहू, अजय सिंह, जुझार, उजाला, वीर एवं अन्य पात्रों के संघर्ष ने.

दरअसल, साहित्यकार का असल धर्म–असल कर्तव्य यही है कि वह समाज में, अपने इर्द–गिर्द, पास–पड़ोस और जहां तक उसकी नज़र जाए, सच को तलाशे. और, उस सच को तलाशे, जिससे हर कोई परे होकर निकलना चाहता हो, जिसे हर कोई नज़रअंदाज़ करना चाहता हो, स्वार्थवश अथवा मजबूरन. मैत्रेयी जी ने यह काम बखूबी अंजाम दिया है और पूरी ईमानदारी के साथ. फ़रिश्ते निकले बताता है कि डाकू सिर्फ़ जंगलों–बीहड़ों में नहीं होते, वे समाज के अंदर घनी आबादी के बीच भी होते हैं. और, ऐसे डाकू उन्हें बड़े शातिराना ढंग से लूटते हैं, जो अन्याय, अत्याचार व शोषण के विरुद्ध बगावत कर जंगलों–बीहड़ों में उतर जाते हैं. फ़रिश्ते निकले बताता है कि समाज में शुगर सिंह जैसे लोग अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए धन–बल और ऐश्वर्य के सहारे किसी का जीवन कैसे बर्बाद कर देते हैं. फ़रिश्ते निकले बताता है कि आज की राजनीति और अधिसंख्य राजनेताओं का असली चेहरा क्या है. वह बताता है कि भारत सिंह एवं जोरावर जैसे लोग, जो समाज में प्रतिष्ठित और अगुवा माने जाते हैं, उनकी नज़र में महिलाओं की हैसियत दो कौड़ी की है. वे महिलाएं तो खासकर, जो वक्त की मारी होती हैं और ग़रीबी जिनके प्रारब्ध का प्राक्कथन होती है. वही ग़रीबी, जिसने बेला को बेला बहू बनाया, जिसने जुझार को बागी बनाया, जिसने उजाला एवं उसके पिता राम रतन लोहापीटा के जीवन में अपमान के अंगार भर दिए और जिसने सीधी–सादी फूलन को दस्यु सुंदरी बना दिया.

उपन्यास-फ़रिश्ते निकले कई मायनों में बेमिसाल है. वह बताता है कि परंपरा और विरासत को जिया कैसे जाता है, कैसे उस पर गर्व किया जाता है. राम रतन लोहापीटा अपनी गाड़ी को जायदाद की तरह सीने से लगाए क्यों घूमता है, उसे हर क़ीमत पर बचाए रहने की जुगत क्यों करता है? और, जब गाड़ी बिक जाती है, तो उसे क्यों लगता है कि उसकी अनमोल थाती बिला गई.

उपन्यास–फ़रिश्ते निकले कई मायनों में बेमिसाल है. वह बताता है कि परंपरा और विरासत को जिया कैसे जाता है, कैसे उस पर गर्व किया जाता है. राम रतन लोहापीटा अपनी गाड़ी को जायदाद की तरह सीने से लगाए क्यों घूमता है, उसे हर क़ीमत पर बचाए रहने की जुगत क्यों करता है? और, जब गाड़ी बिक जाती है, तो उसे क्यों लगता है कि उसकी अनमोल थाती बिला गई. फ़रिश्ते निकले बताता है कि खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानने वाले, जन–सामान्य में लौह–मानव, लोहापीटा जैसे उपनामों से पहचाने जाने वाले और देश भर में जगह–जगह डेरे लगाकर रहने वाले लोग भी हद दर्जे तक सच्चे व ईमानदार होते हैं. आम समाज में उन्हें लेकर जो धारणाएं हैं, वे मिथ्या हैं. फ़रिश्ते निकले बताता है कि अन्याय और शोषण किस तरह एक संपन्न परिवार के नवयुवक अजय सिंह को घर–द्वार, सगे–संबंधी और माता–पिता को छोड़कर चुपचाप निकल जाने तथा फिर बीहड़ में कूदने को बाध्य कर देता है. अजय सिंह के माध्यम से पता चलता है कि बागियों का जीवन होता कैसा है, उन्हें एक रोटी–एक कारतूस के बदले कितनी क़ीमत चुकानी पड़ती है, एहसान अलग से सिर–आंखों पर लेना पड़ता है. और, अपने किसी साथी की एक मामूली–सी ग़लती पर समाज की ज़लालत अलग से सहनी पड़ती है.

उपन्यास की भाषा और शिल्प में मैत्रेयी जी का अनुभव बोलता है. कहानी गढ़ना, फिर उसे दूसरी, तीसरी, चौथी... अनगिनत कहानियों के साथ पिरोते जाना. पूरी लयबद्धता और पूरी रोचकता के साथ. पाठक यदि पढ़ना शुरू करे, तो अंत तक पहुंचे बिना माने नहीं. खाना–पीना–सोना, सब कुछ भूल जाए. यही तो लेखन की सार्थकता है और लेखक की सफलता भी. बहुत कुछ है, फ़रिश्ते निकले में, जिसका बखान एक सीमित स्थान पर नहीं किया जा सकता. फिर कहावत के रूप में हमारे सामने वह शाश्वत सत्य भी है कि भला सूरज को दीपक कौन दिखा सकता है. ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

कहानी

त्रिया चरित्र

पिछले अंक में आपने पढ़ा कि अनजाने ही मगन दास को सारी बातें कह सुनाना सेठ मक्खन लाल की बेटी को इतना नागवार गुज़रा कि उसने चंपा मालिन और उसकी भतीजी रंभा को नौकरी से निकाल दिया. उधर मगन दास नागर घाट इलाके में ठाकुर अटल सिंह की मदद से अपने रहने के लिए झोंपड़े की व्यवस्था कर चुका था और रोज़गार पाने के लिए दर–दर भटक रहा था. ऐसे में, एक दिन चंपा उसके दरवाजे जा पहुंची. जब उसे मालूम हुआ कि यह तो वही युवक है, तो उसने अपनी आपबीती कह सुनाई. मगन दास ने उसे और रंभा को अपने झोंपड़े में रख लिया. साथ रहते–रहते मगन और रंभा के दिलों में प्यार के अंकुर फूटने लगे. आगे क्या हुआ? पढ़िए, इस बार...

मगन दास की हृदय-भेदी दृष्टि को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वर्ना वह रंभा की वफा भरी खातिरदरियों का तुक कैसा बैठाता? वफा वह जादू है, जो रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकती है. मगर, प्रेमिका के दिल में बैठने का माद्दा उसमें बहुत कम था. कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगन दास ने दिल आशक्ति का पाया था और ज़ुबान माशूक की. एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाज़ार गई थी और मगन दास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था.

प्रेमचंद

तीन महीने गुज़र गए. मगन दास रंभा को ज्यों–ज्यों बारीक से बारीक निगाहों से देखता, उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता था. वह रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता, वह रोज घर में झाड़ू देती, खाना पकाती. आह, मगन दास को उन ज़्वार की रोटियों में जो मजा आता था, वह अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी न आया था. उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ़–सुधरी मिलती. न जाने कौन उसका बिस्तर बिछा देता. क्या यह रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थीं. उसने उसे कभी अपनी तरफ़ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा. आवाज़ कैसी मीठी! उसकी हंसी की आवाज़ कभी कानों में नहीं आई. अगर मगन दास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी. उसकी भूखी निगाहें बेचैनी एवं लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करतीं. वह जब किसी गांव को जाता, तो मीलों तक उसकी जिद्दी एवं बेताब आंखें मुड़–मुड़कर झोंपड़े के दरवाजे की तरफ़ आतीं. उसकी ख्याति आस–पास फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की मुसीबत और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे. इंसाफ़ पसंद लोग तो स्वागत–सत्कार से काम निकाल लेते और जो लोग ज़्यादा समझदार थे, वे लगातार तकाजों का इंतजार करते. मगन दास यह फन बिल्कुल नहीं जानता था, इसलिए दिन–रात की दौड़–धूप के बावजूद ग़रीबी से उसका गला न

छूटता. जब वह रंभा को चक्की पीसते हुए देखता, तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पिस जाता था. वह कुएं से पानी निकालती, तो उसका कलेजा निकल आता. जब वह पड़ोस की औरत के कपड़े सिलती, तो कपड़ों के साथ मगन दास का दिल भी छिद जाता. मगर, इन तमाम बातों पर उसका कोई वश नहीं था.

मगन दास की हृदय–भेदी दृष्टि को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वर्ना वह रंभा की वफा भरी खातिरदरियों का तुक कैसा बैठाता? वफा वह जादू है, जो रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकती है. मगर, प्रेमिका के दिल में बैठने का माद्दा उसमें बहुत कम था. कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगन दास ने दिल आशक्ति का पाया था और ज़ुबान माशूक की. एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाज़ार गई थी और मगन दास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था. रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई. उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था. मगन दास ने उसकी तरफ़ पहले आश्चर्य, फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थीं. रंभा ने कहा, मैं यहां न आती, तो तुम मुझसे कभी न बोलते. मगन दास बोला, बिना मर्जी पाए, तो कुत्ता भी नहीं आता. रंभा मुस्कराई, मैं तो खुद चली आई. मगन दास का कलेजा उछल पड़ा. उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज़ में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है. यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है.

मगन दास ने उसे गले से लगा लिया. जब वह चलने लगी, तो उसकी ओर देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी. पौ फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थीं, मगन दास की आंखें खुलीं. रंभा आटा पीस रही थी. उस सन्नाटे में चक्की की घुमर–घुमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और उससे सुर मिलाकर वह प्यारे ढंग से गाती थी, झुलनियां मोरी पानी में गिरी...मैं जानूं पिया मौको मनैहैं...उलटी मनावन मोको पड़ी...एक साल गुज़र गया. मगन दास की मुहब्बत और रंभा के सलीके ने मिलकर उस वीरान झोंपड़े को कुंज बना दिया. अब वहां गायें थीं, फूलों की क्यारियां थीं और कई देहाती ढंग के मोढ़े थे. सुख–सुविधा की अनेक चीजें दिखाई पड़ती थीं. एक रोज सुबह मगन दास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा. उसे देखते ही वह दौड़कर गले से लिपट गया. मगन दास और वह, दोनों एक साथ पढ़ते थे. वह अब वकील हो गया था. बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे. घटनाओं एवं संयोगों की एक लंबी कहानी थी. कई महीने हुए, सेठ लगन दास का छोटा बच्चा चेचक की नज़र हो गया. सेठ जी ने दु:ख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगन दास सारी जायदाद, कोठी, इलाके एवं मकानों का एकछत्र स्वामी था. सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे. कर्मचारियों ने गबन को अपना स्वभाव बना रखा था. बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थीं, मगर वकील साहब ने उन्हें रोक रखा था.

...क्रमश:

भारत का पहला
रेट्रो मोबाइल द ब्रिक

बिनाटोन कंपनी ने भारत का पहला रेट्रो मोबाइल द ब्रिक लॉन्च किया है. इस फोन की खासियत इसका स्टैंडबाय टाइम है. 80 के दशक जैसी स्टाइल वाला इस फोन को ब्लूटुथ के जरिए आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं. इस फोन की खासियत है कि यह एक महीने का स्टैंडबाय टाइम देगा. द ब्रिक की भारत में कीमत 3495 रुपये होगी. स्मार्टफोन के कॉन्टैक्ट्स, म्यूजिक और कॉल लॉग भी ब्लूटुथ के जरिए एक्सेस कर सकते हैं. स्पीकर से म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं. इसमें म्यूजिक के लिए एस कार्ड स्लॉट उफलब्ध है. एंड्रॉयड और आईओएस फोन से ब्लूटुथ कनेक्ट कर सकते हैं. इस को यूएसबी के जरिए चार्ज कर सकते हैं. ■

बीएमडब्ल्यू ने उतारी
शानदार कारें

बीएमडब्ल्यू ने भारत में दो नई कारें लॉन्च की हैं. ये हैं एम3 सेडान और एम4 कूपे. एम3 चार दरवाजों वाली कार है जबकि एम4 सिर्फ दो दरवाजों वाली. लेकिन मशीन के लिहाज से दोनों एक जैसी हैं. इनका इंजन 3.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड 6 सिलिंडर पेट्रोल इंजन है जो बेहद शक्तिशाली है. ये कारें सिर्फ 3.9 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. इनकी अधिकतम गति सीमा 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और इलेक्ट्रानिक सिस्टम से नियंत्रित होता है. कंपनी ने इनका परफॉर्मेंस बेहतर हो इसलिए इनका वजन घटाया है और इसके लिए हल्के लेकिन मजबूत पदार्थों का इस्तेमाल किया है. इनकी छत कार्बन फाइबर की है जबकि बॉडी में एल्युमिनियम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है. इनकी एक खासियत है कि इनका स्टियरिंग इलेक्ट्रॉनिक पॉवर से चलता है. इनका हेडलैंप एलईडी का है और उसमें एलईडी रिंग्स भी हैं. इन कारों की सीटें बके लेदर सीटें हैं और इनके बैकरेस्ट पर अंग्रेजी का एम शब्द चमकता है. इसमें मनोरंजन के लिए 22.35 सेंटीमीटर का इंफोटनेमेंट स्क्रीन भी है. इसकेअलावा सैटेलाइट नेविगेशन भी है. म्यूजिक के शौकीनों के लिए इसमें 16-स्पीकर हर्मन कारदां सराउंड साउंड सिस्टम है. इसमें यात्री सुरक्षा केकड़े इंतजाम हैं. एक्स शोरूम में एम3 की कीमत 1.20 करोड़ रुपये से शुरू होती है जबकि ए4 की 1.22 करोड़ रुपये से. ■

यह डिवाइस चैन से सुलाएगी
और सुबह मस्ती के साथ उठाएगी

अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी केतीन इंजीनियरिंग छात्रों ने एक ऐसा ईयरप्लग बनाया है, जो अलार्म की आवाज को सीधा कानों तक पहुंचाएगा. इस ईयरप्लग का नाम है स्माइल क्लॉक. यह ईयरप्लग स्मार्टफोन ऐप केसाथ ब्लूटुथ से कनेक्ट होता है. सैन डिएगो की कंपनी ही(he) इसे बनाएगी. इसकी खास बात यह है कि इससे आप म्यूजिक का आंनद भी उठा सकते हैं और रात को सोते समय बाहरी आवाजों जैसे खर्राटों से बचने केलिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं. विशेष फीचर यह है कि यह आपके स्मार्टफोन कैमरा से कनेक्ट होगा. अलार्म ऑफ करने केलिए आपको कैमरा में देखना होगा और ऐप इस बात की तस्दीक करेगा कि आप उठने के मूड में हैं या नहीं. ■

बारिश से बचाएगा
न दिखने वाला
छाता

छाता कभी हमें धूप से तो कभी हमें बारिश से बचाता है. छाता कई अलग-अलग डिजाइन और रंगों में उपलब्ध होता है. लेकिन एक ऐसा छाता है, जिसमें न कोई पतली कमानियां होगी और न ही उस पर कोई प्लास्टिक या कपड़े की सीट होगी. लेकिन ऐसा ही एक अदृश्य छाता बनाया गया है, जो आपको बारिश से बचाएगा. वैसे यह आपको धूप से नहीं बचा पाएगा. इसे एयर अंब्रेला नाम दिया गया है. एयर अंब्रेला एक पाइप जैसा दिखता है, जिसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है. यह छाता हवा की मदद से पानी को आपके ऊपर नहीं गिरने देता. एयर अंब्रेला में सबसे नीचे स्विच है. उसके ऊपर कंट्रोलर, लिथियम बैटरी और मोटर है. मोटर सबसे ऊपरी हिस्से में नीचे से हवा लेकर उसे ऊपर चारों तरफ फेंकता है. हवा की वजह से पानी सीधा नीचे नहीं गिरता और थोड़ी दूरी पर गिरता है. एयर अंब्रेला के3 मॉडल हैं. एयर अंब्रेला करीब 30 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी बैटरी 15 मिनट चलेगी. एयर अंब्रेला बी 50 सेंटीमीटर लंबा है, एयर अंब्रेला सी 80 सेंटीमीटर लंबा है और इनकी बैटरी 30 मिनट तक चलेगी. इसकी कीमत लगभग 5500 रुपये हो सकती है. ■

हीरो एक्सट्रीम एक्सपोर्ट्स
जल्द होगी लॉन्च

हीरो मोटोकॉर्प अपनी नई बाइक केतौर पर हीरो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को बहुत जल्द भारतीय बाजार में उतारेगी. यह कंपनी की लोकप्रिय 150 सीसी बाइक एक्सट्रीम का ही अपग्रेड वर्जन है. नई हीरो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स अपने पिछले वर्जन से काफी अलग है, इसमें डुअल फिनिश कलर का इस्तेमाल किया गया है. ये बाइक पांच शानदार रंगों में मौजूद है. स्पिलिट सीट डिजाइन केसाथ कंपनी ने इसमें कई एडवांस फीचर्स जैसे अंडरसीट मोबाइल चार्जर और इंजन इंमोबलाइजर का इस्तेमाल किया है. इसकेअलावा पावर की बात करें तो इसमें 149.2सीसी, 4 स्ट्रोक , सिंगल सिलेंडर इंजन, 5 स्पीड गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है. ■

माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया
8 इंच स्क्रीन का टैबलेट

माइक्रोमैक्स ने कैनवस टैब पी666 लॉन्च किया है, जो 1.2 जीएचजेड इंटेल ऐटम डुअल कोर प्रोसेसर से लैस है. यह 3जी को सपोर्ट करता है. पी666 एंड्रॉयड 4.4.2 जेलीबीन किटकैट पर आधारित है. इसका टच स्क्रीन 8 इंच का है जिसका रेजोल्यूशन 1200 गुणा 800 पिक्सल है. इस टैब में 1 जीबी रैम है और इसमें 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है. साथ ही माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से इसकी 32 जीबी तक स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जा सकती है. इसमें तीन सेंसर हैं, लाइट, ऐक्सीलरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी. यह सिंगल सिम वाला टैबलेट है. इसमें 5 एमपी रियर कैमरा है और 2एमपी फ्रंट कैमरा है. इसका रियर कैमरा 1080 पी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसमें कोई फ्लैश नहीं है. इसकेअन्य फीचर हैं 3जी, 2जी, वाई-फाई, ब्लूटुथ और जीपीएस. इसकी बैटरी 4400 एमएएच की है और 15 घंटे का टॉक टाइम देती है. इसकी कीमत कंपनी ने 10,999 रुपये रखी है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

मैदान में जितना खतरा खिलाड़ियों को होता है उतना ही अंपायरों और रेफरियों को भी होता है. ह्यूज की मौत के बाद इजरायल के पूर्व कप्तान और वर्तमान अंपायर हिलेल अवास्कर भी मैदान पर गेंद का शिकार हो गए. एक स्थानीय मैच के दौरान गर्दन पर देंद लगने की वजह से उनकी मौत हो गई. तेजी से आती हुई गेंद पहले स्टंप पर टकराई और फिर अवास्कर की गर्दन पर लगी. उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां डॉक्टर उनकी जान बचाने में नाकाम रहे.

खेल-खेल में मौत

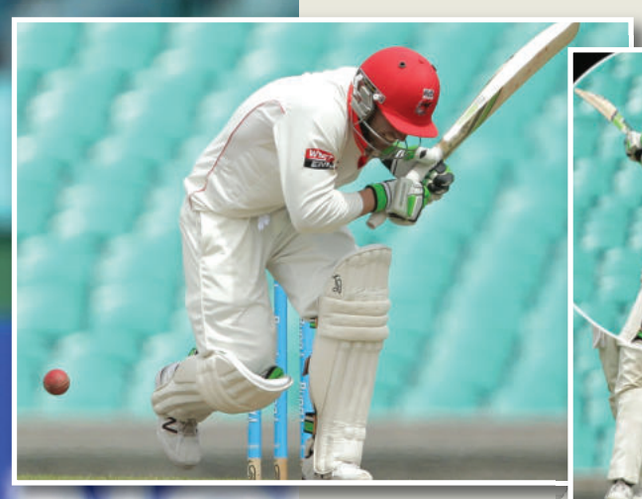

खेल-खेल में चोट तो लगती ही है लेकिन कभी-कभी यह चोट जानलेवा और करियर खत्म करने वाली भी बन जाती है. फिल ह्यूज को लगी गंभीर चोट ने फिर से उन खतरों की याद दिला दी है. खेलों के इस दर्दनाक पहलुओं पर नज़र डालना इसलिए भी जरुरी हो जाता है क्योंकि खिलाड़ी कई बार सुरक्षा को दरकिनार कर देते हैं. दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है. कोई भी खेल इससे अछूता नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर फिलिप ह्यूज 25 नवंबर को एक घरेलू मैच के दौरान तेज गेंदबाज सीन एबट की गेंद सिर पर लगने की वजह से घायल हो गए थे. इसके दो दिन बाद 27 नवंबर को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. गेंद के सिर पर लगने के कुछ पल बाद ह्यूज जमीन पर गिर पड़े थे. किसी को पता नहीं था कि यह बाउंसर क्रिकेट की दुनिया का एक उभरता सितारा छीन लेगी. किसी भी खेल में चोट लगने का जोखिम होता है. यदि खेल के मैदान पर लगी चोट जानलेवा हो जाए तो यह दु:खद है. हर खेल में कुछ खतरे होते हैं और क्रिकेट कोई अपवाद नहीं है. क्रिकेट के अलावा कई खेलों में खेल के दौरान चोटिल होने की वजह से खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है. फॉर्मूलावन, कार और बाइक रेसिंग के दौरान खिलाड़ियों की जान हर वक्त जोखिम में होती है. एक चूक आपको मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है. कुछ दिनों पहले एक फुटबॉल खिलाड़ी को गोल करने के बाद सेलिब्रेट करते वक्त चोट लगी और उनकी मौत हो गई. पूर्व फॉर्मूला वन विश्व चैंपियन माइकल शूमाकर स्कीइंग करते समय एक चट्टान से टकरा गए थे. उसके बाद वह लंबे समय तक कोमा में रहे. लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद उन्हें होश तो आया लेकिन अभी तक उनकी हालत स्थिर नहीं हुई है. अभी भी वह चोट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.

फिल ह्यूज की मौत क्रिकेट के मैदान पर लगी चोट की वजह से हुआ पहला हादसा नहीं है. क्रिकेट के मैदान पर इससे पहले भी कई खतरनाक हादसे हुए हैं. उन हादसों से रू-ब-रू हुए खिलाड़ियों में से कुछ खुशनसीब रहे और कुछ ह्यूज की तरह बदनसीब रहे और असमय मौत के मुह में समा गए. तेज गेंदबाजी का सबसे ज्यादा खौफ वर्ष 1932-33 में सर डॉन ब्रैडमैन को रोकने के लिए शुरू की गई बॉडी लाइन सीरीज के दौरान पनपा था. इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज हेराल्ड लॉरवुड शरीर को निशाना बनाकर फेंकी गई एक गेंद से ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बर्ट ओल्डफील्ड के सिर की हड्डी टूट गई थी. साल 1959 में पाकिस्तान के 17 वर्षीय खिलाड़ी अब्दुल अजीज की मौत कायदे आज़म ट्रॉफी के फायनल के दौरान हुई थी. बैंटिंग करते वक्त उनकी छाती में गेंद लगी और वह बेहोश हो गए. इसके बाद वो फिर कभी होश में नहीं आए. वर्ष 1960 में भारतीय बल्लेबाज नारी कांट्रेक्टर के सिर पर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज चार्ली ग्रिफिथ की गेंद लगी थी. इस चोट के बाद कांट्रेक्टर छह दिन तक बेहोश रहे थे. ऑपरेशन के बाद उनकी जान तो बच गई लेकिन वो दोबारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सके. पूर्व भारतीय बल्लेबाज अंशुमन गायकवाड़ भी पिच पर मौत के करीब से गुजर चुके हैं 1976 के वेस्टइंडीज दौरे में उनके कान पर माइकल होल्डिंग की गेंद लगी थी. इसके बाद दो दिनों तक उन्हें आईसीयू में रहना पड़ा था. इस हादसे में उनके काम के पर्दे फट गए थे. इस वजह से उन्हें आज भी कम सुनाई देता है. वर्ष 1986 में वेस्टइंडीज के सर्वकालिक तेज़ गेंदबाजों में से एक मैल्कम मार्शल की एक गेंद माइक गैटिंग के हेलमेट की जाली को तोड़ते हुए नाक जा लगी और परिणाम स्वरूप गैटिंग के नाक की हड्डी टूट गई. साल 1998 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते वक्त फील्डिंग के दौरान भारत के रमन लांबा के सिर में गेंद लगी थी. बांग्लादेश में रमन लांबा जब पाइंट की दिशा में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे, तब उनके भी सिर पर गेंद लगी थी और वे कोमा में चले गए थे. कई दिनों तक जीवन और मौत से संघर्ष करने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका था. पिछले साल पाकिस्तान के 22 वर्षीय युवा बल्लेबाज जुल्फिकार भट्टी की मौत सिंध प्रांत में क्लब क्रिकेट के दौरान हो गई थी. गेंद उनकी छाती पर लगी थी. साल 2013 में ही दक्षिण अफ्रीका के 32 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज डेरियन रेनडल की मौत भी घरेलू क्रिकेट खेलने के दौरान हुई थी. पुल शॉट खेलते वक्त उनके सिर पर गेंद लगी थी.

वर्ष 1986 में वेस्टइंडीज के सर्वकालिक तेज़ गेंदबाजों में से एक मैल्कम मार्शल की एक गेंद माइक गैटिंग के हेलमेट की जाली को तोड़ते हुए नाक जा लगी और परिणाम स्वरूप गैटिंग के नाक की हड्डी टूट गई. साल 1998 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते वक्त फील्डिंग के दौरान भारत के रमन लांबा के सिर में गेंद लगी थी. बांग्लादेश में रमन लांबा जब पाइंट की दिशा में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे, तब उनके भी सिर पर गेंद लगी थी और वे कोमा में चले गए थे. कई दिनों तक जीवन और मौत से संघर्ष करने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका था.

मैदान में जितना खतरा खिलाड़ियों को होता है उतना ही अंपायरों और रेफरियों को भी होता है. ह्यूज की मौत के बाद इजरायल के पूर्व कप्तान और वर्तमान अंपायर हिलेल अवास्कर भी मैदान पर गेंद का शिकार हो गए. एक स्थानीय मैच के दौरान गर्दन पर देंद लगने की वजह से उनकी मौत हो गई. तेजी से आती हुई गेंद पहले स्टंप पर टकराई और फिर अवास्कर की गर्दन पर लगी. उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां डॉक्टर उनकी जान बचाने में नाकाम रहे. ऑस्ट्रेलिया में एक घरेलू मैच के दौरान 72 वर्षीय अंपायर एल्विन जैनकिंस की मैदान पर मौत हो गई थी. मैच के दौरान फील्डर द्वारा फेंकी गई गेंद जैनकिंस के सिर पर लगी थी. सिर पर गेंद लगने से जैनकिंस मैदान पर ही गिर गए, इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. जैनकिंस पिछले 25 सालों से अंपायरिंग का दायित्व निभा रहे थे. क्रिकेट मैदान पर किसी अंपायर की मौत होने की यह दुनिया में पहली घटना थी.

हॉकी के दौरान भी खिलाड़ियों को चोट लगने की संभावनाएं होती हैं. वहां गोलकीपर के पास हर तरह की सुरक्षा होती है. लेकिन पेनल्टी कॉर्नर के दौरान दूसरे डिफेंस करने वाले खिलाड़ियों के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं होते हैं. हालांकि कुछ खिलाड़ी सुरक्षा के लिए मास्क पहनते हैं. जब खिलाड़ी ड्रैग फ्लिक करता है तो गेंद तेजी से खिलाड़ियों की ओर आती है. गत 30 नवंबर को ब्रिटेन के हॉकी खिलाड़ी सैम ओवन ब्लैकपूल हॉकी क्लब की ओर से बोल्टन के खिलाफ मैच खेल रहे थे. इस दौरान उनकी गर्दन में गेंद लगी. बावजूद इसके वे मैदान में डटे रहे. हॉफ टाइम में वो बाहर आए. उसके बाद उन्हें थोड़ी तकलीफ महसूस हुई और वह अस्पताल गए जहां वो बेहोश हो गए. वो अब भी कोमा में हैं.

तीन बार के फॉर्मूला वन विश्व चैंपियन एर्टन सीना 1994 में सैन मरीनो ग्रां प्री के दौरान हुए हदासे में मौत का शिकार हुए थे. रेस के दौरान वह सबसे आगे चल रहे थे. रेस के दौरान जान गंवाने वाले सीना आखिरी फॉर्मूला वन चालक हैं. पूर्व फॉर्मूला वन चालक मार्क वेबर की गाड़ी 30 नवंबर को ब्राजील के साओ पालो में एक रेस के दौरान दुर्घटना ग्रस्त हो गई. इसके बाद उनकी गाड़ी आग की चपेट में आ गई. जहां सप्ताह भर अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें छुट्टी मिली. इसी साल अक्टूबर में जापान ग्रां प्री के दौरान फेरारी टीम चालक जूल्स बियांची की गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी. हादसे में वह बेहोश हो गए थे उनके सिर पर गहरी चोट आई थी.

भारत में फुटबॉल खेलते हुए भी कई खिलाड़ियों ने अपनी जान गंवाई है. साल 2004 में मोहन बागान और डेंपो के बीच हो रहे मुकाबले में डेपों की ओर से खेल रहे ब्राजीली खिलाड़ी क्रिस्टियानो जूनियर के सीने में गोलकीपर सुब्रत पॉल का मुक्का लगा था. इसके बाद उनकी मौत हो गई थी. इसी तरह साल 2012 में एक डिवीजन लीग के मैच के दौरान बैंगलोर के खिलाड़ी डी व्यंकटेश को चोट लग गई थी. मैदान में एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें ऑटो से अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बॉक्सिंग को एक खतरनाक खेल माना जाता है. वर्ष 1952 में हैवीवेट चैंपियन एड सैंडर्स की सिर पर जोरदार मुक्का लगने की वजह से मौत हो गई थी.■

फिलिप ह्यूज : छोटे से करियर में किए बड़े कारनामे

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के उभरते बल्लेबाज फिल ह्यूज की मौत के बाद सारा क्रिकेट जगत सदमें में है. 25 साल के इस बांए हाथ के युवा बल्लेबाज़ ने कम उम्र में ही क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बना ली थी. साल 2006 में फिलिप ने न्यू साउथ वेल्स की ओर से अंडर-17 क्रिकेट खेलना शुरू किया था. अपने पदार्पण मैच में उन्होंने 51 रन बनाए. ह्यूज मने 26 फरवरी 2009 को जोहानसबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ करियर का पहला टेस्ट मैच खेला. डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में वह खाता भी नहीं खोल सके लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 75 रनों की पारी खेली. इसके बाद सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में की दोनों पारियों में शतक लगाने का कारनामा कर दिखाया और दोनों पारियों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. जनवरी 2013 को फिल ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय मैच खेला था. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए अपने इस डेब्यू मैच में उन्होंने शतक जड़ डाला. ऐसा करने वाले वह पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे. अक्टूबर 2014 को फिल ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेला. फिल ने अपने छोटे से क्रिकेट करियर में 26 टेस्ट मैच खेलते हुए 1535 रन बनाए. टेस्ट मैचों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 160 रन रहा. उन्होंने अपने करियर में कुल 25 अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय मैच खेलते हुए 826 रन बनाए. एकदिवसीय मैचों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 138 रन रहा. फिलिप एक दिवसीय मैचों में 64 नंबर की जर्सी पहनते थे. उनकी इस जर्सी को कप्तान माइकल क्लार्क के अनुरोध पर रिटायर कर दिया गया है. अपने आखिरी मैच में ह्यूज 63 रनों पर नाबाद रहे.■

feedback@chauthiduniya.com

बाजीराव मस्तानी मेरी एक्टिंग काबिलियत का इम्तिहानः प्रियंका

बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि फिल्म बाजीराव मस्तानी उनकी एक्टिंग काबीलियत का इम्तिहान ले रही है. इससे पहले उन्होंने ऐसी ही बात फिल्म मेरीकॉम की शूटिंग के दौरान भी कही थी. संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी प्रियंका की पहली ऐतिहासिक फिल्म है. प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह मेरी पहली ऐतिहासिक फिल्म है और ऐसी फिल्म करना बहुत मुश्किल काम है. जो एक ऐसी घटना की कहानी कहती है जो तकरीबन 500 साल पहले हुई थी. यह रोल बेहद मुश्किल है. फिल्म की कहानी मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और उसकी दूसरी पत्नी मस्तानी की प्रेम कहानी पर आधारित है. फिल्म में प्रियंका बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई का किरदार निभा रही हैं. इस फिल्म में प्रियंका के अलावा लीड रोल में दीपिका पादुकोण भी हैं, जो कि फिल्म में बाजीराव का रोल कर रहे रणवीर सिंह की दूसरी पत्नी के रोल में नजर आएंगी.■

फिर चलेगा आलिया की आवाज का जादू!

अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने अभिनय से सबको मोह रखा है. बीच-बीच में वह अपनी आवाज का जादू भी दिखाती रही हैं. एक बार फिर वह अपनी आवाज के जादू से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली हैं. आलिया फिल्म रॉकऑन के सीक्वल में काम कर रही हैं इस फिल्म के किरदार को वह अपनी आवाज देंगी. इसके लिए आलिया तैयारी कर रही हैं. इससे पहले आलिया ने फिल्म हाइवे और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में गाने गाये हैं. इन गानों को दर्शकों ने पसंद भी किया था. फिल्म के निर्देशक पहले आलिया और श्रद्धा को कास्ट करने के मामले में कन्फ्यूज थे. लेकिन बाद में आलिया का चयन किया गया.बताया जा रहा है कि जिस तरह फिल्म रॉकऑन में फरहान अख्तर ने सभी गानों को अपनी आवाज दी थी, उसी तरह आलिया भी फिल्म के सीक्वल में सारे गाने खुद ही गाने वाली हैं. बॉलीवुड में आजकल कई ऐसे कलाकार हैं जो एक्टिंग के साथ-साथ सिंगिंग में भी अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं. इनमें आलिया के अलावा श्रद्धा कपूर, अली जफर और आयुष्मान खुराना जैसे कलाकार शामिल हैं. आयुष्मान तो अपने गीत पानी दा रंग के लिए बेस्ट मेल सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत चुके हैं. ■

आलिया फिल्म रॉकऑन के सीक्वल में काम कर रही हैं इस फिल्म के किरदार को अपनी आवाज देंगी. इसके लिए आलिया तैयारी कर रही हैं. इससे पहले आलिया ने फिल्म हाइवे और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में गाना गाने गाये हैं. इन गानों को दर्शकों ने पसंद भी किया था. फिल्म के निर्देशक आलिया और श्रद्धा को कास्ट करने के मामले में कन्फ्यूज थे. लेकिन बाद में आलिया का चयन किया गया.

चलती का नाम गाड़ी का रीमेक बनाएंगे रोहित

रोहित शेट्टी साठ के दशक की फिल्म चलती का नाम गाड़ी का रीमेक बनाने जा रहे हैं. इस फिल्म के लिए रोहति ने एश्वर्या रॉय बच्चन को कास्ट किया है. एश्वर्या ने भी फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी है. फिल्म में एश्वर्या के अपोजिट शाहरूख खान होंगे. 1958 में प्रदर्शित इस फिल्म में किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी थी. इस फिल्म में काम करने के लिए पहले रोहित ने काजोल को एप्रोच किया था, काजोल के साथ बात नहीं बन पाई तो एश्वर्या इससे जुड़ गईं. शाहरुख और ऐश्वर्या इससे पहले फिल्म जोश और देवदास में एक साथ काम कर चुके हैं. साथ ही दोनों फिल्म शक्ति के आइटमनंबर इश्क कमीना में भी साथ नड़र आए थे. चलती का नाम गाड़ी में अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार एक साथ नज़र आए थे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

श्रद्धांजलि

बहुत याद आएंगे देवेन

साठ के दशक के लोकप्रिय हास्य अभिनेता देवेन वर्मा का पुणे में निधन हो गया. वे 78 वर्ष के थे. उन्होंने 1961 से लेकर 2003 तक 149 फिल्मों में काम किया. 2003 के बाद वह परदे पर नज़र नहीं आए. समय के साथ बॉलीवुड में आए बदलाव के साथ वे तालमेल नहीं बना सके. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब कोई असिस्टेंट डायरेक्टर सिगरेट झाड़ते हुए शॉट के लिए बुलाने आती है तो अच्छा नहीं लगता है. हमारे समय में कलाकारों की इज्जत थी लेकिन अब ऐसा नहीं है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई उन्हें नई किस्म की फिल्मों में रोल मिलने भी कम हो गए, ऐसे में उन्होंने फिल्मों में आगे काम नहीं करना ही उचित समझा. फिल्मों से उनका अटूट नाता था. वे पुणे में अपने दोस्तों के साथ निजी थिएटर में फिल्में देखा करते थे. हाल के दिनों में प्रदर्शित फिल्मों में उन्हें विकी डोनर बहुत पसंद आई थी. नए कलाकारों में उन्हें रणबीर कपूर सबसे ज्यादा पसंद थे. देवेन वर्मा मूलरूप से गुजरात के कच्छ के रहने वाले थे. उनके पिता बलदेव सिंह वर्मा चांदी के कारोबारी थे. बड़ी बहन की पढ़ाई के लिए उनके माता-पिता पुणे आ गए. देवेन को शुरू से ही मिमिक्री का शौक था. पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई आने के बाद वे जॉनी व्हिस्की के साथ स्टेज पर मिमिक्री करते थे. एक शो के दौरान बीआर चोपड़ा की नज़र उनपर पड़ी. उन्होंने अपनी फिल्म धर्मपुत्र में काम करने का देवेन को ऑफर दिया. साल 1961 में प्रदर्शिति इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 600 रुपये बतौर पारिश्रमिक मिले. हालांकि यह फिल्म असफल रही. यह फिल्म शशि कपूर की पहली फिल्म थी. देवेन को 1963 में आई फिल्म गुमराह से पहचान मिली. यह फिल्म भी बीआर चोपड़ा की ही थी. इस फिल्म में उन्होंने अशोक कुमार के नौकर का किरदार अदा किया था. रियल लाइफ में वे अशोक कुमार के दामाद बने. उन्होंने अशोक कुमार की बेटी रूपा गांगुली से विवाह किया था.

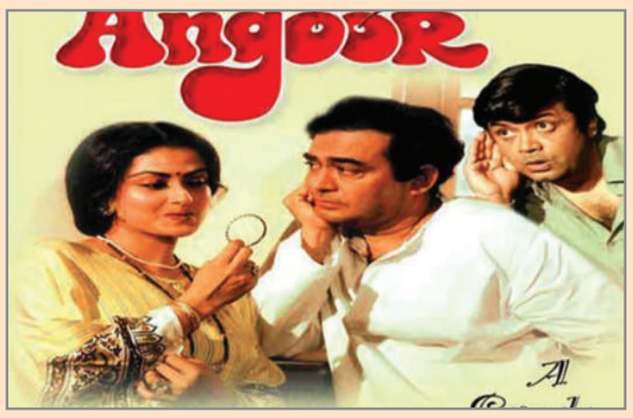

1975 में रिलीज हुई फिल्म चोरी मेरा काम में निभाए उनके किरदार को बहुत सराहा गया. इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया. फिल्म अंगूर के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया. इस फिल्म में बहादुर के डबल रोल में उन्होंने संजीव कुमार का पूरा साथ दिया था. देवेन वर्मा की कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त थी. उन्होंने अपने समकालीन दूसरे कॉमेडियन की तरह फूहड़ता का सहारा कभी नहीं लिया. चेहरे पर निर्विकार भाव लाकर चुटीली बातें करना उनकी खासियत थी. उनके हाव-भाव में शालीनता रहती थी. उन्होंने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाए. उन्होंने फिल्म नादान का निर्देशन किया. बतौर निर्मात-निर्देशक उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिली. उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया. नैहर छूटल जाए नाम की भोजपुरी फिल्म में कुमकुम ने उनकी हिरोइन का रोल अदा किया था. शशि कपूर उनके खास मित्र थे. देवेने ने अमिताभ बच्चन के साथ भी अनेक फिल्में कीं. उनके साथ वे स्टेज शो किया करते थे. 1993 में वह मुंबई से पुणे शिफ्ट हो गए . बावजूद इसके वे फिल्मों में अभिनय करते रहे. उनकी आखिरी फिल्म सबसे बढ़ कर हम थी. उनकी आखिरी रिलीज फिल्म कलकत्ता मेल थी. ■

चौथी दुनिया

15 दिसंबर–21 दिसंबर 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार-झारखंड

सबके दुलरुआ मांझी

सीएम मांझी के बयानों से न केवल महादलितों में बल्कि कुछ हद तक अतिपिछड़ों में भी उत्साह बढ़ा है. जो महादलित कल तक नीतीश कुमार की आंखों का इशारा समझ रहे थे वे आज जीतन राम मांझी के बयानों को गौर से समझने की कोशिश कर रहे हैं. महादलितों को अब लगने लगा है कि उनके बीच का ही कोई आदमी अब उनके हक की आवाज उठा रहा है और उसे इसका वाजिब हक देने की कोशिश कर रहा है. कहा जाए तो महादलितों के नेता के तौर पर जीतन राम मांझी ने खुद को बहुत हद तक स्थापित कर लिया है. जीतन राम मांझी की यही पूंजी भाजपा सहित दूसरे दलों को उनकी तरफ आकर्षित कर रही है. सूत्र बताते हैं कि भाजपा के कई बड़े नेता इस काम में लगे हैं कि कैसे सीएम मांझी को तोड़कर भाजपा खेमे में किया जाए.

सरोज सिंह

बिहार में राजनीति की बिसात पर इन दिनों कुछ ऐसी चालें चली जा रही हैं जिसे अगर समझने की कोशिश में चूक हो जाए तो लगेगा कि सूबे में दल का बंधन कमजोर हो गया है और सभी पार्टियां सौ फीसदी मेरिट के आधार पर बयानबाजी कर रही हैं. लेकिन अगर इन चालों को बारीकी से समझ लिया जाए तो पता चल जाएगा कि दल का बंधन नहीं टूटा है बल्कि जदयू को तोड़ने की कोशिश बदस्तूर जारी है. भले ही यह बात अभी ऊपरी तौर पर बयानों और छोटी-मोटी मुलाकातों तक ही सीमित दिखलाई पड़ती है पर जानकार बताते हैं कि इसके लिए गंभीर पहल हो चुकी है और बाहर से जो हल्का फुल्का दिख रहा है, वास्तव में इसके पीछे एक ठोस गेमप्लान काम कर रहा है और अगर यह सफल रहा तो यह नीतीश कुमार और जदयू के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है.

मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया. कहा गया कि नीतीश कुमार ने महादलित कार्ड खेला है और बिहार के आगामी चुनावों में उन्हें इसका बंपर फायदा होगा. बात भी सही लग रही थी लेकिन इस कहानी में जीतन राम मांझी के बयानों ने इतना पेंच फंसा दिया कि अब यह दांव उल्टा दिखाई पड़ने लगा है. सोशल इंजीनयरिंग के माहिर खिलाड़ी लगता है इस बार कहीं धोखा न खा जाएं. सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि एनडीए में शामिल सभी पार्टियों ने तो मांझी का गुनगान ही शुरू कर दिया. भाजपा, लोजपा और रालोसपा के कई नेताओं ने सीएम मांझी को जदयू छोड़कर अपने यहां आने का खुला निमंत्रण दे रखा है. जदयू की तरफ से मांझी पर अगर कोई भी हमला होता है तो एनडीए इसका पुरजोर विरोध करता है. भाजपा के सीपी ठाकुर और शाहनवाज हुसैन ने तो सार्वजनिक मंच से जीतन राम मांझी को भाजपा में शामिल होने का न्योता दे रखा है. इसी तरह रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण कुमार ने भी मांझी को अपनी पार्टी में आ जाने का अनुरोध किया है. रामविलास पासवान कई दफा कह चुके हैं कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री हैं. जीतन राम मांझी पर शरद यादव के एक बयान से लोजपा नेता विष्णु पासवान तो इतने आहत हो गए कि उन्होंने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शरद यादव पर मुकदमा ठोंक दिया. हाल यह हो गया है कि जदयू के लोग जितना जीतन राम मांझी का बचाव नहीं करते हैं उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार के विरोधी मांझी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं. देखा जाए तो जीतन राम मांझी बतौर मंत्री और बतौर मुख्यमंत्री दो अलग-अगल चेहरे हो गए हैं. मंत्री के तौर पर कहा जाता था कि वह महादलित कोटे का प्रतिनिधित्व करते हैं. काम के लिहाज से भी उन्होंने ऐसा कुछ कारनामा नहीं किया जिससे उनकी एक अलग छवि बनी हो पर बतौर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बयानों और कामों से सबका ध्यान खींचा है चाहे वह पक्ष हो या फिर विपक्ष.

सीएम मांझी के बयानों से न केवल महादलितों में बल्कि कुछ हद तक अतिपिछड़ों में भी उत्साह बढ़ा है. जो महादलित कल तक नीतीश कुमार की आंखों का इशारा समझ रहे थे वे आज जीतन राम मांझी के बयानों को गौर से समझने की कोशिश कर रहे हैं. महादलितों को अब लगने लगा है कि उनके बीच का ही कोई आदमी अब उनके हक की आवाज उठा रहा है और उसे इसका वाजिब हक देने की कोशिश कर रहा है. कहा जाए तो महादलितों के नेता के तौर पर जीतन राम मांझी ने खुद को बहुत हद तक स्थापित कर लिया है. जीतन राम मांझी की यही पूंजी भाजपा सहित दूसरे दलों को उनकी तरफ आकर्षित कर रही है. सूत्र बताते हैं कि भाजपा के कई बड़े नेता इस काम में लगे हैं कि कैसे सीएम मांझी को तोड़कर भाजपा खेमे में किया जाए. महादलितों की आबादी सूबे में करीब सवा करोड़ के आस-पास है. रामविलास पासवान पहले से ही एनडीए के खेमे में हैं. ऐसे में अगर मांझी के बहाने महादलितों का एक बड़ा तबका भाजपा के साथ हो लेता है तो यह एनडीए के लिए निर्णायक पहल होगी. जदयू के गुस्साए विधायक भी मांझी के संपर्क में हैं. भाजपा का अप्रत्यक्ष साथ तो इन विधायकों के साथ है ही. ऐसे में अगर कुछ महादलित विधायक भी साथ हो जाएं तो जदयू में एक बड़ी टूट चुनाव से पहले हो सकती है.

राजनीतिक विश्लेषक बतलाते हैं कि सीएम मांझी ने अपने बयानों से इतनी दूरी नीतीश कुमार और शरद यादव से बढ़ा ली है कि अब इसे पाटना बहुत ही मुश्किल है. सच्चाई यह है कि खुद मांझी भी नहीं चाहते हैं कि यह दूरी कम हो और इसलिए वह ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे जदयू और सरकार की स्थिति हास्यास्पद होती जा रही है. इसका पूरा फायदा भाजपा उठाना चाह रही है. गौरतलब है कि जीतन राम मांझी के घर में भाजपा का माहौल कोई नया नहीं है. सीएम मांझी के एक पुत्र पिछले चुनाव में भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे. लेकिन घर में ही सहमति न हो पाने के कारण उनको भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला बदलना पड़ा. केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता भी मांझी के समर्थकों को लुभा रही है. सीएम के एक समर्थक विधायक कहते हैं कि नीतीश कुमार तो अब उन्हें मुंख्यमंत्री बनाने से रहे. वह तो कहते फिर रहे हैं कि अगर मौका मिला तो बिहार की सेवा करने को तैयार हूं. इसलिए जदयू में तो कोई आस नहीं बची है. बेहतर तो यही होता कि उनका बेटा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ता और सीएम खुद कहीं के गवर्नर या फिर केंद्र में मंत्री बन जाते. नाम न छापने की शर्त पर इस समर्थक विधायक ने बताया कि महादलितों के लिए सीएम एक मसीहा के तौर पर उभरे हैं और अगर उनके हाथ में शक्ति नहीं रही तो फिर महादलितों के सपनों को कौन पूरा करेगा. इस पूरी कहानी में लालू प्रसाद की भी बहुत अहम भूमिका है. लालू चाहते हैं कि सीएम मांझी के बयानों से नीतीश कुमार रोज ब रोज कमजोर होते जाएं ताकि सीटों के बंटवारे में ज्यादा हील हुज्जत न हो. इसलिए जब सीएम को हटाने की मांग को लेकर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से मुलाकात की तो लालू ने टो टूक मना कर दिया. राजद बार-बार कह रहा है कि उसने जदयू को नहीं बल्कि महादलित जीतन राम मांझी की सरकार को अपना समर्थन दिया है. लालू भी चाहते हैं कि अगर बात बिगड़े तो जीतन राम मांझी भाजपा में जाने के बजाय धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के नाम पर राजद का दामन थाम लें. जीतन राम मांझी को अभयदान देकर लालू ने इस तरफ इशारा भी कर दिया है. राजद को लगता है कि अगर माय के बाद महादलित भी इसके खेमे में आ जाए तो फिर नरेंद्र मोदी के विजय रथ को बिहार में रोकना बेहद आसान हो जाएगा. देखा जाए तो वर्तमान राजनीतिक हालात में जीतन राम मांझी सभी के दुलरुआ होकर सामने आ गए हैं. अब यह जीतन राम मांझी को तय करना है कि इतने बड़े वोट बैंक के साथ वह किसकी झोली भरते हैं या फिर सारे कयासों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार का ही साथ देते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

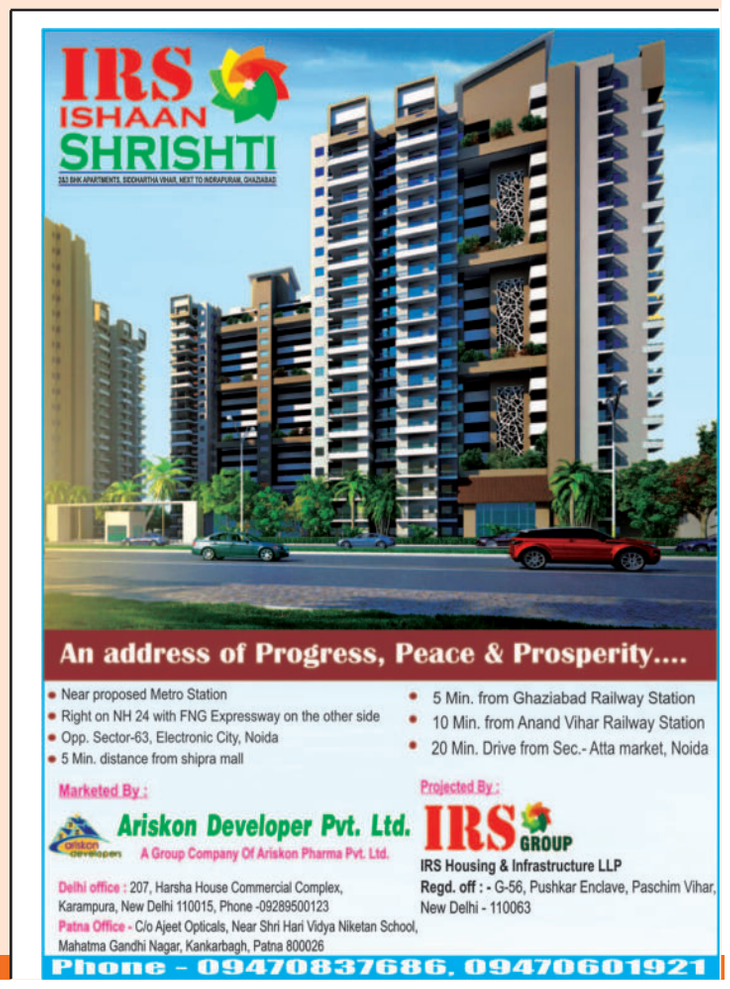

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

लोजपा का स्थापना दिवस

गोपालगंज जिला परिषद सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से पार्टी की 14 वीं स्थापना दिवस मनाया. कार्यक्रम की शुरुआत केक काट कर तथा एक दूसरे का मुंह मीठा कर की गई. इस मौके पर अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में लोजपा मजबूत है और इसे मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता गांव–गांव में संगठन का विस्तार करें. उन्होंने कहा कि चुनाव का बिगुल बजने वाला है. विधानसभा चुनाव में लोजपा दमदारी से लड़ेगी. जनता महागठबंधन सरकार से ऊब चुकी है. विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा, लोजपा , रालोसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी. इस अवसर पर जिला प्रभारी उपेन्द्र यादव ने भी अपने विचार रखे और पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया. इस अवसर पर डॉ. मोहम्मद इरकान, धर्मदेव सिंह, अबुल हसन, रामाशंकर प्रसाद सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे. –भारती

गन्ना मंत्री ने किया उद्घाटन

मां जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम एवं जानकी मंदिर, सीतामढ़ी, समेत अन्य स्थानों पर वृहद सीताराम विवाहोत्सव का आयोजन किया गया. सीता जन्म स्थली पुनौरा धाम में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन सूबे की गन्ना विकास मंत्री डॉ. रंजू गीता, जदयू नेता राजेश चौधरी, मंदिर के महंत कौशल किशोर दास, महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉ. ममता सिन्हा समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. मौके पर आयोजन समिति के मनोज कुमार सिंह, प्रबंधक अनिल कुमार, दिनेश चंद्र द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता सुशील कुमार सिंह, ऑल पूर्वांचल संघ के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह, भानू प्रसाद सिंह, आनंद बिहारी सिंह व श्रवण कुमार समेत अन्य थे. – ब्रजेश

महंत ने किया सम्मानित

जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम में आयोजित विवाहोत्सव समारोह के मौके पर पुनौराधाम मंदिर के महंत कौशल किशोर दास ने अतिथियों का सम्मान शॉल, जानकी प्राकट्य की तस्वीर देकर किया. कार्यक्रम में सम्मानित होने वालों में मंत्री डॉ. रंजू गीता, जदयू नेता राजेश चौधरी, महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉ. ममता सिन्हा, प्रो. अमर सिंह, बबलू मंडल, भवदेपुर श्रीराम जानकी मंदिर के महंत राम उदार दास, रेवासी महंत परमेश्वर दास, पुरनहिया महंत सह बिहार प्रदेश भारत साधु समाज के अध्यक्ष बृज विहारी दास, अवध किशोर दास, सुखराम दास, विमल शरण दास, दामोदर दास समेत अन्य थे. – वाल्मीकि

ऑल पूर्वांचल संघ ने किया सहयोग

सेवाभाव से परिपूर्ण ऑल पूर्वांचल संघ के संस्थापक सह सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर कुमार महतो ने विवाहोत्सव समारोह में अहम योगदान दिया. बतौर प्रतिनिधि संघ के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह ने कार्यक्रम के दौरान आयोजित सम्मान समारोह के लिए पुनौराधाम मंदिर के महंत कौशल किशोर दास को शॉल, गमछा भेंट किया. मौके पर महंत ने कहा कि सीता जन्म स्थली के प्रति संघ की श्रद्धा सराहनीय है. जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में संघ और भी कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग के लिए तैयार रहेगा. संघ के संस्थापक ने मां जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम को विश्व पर्यटन मानचित्र पर काबिज कराने को लेकर हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया. ■ – ब्रजेश

गया

मगध में लोजपा की मजबूत दावेदारी

अरवल, मखदूमपुर, बोधगया, टिकारी तथा नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी जीत कर गये थे. लेकिन तब बिहार का राजनीतिक समीकरण ठीक नहीं रहा, फलत: पुन: नवंबर 2005 मे बिहार विधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व मे एनडीए की जीत हुई थी. 2010 की विधानसभा चुनाव मे लोजपा का गठबंधन राजद से था. लोजपा बिहार के 75 सीटों पर लड़ी, जिनमें 48 स्थानो पर दूसरे स्थान पर आयी. मगध की सीटों पर भी लोजपा की स्थिति ठीक रही. गत लोकसभा चुनाव में लोजपा, राजद को छोड़ एनडीए का हिस्सा बना.

सुनील सौरभ

मगध की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है. लंबे समय तक घोशी विधान सभा क्षेत्र से विधायक तथा बाद मे जहानाबाद से सांसद रहे और चारा घोटले में सजाफ्याता होकर सांसदी गवां चुके जगदीश शर्मा ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा है. जगदीश शर्मा के पुत्र और जदयू से निष्काषित घोशी के विधायक राहुल कुमार का भी लोजपा में अब जाना तय माना जा रहा है. मगध की राजनीति में दिग्गज माने जाने वाले जगदीश शर्मा के लोजपा में आने से लोजपा और मजबूत होगी. एनडीए की भी मजबूती बढ़ेगी. ऐसे तो मगध मे लोकजनशक्ति पार्टी का दावा आठ से दस विधानसभा पर होगा. लेकिन आधा दर्जन विधानसभा पर तो दमदार दावेदारी होगी. 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में मगध की 26 मे पांच सीटों पर लोजपा प्रत्याशी की जीत हुई थी.

अरवल, मखदूमपुर, बोधगया, टिकारी तथा नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी जीत कर गये थे. लेकिन तब बिहार का राजनीतिक समीकरण ठीक नहीं रहा, फलत: पुन: नवंबर 2005 मे बिहार विधान सभा का चुनाव हुआ जिसमे नीतीश कुमार के नेतृत्व मे एनडीए की जीत हुई थी. 2010 की विधानसभा चुनाव मे लोजपा का गठबंधन राजद से था. लोजपा बिहार के 75 सीटों पर लड़ी, जिनमे 48 स्थानो पर दूसरे स्थान पर आयी. मगध की सीटों पर भी लोजपा की स्थिति ठीक रही. गत लोकसभा चुनाव में लोजपा, राजद को छोड़ एनडीए का हिस्सा बना. लोकसभा में लोजपा की स्थिति भी बहुत अच्छी रही. अब जबकि जगदीश शर्मा लोजपा मे आ गये हैं तो मगध मे इसकी मजबूती और बढ़ने की उम्मीद है. वहीं दूसरी ओर लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक सर्वजीत और बिहार प्रदेश संगठन सचिव अरविन्द कुमार सिंह की मेहनत की बदौलत ही लोजपा की आधा दर्जन विधान सभा क्षेत्र पर दावेदारी है. बोधगया से पूर्व सांसद स्व. राजेश कुमार के पुत्र सर्वजीत विधान सभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस सीट पर वर्तमान में भाजपा के श्यामदेव पासवान विधायक है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि भाजपा और लोजपा आपसी सहमति से बोधगया सुरक्षित और बाराचट्टी सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र की अदला–बदली कर सकती है. माना जाता है कि कुमार सर्वजीत चुनाव के दौरान अपने पिता पूर्व सांसद राजेश कुमार की इमामगंज में हत्या के बाद से किसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से लड़ना उचित नहीं मानते हैं. बोधगया विधानसभा क्षेत्र एक तरह से वे परंपरागत सीट मानते हैं. इनके पिता राजेश कुमार यहां से विधायक रह चुके थे. ऐसे तो पूरे मगध क्षेत्र मे कुमार सर्वजीत अपने जातीय वोट बैंक के अलावा मुस्लिम मतदाताओं को भी लोजपा के वोट बैंक बनाने का काम किया. इस बार लोजपा के एनडीए का हिस्सा बनने से भी भाजपा के वोट बैक का लाभ उसे मिलेगा. इन्ही सब को देखते हुए बोधगया सीट पर लोजपा की नजर है. जहानाबाद के घोशी से जदयू के निष्काषित और जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल कुमार विधायक हैं. यहां से लोजपा को टिकट मिलना तय है. जहानाबाद के मखदूमपुर सुरक्षित सीट पर भी लोजपा की दावेदारी हो सकती है. यहां से फिलहाल मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधायक है. अरवल से फरवरी 2005 मे लोजपा के दलारचंद यादव विधायक थे. यही कारण है कि यहां से भी लोजपा अपना हक जता रही है. गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र से फरवरी 2005 मे लोजपा प्रत्याशी के रूप में अनिल कुमार की जीत हुई थी बाद मे ये जदयू में शामिल हो गये थे. फिलहाल यहां से अनिल कुमार जदयू के विधायक हैं. इस सीट पर भी लोजपा की मजबूत दावेदारी है. बिहार प्रदेश लोजपा के संगठन सचिव अरविन्द कुमार सिंह को भी यहां से संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है. टिकारी विधान सभा क्षेत्र मे ही उनका गांव पड़ता है. समाजिक–राजनीतिक कार्य भी अरविन्द कुमार सिंह का टिकारी में अधिक हो रहा है. लोजपा का सदस्यता अभियान हो या कोई भी कार्यक्रम अरविन्द सिंह का जुड़ाव टिकारी से अधिक है. इसीलिए लोजपा टिकारी सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी कर सकती है. विपरीत राजनीतिक परिस्थिति में भी लोजपा के साथ रहने तथा गया जिलें मे युवा लोजपा अध्यक्ष के रूप में अच्छा कार्य करने के कारण ही लोजपा द्वारा टिकारी सीट पर अरविन्द सिंह को लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है. इसी प्रकार औरंगाबाद के नवीनगर विधान सभा क्षेत्र से भी लोजपा की दावेदारी हो सकती है.क्योंकि यहां से विजय सिंह उर्फ डब्लू सिंह विधायक रह चुके हैं. पिछले विधानसभा चुनाव मे भी यहां इनकी अच्छी स्थिति रही थी. इसके अलावा औरंगाबाद के रफीगंज से भी लोजपा अपना दावा कर सकती है. बिहार विधान सभा चुनाव के हिसाब से ही एनडीए मे शामिल लोजपा पूरे मगध में राजनीति कर रही है. जगदीश शर्मा के लोजपा मे आने से मगध में एनडीए और मजबूत होगा, इसमे कोई शक नही है. लोजपा के चल रहे सदस्यता अभियान मे भी मगध में कम से कम दस लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है. सारी परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मगध में लोजपा एनडीए का एक मजबूत साथी के रूप में नजर आयेगा विधान सभा चुनाव में.■

बोध गया विधानसभा क्षेत्र एक तरह से वे परंपरागत सीट मानते है. उनके पिता राजेश कुमार यहां से विधायक रह चुके थे. ऐसे तो पूरे मगध क्षेत्र मे कुमार सर्वजीत अपने जातीय वोट बैंक के अलावा मुस्लिम मतदाताओं को भी लोजपा के वोट बैंक बनाने का काम किया. इस बार लोजपा के एनडीए का हिस्सा बनने से भी भाजपा के वोट बैंक का लाभ उसे मिलेगा.

feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण शुरू

प्रखंड के माधवपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय परिसर से नजदीक आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण कार्य की आधारशिला जिला परिषद सदस्य पिंकू देवी के हाथों रखी गई. जिला परिषद सदस्य ने कहा कि मध्य विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 161 के लिए भवन बनेगा. जिसमें वार्ड नंबर 7 और 8 के बच्चे आकर इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द भी भवन बनकर तैयार हो जायेगा. जो बच्चे झोपड़ी में तथा यत्र तत्र भटक कर शिक्षा अध्ययन करते थे. अब उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का लाभ मिलेगा. उनके भटकने की मजबूरी अब समाप्त हो गई है. उन्होंने कहा कि बच्चों की कठिनाइयों को देखते हुए उठाया गया यह कदम है. जबकि भाजपा नेता अखिल कुमार राय उर्फ मंटू राय ने अपने संबोधन में कहा कि अब बच्चों की परेशानी भवन बन जाने से दूर होगी. किन्तु इसमें सभी लोगों के अहम सहयोग की जरूरत है. ताकि यह भवन ससमय बन कर तैयार हो जाये. इस मौके पर मुरलीधर सिंह, वंशीधर सिंह, रामविलास राय, संजीव कुमार झा, रामनिवास राय, नवीन राय, रविन्द्र ठाकुर, माधो ठाकुर, प्रियदर्शी चितरंजन, विधान कुमार, रंगीला सिंह, नन्दन सिंह, सुनिल कुमार झा सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे. – गीता कुमार

सड़कों का शिलान्यास

ग्रामीण कार्य विभाग की योजना के तहत 87 लाख की लागत से बनने वाली गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र के तेतरी पकरा 14 नंबर सड़क से लक्ष्मीपुर मंडल टोला तक 665 मीटर सड़क निर्माण तथा पचगछिया में जनार्दन साह के घर से मुस्लिम टोला तक 680 मीटर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास गोपालपुर के विधायक नरेन्द्र कुमार नीरज ने किया. इस मौके पर जदयू के सीताराम मंडल, मुन्ना जायसवाल, गौतम यादव सहित सैकघें लोगों की मौजूदगी में विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में सघ्क, पुल, पुलिया का जाल बिछ गया है. विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है. अब गांवों कि एक भी सघ्क कच्ची नहीं बचेगी. दुर्गम दियारा तक के क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया गया है.

स्वच्छता जागरूकता अभियान

क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत–स्वास्थ भारत' संकल्प के तहत नवगछिया नगर में एक माह से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें शामिल युवाओं द्वारा इस रविवार को महाराजजी चौक से जनकसिंह रोड, मुमताज मोहल्ला, शहीद टोला, गरीबदास ठाकुरबाड़ी रोड में स्वच्छता अभियान चलाया. इस स्वच्छता जागरूकता अभियान में श्रीधर, अशोक केडीया, विक्की भूडोलिया, छोटू भगत सहित दर्जनों युवाओं के अलावा जिला 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, मुन्ना भगत, सोनी इकराम सहित गौशाला सचिव रामप्रकाश रुंगटा, मारवाधी युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र वर्मा एवं नगर पंचायत कर्मियों की सक्रियता रही.

निशान शोभा यात्रा आयोजित

बाबा गणिनाथ गोविंद धाम खरीक के लिए नवगछिया से पैदल निशान शोभा यात्रा निकाली गयी. चौती दुर्गा स्थान से निकली यह पैदल निशान शोभा यात्रा मेन रोड, स्टेशन रोड, आसाम रोड, चौदह नंबर रोड व तुलसीपुर के रास्ते खरीक स्थित बाबा गणिनाथ गोविंद धाम पहुंची. इस निशान शोभा पद यात्रा में आशीष कुमार साह, बजरंग साह, पंकज साह, सुमित साह, शंभू साह, जितेंद्र, चीकू, पवन, मंजु देवी सहित सैकड़ों पुरुष तथा महिलाएं हाथों में रंग बिरंगे निशान लिए शामिल थी. जिनका धाम पर पहुंचते ही आयोजन समिति के अध्यक्ष शंकर साह, निरंजन साह, दिनेश साह, राज कुमार साह, राजीव कुमार साह के अलावा बिहपुर के विधायक कुमार शैलेंद्र द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया. मौके पर वैश्य समाज का अधिवेशन सम्पन्न हुआ.

कैंसर जागरूकता रैली निकली

मारवाड़ी युवा मंच तथा एचडीएफसी बैंक की नवगछिया शाखा के सौजन्य से नौ स्कूलों के बच्चों द्वारा नवगछिया में कैंसर जागरूकता रैली निकाली गयी. जिसे अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. इन छात्रों के हाथों में स्लोगन युक्त तख्तियां थी. जिसपर लिखा था–जिंदगी चुनो–तंबाकू नहीं, धूम्रपान निषेध, तंबाकू जान लेवा है, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकर है. इस कैंसर जागरूकता रैली में बाल भारती, बाल भारती विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, अरविंद मेमोरियल स्कूल, इंटर स्तरीय रुंगटा बालिका विद्यालय, राजकीय श्री लक्ष्मी कन्या मध्य विद्यालय तथा सावित्री पब्लिक स्कूल के छात्र बड़ी संख्या में शामिल देखे गए. मंच के प्रादेशिक अध्यक्ष सुभाष चंद्र वर्मा, शाखा अध्यक्ष अरविंद चौधरी, सचिव निखिल चिरानिया, वरुण केजरीवाल, प्रभात पंसारी, मनोज चौधरी, राज चौधरी, शंभू सर्राफ, कमल टिबरेवाल, सौरभ नारनोली, संदीप चिरानिया, विशाल चिरानिया, सुमित वर्मा के अलावा एचडीएफसी बैंक के शाखा प्रबन्धक मनीष आचार्य, विक्रय पदाधिकारी अविनाश शर्मा और मदन झा भी शामिल रहे. – राजेष कनौडिया

25 कन्याओं का सामुहिक विवाह होगा

चंपारण लोक सांस्कृतिक महोत्सव सह 25 कन्याओं सामुहिक विवाह कराने को ले आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संरक्षक मंडल के सदस्य पंडित चन्द्रकिशोर मिश्रा के आवास पर हुई जिसमें अनेक महत्वपूर्ण विन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. बैठक में आगामी एक फरवरी को नगर भवन के मैदान में यह समारोह करने व इसे ऐतिहासिक बनाने पर बल दिया गया. बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि आदर्श लोक सांस्कृतिक धरोहर एवं सामाजिक सुधार के साथ–साथ आपसी सौहार्द कायम रखना हमारी प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित है. इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष मुन्ना गिरी ने समारोह की रूप रेखा प्रस्तुत की. बैठक की अध्यक्षता प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. परवेज ने की जबकि मौके पर प्रो. अरुण मिश्रा, रवि नारायण राम, अमित सेन, धर्मवीर प्रसाद, डॉ. लालबाबू प्रसाद, अमरेन्द्र सिंह, राजा ठाकुर, विन्टी शर्मा, रिपुसूदन तिवारी, प्रभात शर्मा, सागर सूरज, प्रभात प्रभाष सिंह, राजन मिश्रा, सुदिष्ट नारायण ठाकुर, राकेश रौशन, अमर नाथ पाण्डेय, सब्लू श्रीवास्तव, प्रभात सिंह, सरोज यादव, सुनील गिरी, संजू गिरी, अनिकेत पाण्डेय, संजय मिश्रा, प्रमोद तिवारी, संजय वर्मा, संजय उपाध्याय, हरेन्द्र रजक, विजय पाण्डेय, रमेश पंडित, मुन्ना द्विवेदी, संजय सिंह समेत बड़ी संख्या में आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे.

साईबर व्यवसायी संघ का हुआ गठन

साईबर व्यवसाय में मूल्यों का उतार–चढाव, असुरक्षा, साईबर सामग्रियों में बढ़ती हुई महंगाई की मार से साईबर व्यवसाय में हो रहे घाटे को देखते हुए जिले के समस्त साईबर व्यवसायियों ने एमएस कॉलेज रोड स्थित मुन्ना साईबर संस्थान में बैठक कर चंपारण साईबर एसोशिएसन का गठन किया. इस गठन में सर्वसम्मति से फेसबुक साईबर कैफे के संचालक अधिवक्ता विनय कुमार इपाध्याय को अध्यक्ष, मुन्ना साईबर कैफे के संचालक प्रो0 राम कुमार सिंह को सचिव और सौम्या साईबर कैफे के संचालक प्रो. मनोज कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया, और एक छह सदस्यीय आईटी सेल का गठन किया गया. उक्त बैठक में उपस्थित साईबर व्यवसाईयों में रवि कुमार, आषीष वर्मा हिमांषु पाण्डेय, मनोज कुमार, विभाष रंजन पांडेय, अमित कुमार, राज कुमार, राजन श्रीवास्तव, मनीष कुमार, अविनाष कुमार, रामानंद कुमार, आषुतोष कुमार, विवके कुमार, नितेष जायसवाल, कुणाल प्रताप, प्रदीप पंडित, षिबू कुमार, एआर भारद्वाज, पंकज कुमार, ब्रज किषोर प्रसाद, धीरेन्द्र कुमार शर्मा, मदनाकर कुमार, रविन्द्र कुमार आदि ने अपनी उपस्थिति और सहभागिता दर्ज की. – इन्तेजारूल हक

किसानों को किया सम्मानित

इस बार के धान फसल में चतरा जिला के हंटरगंज प्रखण्ड के कटैया गांव में नुजीवीड सिडस ने सभी हाई ब्रिड धानों को मात दे दी है. इसका प्रर्दशनी किसानों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया इस परदर्शणी के लिये कम्पनी के मार्केटिंग अफसर कुन्दन कुमार , पप्पु कुमार गुप्ता, को जाती है. कम्पनी ने किसानों के बीच अच्छे इत्पादन होने के कारण प्रथम पुरस्कार कंबल, दुसरा पुरस्कार घंड़ी एवं तीसरे पुरस्कार स्प्रे–मशीन दिया गया इस किसान गोष्टि में कटैया पंचायत के मुखिया सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, पंचायत समिति शिवशंकर यादव, तारवागडा पंचायत के मुखिया दिलिप दास सभी ग्रामीणों एवं किसान इपस्थित थे.■ – चौथी दुनिया ब्यूरो

बेगूसराय

गुटबाजी को हवा दे गए अशोक चौधरी

बेगूसराय जिले की पृष्ठभूमि कांग्रेस-भाकपा की रही है. पूर्व में कांग्रेस की एक गलती ने जिले में कांग्रेसियों की कमर तोड़ दी. बात 1957 के विधान सभा चुनाव की है. कांग्रेस पार्टी ने जिले के कद्दावर नेता राम चरित्र सिंह को पार्टी के सर्वाधिक मजबूत गढ़ तेघड़ा विधन सभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया. जबकि वे सरकार में सिंचाई तथा बिजली मंत्री थे. वे तपे-तपाये धाकड़ कांग्रसी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे. जब तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र से पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा.

सुरेश चौहान/संदीप कुमार

पहले से ही पार्टी के अंदर व्याप्त गुटबाजी को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने दी हवा. पिछले दिनों बेगूसराय का दौरा कर चौधरी ने पार्टी के स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे अन्तर्विरोधों में 'आग में घी' डालने जैसा कार्य किया. अभी तक पार्टी की गुटबाजी खुलकर सतह पर नहीं आ पायी थी. अन्तर्विरोध के बावजूद जिले के नेता एवं कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रमों में पूरे दमखम से शिकरत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए शक्ति प्रदर्शन करते आ रहे थे. लेकिन चौधरी के आगमन ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के अन्दर व्याप्त गुटबाजी को जगजाहिर कर दिया. जिले के मूर्धन्य नेताओं को कार्यक्रम की विधिवत जानकारी नहीं देकर चौधरी ने गुटबाजी को पाटने की बजाय अलगाव की दूरी को अत्यधिक बढ़ा दिया.चौधरी के इस आचरण से जिले के कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का न सिर्फ मनोबल टूटा है बल्कि वे अचंभित हैं कि जब प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के अन्दर गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं तो पूर्व से जारी अन्तरविराध को कैसे पाटा जाएगा?

ज्यों–ज्यों बिहार विधान सभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी इसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है. कांग्रेस पार्टी का प्रदेश आलाकमान पूर्व की भूल से सबक लेने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा है. बेगूसराय जिले की पृष्ठभूमि कांग्रेस–भाकपा की रही है. पूर्व में कांग्रेस की एक गलती ने जिले में कांग्रेसियों की कमर तोड़ दी. बात 1957 के विधान सभा चुनाव की है. कांग्रेस पार्टी ने जिले के कद्दावर नेता राम चरित्र सिंह को पार्टी के सर्वाधिक मजबूत गढ़ तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया. जबकि वे यहां से सीटिंग विधायक एवं सरकार में सिंचाई तथा बिजली मंत्री थे. वे तपे–तपाये धाकड़ कांग्रसी नेता एवं स्वतंत्राता सेनानी थे. जब तेघड़ा विधान सभा क्षेत्रा से पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित कांग्रेसियों ने सूर्यनारायण पोद्दार, रामजी लाल, वैद्यनाथ सुल्तानियां, रामदेव राय, विजय नन्दन प्रसाद नारायण सिंह , नुनूलाल पोद्दार, केदार नारायण सिंह आदि के नेतृत्व में राम चरित्र बाबू को तेघड़ा विधन सभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा और उनकी शानदार जीत हुई. इसका प्रभाव यह हुआ कि आजतक तेघड़ा–बरौनी विधनसभा क्षेत्रा से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत नहीं पाया है. धीरे–धीरे जिले की सातों विधान सभा सीट कांग्रेस के हाथ से खिसकती चली गयी और पार्टीजनों के अन्तर्कलह का लाभ अन्य दलों को मिलता गया.

वर्तमान में भंग जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन, पूर्व सांसद रामदेव राय, पूर्व जिलाध्यक्ष शांति स्वामी, प्रदेश महिला सेल की अध्यक्ष अमिता भूषण, राम बदन सिंह, संजय कुमार (मोसादपुर), सुबोध कुमार एवं संजय कुमार (बरौनी), सुबोध कुमार सिंह (रामदीरी), लखन पासवान, राम प्रकाश सिंह, रामानन्द सिंह (रतनपुर), शमशू जोहा, महेश कुमार (मोहनपुर) अधिक्ता अमीर सिंह, मदन प्रसाद सिंह एवं शिवनन्दन सिंह, मुरलीधर मुरारी, मिथिलेश झा, शकुन्तला गुप्ता, अनुपम कुमार अन्नु, राकेश कुमार सिंह, चुनचुन राय, रामनाथ महतो, राम सरोवर आदि कांग्रेस के ध्वजवाहक माने जाते हैं. पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने बेगूसराय आए. शहर के रतनपुर सार्वजनिक धर्मशाला के प्रांगण में समारोह आयोजित कर सदस्यता अभियान की शुरुआत चौधरी ने की. इस अवसर पर पार्टी की सदस्यता अभियान के प्रभारी निवर्तमान जिलाध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन, पूर्व सांसद रामदेव राय, पार्टी नेता राम विलास सिंह, मिथिलेश झा सहित अन्य वरीय नेता उपस्थित नहीं थे. पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं को कार्यक्रम की विधिवत सूचना नहीं दी गयी.

पार्टी के एक महासचिव का कहना है कि चौधरी के इस कदम से जिले में कांग्रेस की मजबूत नींव कमजोर हुई है, जिसका प्रभाव आगामी विधनसभा चुनाव पर पड़ सकता है. जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के इस कदम की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं बिहार प्रभारी को दे दी है. जिले के अधिकांश कांग्रेसियों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के इस व्यवहार से पूर्व से जारी अन्तरविरोध को बल मिला है. समय रहते यदि इससे नहीं पाटा गया तो इसका प्रभाव आगामी विधान सभा चुनाव पर पड़ सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

विदेशी बौद्ध धर्म गुरु ने स्वच्छता अभियान को जरूरी बताया

सुनील सौरभ

दुनिया के दर्जन भर के देशों में 110 बौद्ध मंदिर व मठ की स्थापना करने वाले लाओस के बौद्ध धर्मगुरु डॉ. फमाहा चंदाफोन चक्कावारों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान को देश व दुनिया के लिए फायदेमंद बताया. पिछले दिनों बोधगया आये बौद्ध धर्मगुरु ने कहा कि दुनिया में शांति, सद्भावना, भाईचारे के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाये गया स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा है. डॉ. चक्कावारो बोधगया स्थित लाओस पीडीआर बौद्ध मठ के भी इंचार्ज है. इस मठ की स्थापना भी उन्होंने ही की थी. उन्होंने कहा कि बुद्ध आज भी पूरी दुनिया मे प्रासंगिक हैं.

यही कारण है कि बुद्ध के दर्शन को अपनाने वालों की संख्या में दिनों–दिन बढ़ोतरी हो रही है. अमेरिका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, लाओस और भारत समेत अन्य कई छोटे–छोटे देशों में करीब 110 बौद्ध मंदिर व मठ स्थापित करने वाले चर्चित बौद्ध धर्म गुरु डॉ. फमाहा चंदाफोन चक्कावारो पूरी दुनिया में घूम–घूम कर लोगों को बौद्ध दर्शन के बारे में बताते हैं. उन्होंने कहा कि उनके कार्यक्रमों व प्रवचन में बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्मों को मानने वाले भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं. चौथी दुनिया से विशेष रूप से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि बौद्ध धर्म को अंगीकार करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, असल में देखने की बात यह है कि बुद्ध के संदेश, दर्शन व जीवन से संबधित बातों को सुनने व उसका अनुपालन करनेवालों की संख्या कितनी है. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी (वर्जिनिया) में वाट लाओ बुद्धाबोंग बौद्ध मठ की स्थापना करने वाले डॉ. चक्कावारो ने बताया कि अमेरिका में दस लाख से अधिक लाओस के लोग रहते है. यही कारण है कि अमेरिका में बौद्ध मंदिरो की संख्या भी बहुत है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया घूमने पर ऐसा लग रहा है कि अब बुद्ध दर्शन किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए जरूरी बन चुका है. उन्होंने कहा कि बोधगया गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. बोधगया में आनेवाले बौद्ध श्रद्धालुओं व अन्य देशी–विदेशी पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं कम हैं. यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए और अधिक सुविधाएं होनी चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

भूख हडताल

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरशन के आधा दर्जन कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड अंतर्गत हरिबेला गांव में भूख हडताल की. 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में एआइएसएफ के राज्य पार्षद सदस्य सुशील उमाराज, जिला कार्यकारिणी सदस्य पप्पू कुमार, छात्र अभिषेक कुमार, विकास कुमार व मंटू कुमार समेत अन्य थे. भूख हड़ताल के चौथे दिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण विचार केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष आफताब अंजुम बिहारी ने कार्यक्रम स्थल पहुंच कर मांगों का समर्थन किया.

शिविर में दिया कृत्रिम पैर

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मां जानकी जन सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में तीन दिवसीय कृत्रिम पैर प्रत्यारोपन शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का उद्घाटन नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू ने किया. सीतामढ़ी शहर स्थित कोट बाजार के खेमका हॉस्पीटल में आयोजित शिविर में नेपाल के अलावा बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर व पूर्वी चंपारण समेत अन्य जिलों के करीब 1 सौ जरूरतमंदो को कृत्रिम पैर उपलब्ध कराए गए. मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष राधे श्याम मिश्र, संरक्षक डॉ. एंकर प्रसाद खेतान, सदर एसडीपीओ एमएन उपाध्याय, सचिव सज्जन हिसारिया, संयोजक राजेश कुमार सुंदरका, शिव कुमार अग्रवाल, सह संयोजक नीरज कुमार गोयनका, संरक्षक राम प्रसाद सर्राफ, शिव कुमार प्रसाद, अजय विद्रोही, डॉ. विजय सर्राफ, पंकज गोयनका, गणेश प्रसाद स्वर्णकार, मंटू सुंदरका, राजेंद्र प्रसाद, कांतिलाल शसर्मा, पवन हिसारिया, प्रदीप डालमिया, शिव कुमार खेमका, सुरेश हिसारिया, नरोत्तम व्यास, मोहन शर्मा, काली चरण व्यास, दीपक चौमाल, अभिषेक सुंदरका, केदार प्रसाद, अभिषेक तिवारी व पुष्पेंद्र सिंह समेत अन्य थे. – वाल्मीकि

सड़कों का बिछेगा जाल

गोगरी के फतेहपुर में जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने एक साथ तीन सड़कों का उद्घाटन किया. शिशवा गांव में मेन रोड से हुकुमलाल यादव के घर तक जाने वाली दो लाख बत्तीस हजार आठ सौ की लागत से तेरहवें वित्त आयोग से पीसीसी सड़क का उद्घाटन सर्व प्रथम किया गया. इसके बाद बरेटा गांव में मेन रोड से बीजो यादव के घर तक जाने वाली सात लाख पचास हजार की लागत से पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया गया. फतेहपुर में मेन रोड से होली मिशन स्कूल तक जाने वाली दो लाख चार हजार आठ सौ की लागत से पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया गया. वहीं होली मिशन स्कूल में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूं. पूर्व मुखिया कृष्णा यादव ने जिला परिषद अध्यक्ष से फतेहपुर अभिशाप के रूप में माने जाने वाले 1914 ईस्वी में बने स्कूल के लिए जमीन नहीं होने के कारण स्कूल का विकास अवरुद्ध होने की बात कही. इस अवसर पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष कैलाश चन्द्र यादव, पूर्व समिति सदस्य विजय कुमार यादव, मनोज कुमार यादव, प्रमुख प्रतिनिधि संजय यादव, राजेश कुमार झा, जदयू के मिडिया प्रभारी गौतम सुमन, मो. इम्तियाज, सुरेन्द्र सिंह,रितेश सिन्हा, विष्णुदेव यादव, सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

अतिक्रमित जमीन कराया मुक्त

गोगरी अनुमंडल क्षेत्राधीन अररिया गांव इस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया जब अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए पुलिस पहुंची. मामला यह है कि अररिया निवासी विभषण यादव की जमीन को अवैध कब्जा कर गांव के ही कुछ लोग दखल किये हुए थे. जिसे हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के अररिया गांव पहुंचते ही ग्रामीणों में भय समा गया. लेकिन परबत्ता सीओ व पुलिस इंस्पेक्टर तारणी प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 3–4 वर्ष से अवैध कब्जे वाली जमीन को भूस्वामी को कब्जा दिलाया गया. परबत्ता के सीओ शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा अवैध कब्जा को नहीं हटाया जा रहा था. कई बार नोटिस देने के बाद भी कब्जाधारी द्वारा जमीन खाली नहीं की गई. वहीं पुलिस इंस्पेक्टर तारणी प्रसाद सिंह ने बताया कि लगभग तीन बीघे जमीन पर कई वर्षो से विवाद चल रहा था. दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा एक बीघा सात कट्ठा जमीनपन पर झोपड़ी व वासा बनाकर जबरन कब्जा कर लिया गया था तथा शेष जमीन पर खेती की जाने लगी. कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जाधारी से उक्त जमीन को मुक्त कराया गया और भूस्वामी को कब्जा दिलाया गया. मौके पर मड़ैया थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, परबत्ता थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार, पसराहा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार यादव सहित दर्जनों पुलिस कर्मी उपस्थित थे.

एसपी ने किया टूर्नामिन्ट उद्घाटन

खाली मन शैतान का होता है. इसलिए मनुष्य को हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहना चाहिए. लोग अपने समय का उपयोग सृजनात्मक कार्य में करें. जिससे न सिर्फ इनका ही बल्कि समाज व देश का भी विकास होगा. क्योंकि खाली बैठना नकारात्मक सोच को जन्म देता है. उक्त बातें एसपी किम ने गोगरी के मुश्कीपुर जनता मैदान में आयोजित अंतराष्ट्रीय फुटबॉलर स्वर्गीय विधानचंद्र मिश्रा की स्मृति में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर कही. उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक व मानसिक विकास होता है. इस तरह के खेल आयोजन से लोगों में भी सकारात्मक सोच के साथ सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है. मैच का विधिवत उद्घाटन एसपी किम ने फीता काटकर किया. इसके बाद मानसी व समस्तीपुर टीम के महिला खिलाड़ियों के साथ परिचय कराया गया. एसपी ने कबूतर उड़ाकर लोगों को शांति का संदेश दिया. इसके पूर्व एसपी किम, एसडीओ संतोष कुमार, एएसपी विमलेश चन्द्र झा, डीएसपी संजय कुमार झा, पुलिस इंस्पेक्टर तारणी प्रसाद सिंह, परबत्ता थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार, पसराहा थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव एवं माधव कुमार आदि ने विधान चन्द्र मिश्रा के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

कंबल वितरण

परबत्ता प्रखंड के परबत्ता पंचायत स्थित राजभज नगर करना में युवा समाजसेवी सह जदयू जिला महासचिव मुकेश कुमार के द्वारा अपने आवास परिसर में अपने निजी मद से करना समेत आसपास के निसहायों, विकलांगो तथा विधवाओं के बीच कंबल का वितरण किया. इस अवसर पर जदयू नेता मिथीलेश कुमार शास्त्री , अतुल कुमार, तेजनारायण सिंह, महेन्द्र सिह आदि ने भी अपने अपने हाथों से कंबल का वितरण किया. सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से मुकेश कुमार के द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है तथा अन्य कार्यों में भी गरीबों के बीच हाथ बंटाया जा रहा है. उन्हें आने वाले समय में गरीबों की सेवा की फल अवश्य ही मिलेगा. वहीं वक्ताओं ने कहा कि इससे समाज में भाईचारा बढ़ेगा और हम ऐसे निसहाय के दुख और सुख में उनके साथ खड़े रहेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा. कंबल वितरण के बाद गरीबों को भोजन भी कराया गया. ■ – गीता कुमार

सीतामढ़ी

> जहां तक सीतामढ़ी जिले का सवाल है तो इस बार तकरीबन सभी दलों के संभावित प्रत्याशियों की बोलती बंद है. सूबे बिहार में चल रही गठबंधन की राजनीति ने उनकी मंशा को अधर में लटका दिया है. गठबंधन के तहत कौन सीट किस दल के पाले में जायेगी फिलहाल कहना मुश्किल हो रहा है. ऐसी स्थिति में किसी भी दल से कोई मुखर होकर बोलने को तैयार नहीं है. पिछले दिनों सीतामढ़ी शहर के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी का 14 वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया.

तैयारी में लगे चुनावी दंगल के वैश्य पहलवान

अब तक के चुनावी नतीजों को अगर जातीय आधार पर देखा जाये तो एक बार यादव व तीन बार अल्पसंख्यक के बाद सीतामढ़ी सीट की कमान वैश्य बिरादरी के हाथ में ही रहा है. नतीजा है कि अब वैश्य बिरादरी को इस सीट से ऐसा मोह हो गया है कि वे किसी भी सूरत में इस सीट का कमान वैश्य प्रतिनिधि के हाथ में ही देखना चाह रहे हैं. बताया जाता है कि अब वे भी परिवारवाद की जगह वैश्यवाद को स्थापित करने का मन बनाने लगे हैं.

भरत प्रसाद

अमरनाथ गुप्ता

किरण गुप्ता

मनोज कुमार शक्ति

रामशंकर प्रसाद

सुनील कुमार पिंटू

वाल्मीकि कुमार

सन 1977 में सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर राम सागर राय को विधायक बनने का मौका मिला था. इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या अधिक रहने का फायदा शुरुआती दिनों में कांग्रेस को ही मिला. वर्ष 1980 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर पीर मोहम्मद अंसारी तो 1985 में कांग्रेस की टिकट पर खलील अंसारी को विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था. वर्ष 1990 में पहली बार गैर कांग्रेसी शाहिद अली खान ने जनता दल की टिकट पर इस क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफलता पायी थी और यहीं से यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकली तो फिर अब तक वापस नहीं मिल सकी है. वर्ष 2000 से लेकर अब तक लगातार इस सीट पर भाजपा कब्जा जमाते आ रही है. पूर्व भाजपा विधायक हरि शंकर प्रसाद के निधन के बाद हुए उप चुनाव में उनके पुत्र सुनील कुमार पिंटू को भाजपा ने चुनावी समर में उतारा था. तब से वे लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं.

अब तक के चुनावी नतीजों को अगर जातीय आधार पर देखा जाये तो एक बार यादव व तीन बार अल्पसंख्यक के बाद सीतामढ़ी सीट की कमान वैश्य बिरादरी के हाथ में ही रहा है. नतीजा है कि अब वैश्य बिरादरी को इस सीट से ऐसा मोह हो गया है कि वे किसी भी सूरत में इस सीट का कमान वैश्य प्रतिनिधि के हाथ में ही देखना चाह रहे हैं. बताया जाता है कि अब वे भी परिवारवाद की जगह वैश्यवाद को स्थापित करने का मन बनाने लगे हैं. विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पर गौर करने वालों की मानें तो वर्तमान में अन्य को छोड़ वैश्य बिरादरी के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग सीतामढ़ी विधानसभा सीट से बतौर प्रत्याशी दावेदारी को तैयार है. चल रही चुनावी चर्चाओं पर भरोसा करें तो बिहार में एनडीए गठबंधन में दरार के बाद कई लोग मुखर होकर अपनी दावेदारी को तैयार होने लगे हैं. बताया जाता है कि सीतामढ़ी सीट से चुनावी समर में भाग्य आजमाने के लिए भाजपा से वर्तमान विधायक सुनील कुमार पिंटू के अलावा पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामा शंकर प्रसाद एवं भाजपा क्रीडा मंच के जिलाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी व प्रवक्ता मनोज कुमार शक्ति भी प्रदेश से लेकर दिल्ली दरबार का आशीर्वाद पाने को बेकरार हैं. जबकि जदयू से पार्टी नेता भरत प्रसाद के अलावा डॉ. अमरनाथ गुप्ता व किरण गुप्ता भी जोर आजमाइश कर रही हैं. हालांकि भाजपा के रामा शंकर प्रसाद सीतामढ़ी के अलावा शिवहर तो जदयू की किरण गुप्ता रीगा सीट पर भी अपनी पैनी नजर रख रहे हैं. उक्त सभी संभावित प्रत्याशी वैश्य बिरादरी से ही आते हैं.

कुल मिला कर देखा जाये तो पार्टी चाहे कोई हो परंतु सीतामढ़ी सीट वैश्य बिरादरी के हाथ में हो, इसको लेकर घेराबंदी अब से ही की जाने लगी है. सूबे बिहार में चल रही गठबंधन की राजनीति पर अगर गौर करें तो भाजपा को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जदयू व राजद के अलावा कांग्रेस से सीधे मुकाबले की नौबत आ सकती है. ऐसी स्थिति में भाजपा नेतृत्व अगर वर्तमान विधायक सुनील कुमार पिंटू को ही एक और मौका देती है तब जदयू गठबंधन को सीतामढ़ी सीट पर जवाबी चुनावी हमले के लिए किसी मजबूत वैश्य के अलावा सवर्ण, यादव अथवा अल्पसंख्यक प्रत्याशी को ही सामने लाना होगा. कारण कि वैश्य बिरादरी का वही प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में बाजी मार सकता है जो बिरादरी के अलावा अन्य वोटों में सेंधमारी करने में सफल होगा. यही हाल सवर्ण, यादव अथवा अल्पसंख्यक प्रत्याशी के लिए भी उपयुक्त माना जा रहा है. कारण कि केवल वैश्य मत ही निर्णायक नहीं रही है, वैश्य के साथ सवर्ण व यादव मतों की भूमिका अहम मानी गयी है. चर्चा है कि सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से कुछ अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र को नये समीकरण में बाजपट्टी विधानसभा में समाहित कर दिया गया है, जिसके कारण अल्पसंख्यक इस क्षेत्र में कुछ कमजोर हुए हैं. परंतु चर्चा यह भी चल रही है कि अगर अल्पसंख्यक, यादव व सवर्ण की एकजूटता अन्य के साथ बनी तो किसी के लिए भी चुनावी राह आसान नही होगी. वैसे अभी चुनाव का समय आने में देरी के कारण जातीय सम्मेलनों व बैठकों का दौर चलना बाकी है.

अब जदयू व भाजपा गठबंधन पर भी चर्चा जरूरी प्रतीत होने लगा है. गठबंधन के तहत भाजपा की इस सीट पर मुकाबला के लिए जदयू के अलावा राजद व कांग्रेस से भी संभावित दावेदारों के नाम आने की संभावना है. जिसमें सवर्ण व अल्पसंख्यक के अलावा यादव, व पिछडा भी हो सकता है.

लोकसभा चुनाव में कुशवाहा प्रत्याशी की जीत के बाद अब इस बिरादरी में भी राजनीति जोर पकड़ रही है. संभव है कि इस बिरादरी के लोग भी अपनी दावेदारी देंगे. चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू है. अब देखना है कि सीतामढ़ी सीट पर वैश्य बिरादरी के अलावा और किस-किस जाति से संभावित प्रत्याशी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं. अब तक जो चुनावी चर्चा छन कर आ रही है. उसमें भाजपा, रालोसपा व लोजपा गठबंधन को सबक सिखाने को लेकर जदयू, राजद, कांग्रेस गठबंधन ने जोरदार घेराबंदी की ठानी है. जबकि भाजपा गठबंधन को लोकसभा चुनाव की तरह ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी सफलता की हरियाली नजर आ रही है. मतलब यह कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा-जदयू गठबंधन का सीधा संग्राम सीतामढ़ी सीट पर होने की पूर्ण संभावना है.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी में लोजपा के बड़े ख्वाब

बिहार विधानसभा चुनाव का समय करीब आने के साथ ही सीतामढ़ी जिले में राजनीतिक पारा चढ़ना शुरू हो गया है. वर्ष 2015 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के दावेदार अपने ठिकानों से निकल कर सामने आने लगे हैं. सीतामढ़ी जिले में पिछले दिनों संपन्न लोक जनशक्ति पार्टी के 14 वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में लगभग यह साफ हो गया है कि अबकी बार जिले में लोजपा एक अथवा दो सीटों पर मानने वाली नहीं है. सबको पता है कि विधानसभा चुनाव भाजपा गठबंधन के तहत लड़ा जायेगा, जिसमें टिकट व सीटों के बंटवारे में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का फैसला अहम होगा. बावजूद इसके टिकट के दावेदारों ने सीट पर अपरोक्ष रूप से कब्जा शुरू कर दिया है.....

वाल्मीकि कुमार

feedback@chauthiduniya.com

एक बार फिर चुनावी मौसम के आगमन से पूर्व ही नेताओं का महफिल सजना शुरू हो गई है. आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण माहौल में पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला कर चुनावी खुराक दिया जाने लगा है. कमोवेष यह हाल तमाम राजनीतिक दलों का है. कोई यात्रा तो कोई जयंती के बहाने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में मजबूती से जोड़े रखने का हर संभव प्रयास में लग गये है. लोकसभा चुनाव के दौरान 'नमो सुनामी' के शिकार राजनीतिक दलों को तो और भी अधिक पसीना बहाने की नौबत नजर आ रही है. नेता भले ही मंच से जितनी भी गर्मजोशी से गरज लें, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल अब भी उठता नजर नहीं आ रहा है. पिछले दो बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए सीतामढ़ी जिले में अपनी मजबूत पकड़ की बदौलत सीटो पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है. साल 2005 के चुनाव में राजद के लालू विरोधी मतों का एक होने ने जहां नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का ओहदा तक दिला दिया, वहीं भाजपा से अलगाव का खामियाजा नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी की बलि देकर भुगतना पड़ा है. परंतु सूबे बिहार की राजनीति में 'विकास पुरुष' के रूप में चर्चित नीतीश कुमार अब अपने पुराने राजनीतिक शत्रु से गलबहियां को मजबूर हो गये हैं. अब एक बार फिर नीतीश ने जहां संपर्क यात्रा के बहाने जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी संजीवनी परोसने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके साथ पूर्व में सरकार चला चुकी भाजपा ने भी अपने नये गठबंधन की बदौलत राजनीतिक औकात बताने को कमर कस चुकी है.

जहां तक सीतामढ़ी जिले का सवाल है तो इस बार तकरीबन सभी दलों के संभावित प्रत्याशियों की बोलती बंद है. सूबे बिहार में चल रही गठबंधन की राजनीति ने उनकी मंशा को अधर में लटका दिया है. गठबंधन के तहत कौन सीट किस दल के पाले में जायेगी फिलहाल कहना मुश्किल हो रहा है. ऐसी स्थिति में किसी भी दल से कोई मुखर होकर बोलने को तैयार नहीं है. पिछले दिनों सीतामढ़ी शहर के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी का 14 वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहन झा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का उद्घाटन लोजपा की पूर्व विधायक नगीना देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया. राम विनय कुशवाहा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में लोजपा की मजबूती के लिए कार्य करने का संकल्प लिया. इस दौरान प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी बिजुल सिंह, डॉ. प्रो. बुद्धदेव सिंह, राष्ट्रीय सचिव राम पुकार राय, युवा अध्यक्ष गुंजन कुमार श्रीवास्तव, छात्र लोजपा जिलाध्यक्ष रजनीश यादव, दलित सेना जिलाध्यक्ष हरजीत पासवान, महिला प्रकोष्ठ की ममता देवी, अल्पसंख्यक के फखरुददीन अहमद, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की सुशीला देवी पासवान, मनोज कुमार, सरोज कुमार, संजय कुमार सिंह, जगदीश रमण, उमेश खिरहर, शंकर पासवान, डॉ. ब्रजेशचंद्र झा, अशरफ पप्पू, सुनील पासवान, अशोक गुप्ता, राकेश सिंह, मुकेश कुमार सिंह, नागेष पासवान, विनोद चौबे, शंभू राम, मुकेश कुमार पासवान, अवधेश राय व गंगा झा समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले में कम से कम तीन सीट पर लोजपा प्रत्याशी देने की मांग की.

पार्टी सूत्रों पर भरोसा करें तो लोजपा सीतामढ़ी के चार सीट पर अपना कब्जा जमाने को आतुर है. परंतु गठबंधन के कारण मजबूत दावेदारी पर फिलहाल ग्रहण लगता दिख रहा है.

खबर आ रही है कि जिले के तीन सीट सुरसंड, बेलसंड व रून्नीसैदपुर लोजपा नेताओं के निशाने पर है. जबकि चौथी सीट के रूप में रीगा व पांचवां बाजपट्टी पर भी नजर टिकाये बैठे हैं. बता दें कि उक्त तीनों अर्थात सुरसंड, बेलसंड व रून्नीसैदपुर सीट पर क्रमश: शाहिद अली खान, सुनीता सिंह चौहान व गुड्डी देवी जदयू से वर्तमान में विधायक है. किन्तु रीगा सीट से भाजपा के मोतीलाल प्रसाद विधायक है. इस सीट पर लोजपा के दावे का मतलब वर्तमान विधायक का आगामी चुनाव में बेटिकट होना माना जा सकता है. पार्टी सूत्रों पर भरोसा करे तो आगामी चुनाव में लोजपा से बतौर संभावित प्रत्याशी सुरसंड से पूर्व युवा प्रदेश लोजपा महासचिव सवीह अहमद एवं राजन सिंह दावेदारी कर सकते हैं. बताया जाता है कि सवीह की नजर में बाजपट्टी सीट भी है. जबकि बेलसंड विधानसभा सीट से युवा समाजसेवी असीम कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह प्रबल दावेदार है. इस सीट से इनके अलावा ब्रजेंद्र कुमार सिंह व पूर्व विधायक नगीना देवी के नाम की चर्चा चल रही है. लेकिन पूर्व विधायक नगीना देवी की हवेली से आ रही खबर पर यकीन करे तो वह बेलसंड नही बल्कि रीगा विधानसभा सीट से चुनाव की तैयारी में लगी है. रून्नीसैदपुर सीट से लोजपा के जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ झा उर्फ मोहन झा अपनी दावेदारी का झोला ढो रहे हैं. जबकि इस सीट से बतौर लोजपा प्रत्याशी चुनाव लड़ने की मंशा पिछले महीने मानिक चौक गांव में आयोजित रुन्नीसैदपुर के पूर्व विधायक स्व. महंत विवेकानंद गिरी की आदमकद प्रतिमा अनावरण समारोह की तैयारी में आलोक कुमार उर्फ पिंटू चौधरी ने साफ की है. इनके अलावा एक और संभावित प्रत्याशी पर लोगों की नजर टिकी है. बताया जाता है कि अपराध जगत की बादशाहत का त्याग कर राजनीति में प्रवेश को आतुर संतोष झा भी रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी दंगल में ताल ठोंकने वाले है. हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि वे किस दल की टिकट पर अपना भाग्य आजमायेंगे. परंतु प्रतिमा अनावरण समारोह के मौके पर रुन्नीसैदपुर के मानिक चौक गांव में संतोष के चुनावी ताम-झाम को लेकर चर्चाओं का बाजार अब तक गर्म है. इधर चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अब लोजपा के राष्ट्रीय सचिव राम पुकार राय भी रुन्नीसैदपुर से अपनी उम्मीदवारी को लेकर प्रयास शुरू कर दिया है. वैसे पार्टी नेतृत्व का निर्णय ही कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि होगा ऐसा माना जा रहा है.

वैसे अभी चुनाव में वक्त है. इस बीच जिले से लेकर प्रदेश तक की राजनीति में उतार-चढ़ाव की आशंका है. ऐसे में संभावित प्रत्याशियों की पलटन चाहे जितनी भी ख्याली पुलाव बना ले, लेकिन अंतिम फैसला समय आने पर ही होना तय माना जा रहा है. आम मतदाताओं में भी चुनाव को लेकर मंत्रणा लगभग शुरू हो चुकी है. अविश्वास के साथ लोग वैसे के हाथों ही प्रतिनिधित्व का कमान सौंपने की मंशा व्यक्त करने लगे हैं जो जनहित में कार्य करने वाला हो. फोटो खिंचाने के शौकीन नेताओं के झूठे वादा व घोषणाओं के अंबार पर अब किसी को भरोसा नही रह गया है. देखना है कि चुनाव के वक्त तक लोगों की धारणा यही रहती है अथवा फिर बदलेगी.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

15 दिसंबर–21 दिसंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बुद्ध की धरती पर ख़तरनाक सियासत

आंदोलन या प्रतिशोध

शत्रुंजय सिंह

महात्मा गांधी की खादी पहन कर नेतागीरी चमकाने वाले नेता आज वह हर कार्य कर रहे हैं जिससे गांधी शर्मसार हो रहे हैं. विश्व को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर के जटहां थाना इलाके में 21 नवम्बर को यही देखने को मिला. जहां कुछ भोले–भाले किसानों, मजदूरों व आयातित भीड़ का सहारा लेकर भारतीय किसान यूनियन के तथाकथित नेता ध्रुव नारायण यादव ने ईंट पत्थर लाठी व मिर्ची बम से लैस हो कर थाने पर हमला कर दिया. खेती–किसानी के मुद्दे पर घेराव का नारा देकर व्यक्तिगत रंजिश साधने की कारगुजारियां इस हमले से उजागर हुईं. नतीजा रहा कि वहां पर चली गोली व ईंट पत्थरों की बौछार से कई किसान व आम लोग तो घायल हुए ही, साथ ही जटहां के थानेदार पवन सिंह को खास तौर पर लक्ष्य बनाया गया. उनकी सर्विस रिवाल्वर छीन ली गई और उनकी भीषण पिटाई की गई. इस आक्रमण में बुरी तरह जख्मी ग्रामीण और पुलिसकर्मी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन थानेदार पवन सिंह गंभीर चोट लगने के कारण एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि ध्रुव नारायण यादव 15 नवम्बर को पडरौना के सुभाष चौक पर सड़क जाम कर धरना देते समय यह ऐलान किया था कि खाद, बीज, गन्ना मूल्य, अवैध शराब व अवैध बालू खनन के खिलाफ 21 नवम्बर को भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तहत जटहां थाने का घेराव किया जाएगा. मौके पर पहुंचे पडरौना के एडीएम सचिन कुमार सिंह को ज्ञापन भी सौंपा गया था. इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने ध्रुव नारायण के ऐलान को हल्के में लिया और जटहां थाने पर पर्याप्त पुलिस बल व जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं भेजा गया. जबकि कुशीनगर जनपद में किसान आंदोलन के नाम पर कई बार गोलियां चल चुकी हैं और वही स्थिति 21 नवम्बर को जटहां थाने पर भी हुई. किसानों और मजदूर हितों की आड़ में अपनी नेतागीरी चमकाने वाले नेता की शह पर हुई हिंसा में कई किसान जख्मी हुए. कई लोग भगदड़ में चली गोली का शिकार हुए. घटना के बाद राजनीतिक दल के नेता जटहां से लेकर विधानसभा व लोकसभा तक मुद्दा उठाने और किसानों के रहनुमा बनने की होड़ में शामिल हो रहे हैं. लेकिन कोई नेता हिंसा के पीछे की असलियत जानने को उत्सुक नहीं हुआ और न ही उसे मजदूर या किसान की, या खाद, पानी, बीज व गन्ना मूल्य की चिंता है. उग्र भीड़ की हिंसा में जख्मी हुए पुलिसकर्मी अपने इलाज के लिए भी मोहताज हैं. सबसे मुश्किल स्थिति उन चौकीदारों की हुई जो दिहाड़ी पर थानों की चौकीदारी करते हैं, लेकिन हिंसक घटना में घायल होने पर उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं होती.

ध्यान देने की बात यह है कि किसानों के जिन मुद्दों को लेकर जटहां थाने को घेरने का ऐलान किया गया था, उन मुद्दों पर राजनीतिक दल जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय व सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के कार्यालय या आवास के सामने धरना–प्रदर्शन करते हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि किसान यूनियन के तथाकथित नेता ध्रुव नारायण ने किसानों के उन्हीं मसलों को लेकर थाने का घेराव करने का ऐलान क्यों किया? घेराव के बहाने थानेदार को निशाने पर क्यों लिया गया? और थाने का घेराव करने की घोषणा के समय ही पुलिस प्रशासन ने इसके पीछे की नीयत क्यों नहीं भांपी? जब भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 21 नवम्बर को जिला मुख्यालय पर जनपद के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक करने का पहले से ऐलान था तो फिर ध्रुव नारायण यादव की घोषणा पर जिला और पुलिस प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? मुख्यालय पर चल रहे धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुटे थे तो उसी दिन जटहां थाने का घेराव करने वाले लोग कौन थे? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब प्रशासन के पास नहीं है. स्थानीय लोग तो यह भी कहते हैं कि पुलिस के ही कुछ अधिकारी ध्रुव नारायण के जरिए जटहां के थाना प्रभारी को निबटाना चाहते थे. भाकियू के उस कथित नेता ने जिस बालू के खनन का मुद्दा उठाया, वह उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि बिहार का मसला है और वहां बिहार सरकार की तरफ से जारी पट्टे पर बालू का खनन होता है. ग्रामीण खुद ही कहते हैं कि ध्रुव नारायण यादव का खाद बीज गन्ना मूल्य व बालू खनन का मुद्दा तो एक बहानाभर था. उसका मुख्य धंधा नेतागीरी के जरिए थानों पर हनक बनाने और पैसों की वसूली करना है.

हमले में घायल एसएचओ पवन सिंह

यह भांडा भी तब फुटा जब जटहां थाना अंतर्गत ग्रामसभा पकहा निवासी विद्यासागर ने थाने में तहरीर दी कि भाकियू का सदस्य बनाने के लिए ध्रुव नारायण ने 11 लोगों से 36 हजार रुपये लिए हैं. विद्यासागर का कहना है कि दो साल पहले तक ध्रुव नारायण खेती किसानी कर किसी तरह अपना परिवार चलाता था, आज वसूली के धंधे के कारण ही उसके पास मोटर साइकिल, डीआई जीप व पिकअप गाड़ी है. जटहां थाने में दी गई तहरीर पर थानेदार द्वारा ध्रुव नारायण के खिलाफ धारा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. ध्रुव नारायण के क्रियाकलापों से तंग आकर भारतीय किसान यूनियन के कुशीनगर जिला प्रभारी रणजीत सिंह ने संगठन विरोधी गतिविधियों एवं अनुशासनहीन कृत्यों के कारण उसे संगठन से निष्कासित कर रखा है. निष्कासन की बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी.

> **जटहां में हुई गोलीबारी और पथराव की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दे दिया गया है. कोई भी निर्दोष न प्रताड़ित होगा और न ही जेल जाएगा.**
>
> *–लोकेश एम, जिलाधिकारी*
>
> **जटहां में हुई हिंसक घटना शासन–प्रशासन की विफलता का नमूना है. अपने जरूरी मसलों पर किसान मजदूर आंदोलन करने पर विवश हैं. इसकी आड़ में कुछ लोग अपना धंधा चला रहे हैं.**
>
> *–शरद कुमार सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व घुघुली केन यूनियन के चेयरमैन*

इस घटना पर समाजसेवी डॉ. प्रदीप सिंह कहते हैं कि नेता आते हैं और विष डाल कर चल जाते हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण जनता भुगतती रहती है. ऐसे नेता व ऐसी नेतागीरी पर रोक लगनी चाहिए. 21 नवम्बर को किसान, मजदूर व पुलिसकर्मियों के बीच हुए गोलीबारी व पथराव में पुलिस प्रशासन और स्थानीय खुफिया एजेंसी (एलआईयू) की अकर्मण्यता या मिलीभगत साफ–साफ झलकती है. जटहां थाना क्षेत्र हमेशा ही संवेदनशील रहा है. इसके पूर्व में जंगल दस्यु के आतंक से ग्रामीण अपना गांव जवार छोड़ कर पलायन कर चुके हैं. तीन साल पहले जनपद में आए तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक लव कुमार ने जंगल दस्युओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और ग्रामीणों में विश्वास पैदा कर उनके पुनः वापस आने का रास्ता साफ किया. नतीजा रहा कि दशकों पहले गांव घर छोड़ कर पलायन कर चुके लोग वापस आ गए और अपनी खेती बारी करने लगे. जटहां थाना जनपद का ऐसा थाना है, जो बिहार सीमा के मुहाने पर है. थाना परिसर बाउंड्रीवाल न होने के कारण चारों तरफ से खुला है और उस क्षेत्र में बिहार के जंगल पार्टी दस्युओं का आना–जाना भी लगा रहता है. ऐसे में 21 नवम्बर को हुई घटना में जंगल पार्टी की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता. यह भी विडम्बना ही है कि जटहां थाने को उग्र भीड़ के हवाले कर दर्शक दीर्घा में बैठे आला पुलिस अधिकारियों ने हमलावरों पर कार्रवाई करने के बजाय हिंसा में जख्मी होकर अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती थानेदार पवन सिंह को ही सस्पेंड कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है. जिला पुलिस के अलमबरदारों की यह हरकत हास्यास्पद भी है और दुखद भी. ■

जिलाधिकारी लोकेश एम

feedback@chauthiduniya.com

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत

"आओ हम सब मिल कर एक साथ इस अभियान को सफल बनाएं"।

एवं

घर-घर में स्वच्छ एवं सुन्दर शौचालय बनवाएं।

एवं सुन्दर व स्वच्छ, स्वस्थ भारत का निर्माण करें।।

श्री नरेन्द्र मोदी जी
माननीय प्रधान मंत्री

-: सौजन्य से :-

राष्ट्रीय कृषि आयात-निर्यात परिषद

भारतीय कृषि शोध अनुसंधान

(आयात-निर्यात एवं कृषि शोध की अग्रणी)

(काशी नाथ तिवारी) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

(शम्मन त्रिपाठी) निदेशक (वित्त)

(जितेन्द्र प्रसाद रावत) निदेशक

(राकेश कुमार सिंह) प्रशासनिक अधिकारी

मुख्यालय- सी-183 इन्दिरा नगर लखनऊ (उ0प्र0) 226016

केन्द्रिय कार्यालय- एस-529 प्रथम-तल स्कूल ब्लाक लक्ष्मी नगर (यस बैंक के ऊपर नियर मेट्रो स्टेशन) नई दिल्ली-110092

यूपी में बढ़ रहा है नक्सलवाद

वैष्णवी वंदना

नक्सलियों का हमला हो या अपराधियों का, निशाना पुलिस के लोग ही बन रहे हैं. फर्रुखाबाद में अपराधी की गोली से उत्तर प्रदेश पुलिस के इंसपेक्टर राजकुमार सिंह की हत्या के तीसरे ही दिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में उत्तर प्रदेश के तीन युवक शहीदों की सूची में शरीक हो गए. नक्सल हमले में सीआरपीएफ के अफसर और जवान मिला कर 14 लोग शहीद हुए. छत्तीसगढ़ हमले में शहीद हुए तीन जवान कानपुर, इलाहाबाद और हापुड़ के रहने वाले थे. इनमें कानपुर निवासी डिप्टी कमांडेंट बी.एस. वर्मा, हापुड़ निवासी हेड कांस्टेबल कुलदीप पुनिया और इलाहाबाद निवासी कांस्टेबल मुकेश कुमार के नाम शामिल हैं. इस शहादत पर शोक जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शहीदों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की. लेकिन इस घोषणा में भी सियासत साफ-साफ झलकी. प्रतापगढ़ के कुंडा में सीओ जियाउल हक के मारे जाने पर मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपये के मुआवजे और मृत सीओ की पत्नी और एक अन्य सगे को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी. लेकिन शहादत पर महज 20 लाख के मुआवजे की घोषणा इस फर्क को खास तौर पर रेखांकित करती है. छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले से हुई शहादत की खबर मिलते ही कानपुर के नौबस्ता थाना से तीन किलोमीटर दूर खाड़ेपुर गांव में कोहराम मच गया. सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट बृजेन्द्र स्वरूप वर्मा के शहीद होने की खबर से उनके 90 वर्षीय पिता की हालत खराब हो गई. छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में चिंतागुफा के पास नक्सलियों से मोर्चा लेने वाली सीआरपीएफ बटालियन की अगुवाई खाड़ेपुर गांव के बेटे बृजेन्द्र कर रहे थे. बृजेन्द्र स्वरूप वर्मा की ही कर दी. कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी भी उनके घर पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि दी.

नक्सली हमले में शहीद चौदह जवानों में हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र के गांव जमालपुर के कुलदीप पुनिया का नाम भी शामिल है. शहादत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई. गांव जमालपुर निवासी किसान धर्मपाल सिंह का 26 वर्षीय पुत्र कुलदीप पुनिया सीआरपीएफ में 2009 में भर्ती हुए थे. कुलदीप डिप्टी कमांडेंट डीएस वर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कपूरिया और कोबरा बटालियन के जवानों के साथ चिंतागुफा के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन पर गया था. लौटते समय एलमागुंडा की पहाड़ी के पास नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इसमें वह 13 अन्य साथियों के साथ शहीद हो गए. शहीद कुलदीप धर्मपाल सिंह का इकलौता बेटा थे. गाजियाबाद के अटौला गांव में 15 दिसम्बर को ही उसकी शादी तय थी. परिजन शादी के कार्ड बांटने व अन्य तैयारियों में लगे थे. बीस दिन पहले ही कुलदीप घर से गया था. वह पांच दिन की छुट्टी लेकर आया था और गोद भराई की रस्म पूरी कर ड्यूटी पर लौट गया था. छत्तीसगढ़ नक्सल हमले में शहीद हुए इलाहाबाद के मुकेश कुमार के गांव में भी सन्नाटा छा गया है. मुकेश कुमार प्रयाग के गांव बाझा अतरामपुर नवाबगंज के रहने वाले थे.

मध्य प्रदेश को तोड़ कर बनाए गए छत्तीसगढ़ में राज्य के गठन के बाद आज तक नक्सली हमलों में एक हजार से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं. इसमें राज्य पुलिस के 595 और केंद्रीय बलों के 405 जवान व अधिकारी शामिल हैं. अकेले सीआरपीएफ के 327 जवानों ने शहादतें दी हैं. नक्सली ऑपरेशन के लिए तैनात किए गए 194 विशेष पुलिस अधिकारी शहीदों की संख्या में शुमार हैं. नक्सली मुठभेड़ में मारे गए अर्ध सैनिक बल के जवानों में उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से आने वाले जवान शामिल हैं. किसी एक ही घटना में सर्वाधिक सुरक्षाकर्मी ताड़मेटला की घटना में मारे गए थे. 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला में हुई घटना में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे. मार्च 2007 में रानीबोदली में विशेष पुलिस अधिकारी सहित 55 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे. पिछले करीब 14 वर्षों में 39 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें पांच या उससे अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं. वर्ष 2007 में सबसे ज्यादा 200 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे. वर्ष 2009 में 125 और वर्ष 2010 में 170 जवान शहीद हुए. इस साल 11 मार्च 2014 को टाहकवाड़ा में सीआरपीएफ के 16 जवान शहीद हुए थे. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच साल में ही नक्सली हमलों में देश में केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों के डेढ़ हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों की शहादतें हुई हैं. इनमें उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों से सुरक्षा बलों में भर्ती हुए जवान शामिल हैं.

इधर, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में भी नक्सली संगठन अपनी जड़ें जमाते जा रहे हैं. बिहार, ओड़ीशा और छत्तीसगढ़ से लगने वाली सीमा के अलावा नेपाल से लगने वाले सीमाई क्षेत्र में भी नक्सली गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं. सोनभद्र और चंदौली में नक्सलियों का खासा प्रभाव है. केवल इन्हीं दो जिलों में माओवादियों ने पुलिस के जवानों पर हमले की कई गतिविधियों को अंजाम दिया है. पिछले पांच साल में माओवादियों ने इन दिनों जिलों में करीब 50 घटनाएं की हैं. दो दर्जन से अधिक जवान मारे भी गए हैं. केंद्र में भाजपा की सरकार बनने और राजनाथ सिंह के गृहमंत्री बनने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस तरफ सतर्क और सक्रिय हुई हैं. पुलिस तंत्र का भी ध्यान गया है. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह खुद नक्सल प्रभावित जिले से आते हैं. उत्तर प्रदेश के नक्सल (माओवादी) प्रभावित जिलों में अतिरिक्त विशेष कार्यबल (एसएएफ) तैनात करने की कवायद चल रही है. अर्ध सैनिक बलों ने उत्तर प्रदेश में नक्सलियों के बढ़ते आतंक पर अलग से एक विस्तृत जमीनी रिपोर्ट तैयार की है और इसे गृह मंत्रालय के पास भेजा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ और बिहार से जुड़े होने की वजह से माओवादी इस राज्य का इस्तेमाल छुपने के लिए करते थे, लेकिन वे अब अपनी सक्रिय गतिविधियों का केंद्र बना रहे हैं. नेपाल के माओवादी

> **उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में कुख्यात नक्सली कृष्णा (एक लाख का इनामी) की गिरफ्तारी ने भी यह उजागर किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नक्सलियों का नेटवर्क फैल रहा है. एसटीएफ के हाथों बिहार में पकड़े गए नक्सली चंदन उर्फ चनारिक दास ने यह खुलासा किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का इस्तेमाल फरार नक्सली छुपने के लिए कर रहे हैं.**

यूपी के संगठनों को मदद पहुंचा रहे हैं. नेपाल के माओवादी यूपी में आकर यहां के नक्सलियों को ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहे हैं. आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सिर्फ दो जिलों को नक्सल प्रभावित मानती हो, लेकिन राज्य में तकरीबन 12 जिले ऐसे हैं जहां माओवादी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में तेजी से लगे हैं.

1994 में चंदौली जिले में 15 जवानों के मारे जाने के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी खूनी नक्सली वारदात तो नहीं हुई पर इसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. यूपी पुलिस की सबसे बड़ी चिंता बिहार और झारखंड से सटे इलाके हैं जहां नक्सलियों की तलाशी के साझा ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पा रहे. दोनों राज्यों में यूपी से सटी सीमा के 25 किलोमीटर भीतर तक पुलिस व सुरक्षा बलों की चौकियां तक नहीं हैं. इन इलाकों की निगरानी भी यूपी पुलिस को ही करनी पड़ रही है. पिछले कुछ अर्से में उत्तर प्रदेश में कई नक्सली मारे गए या गिरफ्तार किए गए. इनमें कमलेश चौधरी, कृष्णा वगैरह का नाम उल्लेखनीय है. कमलेश पर तो डेढ़ लाख का इनाम घोषित था. उसे यूपी में नक्सली हमलों के लिए भेजा गया था. उसका एक अन्य साथी शत्रुघ्न यूपी पुलिस के हाथों मारा गया था. इनके अलावा 50 हजार के इनामी गोपी उर्फ गिरधर गोपाल सोनभद्र के दुद्धी इलाके से गिरफ्तार किया गया था. पुलिसिया शब्दावली में बीजे सेक्टर नक्सली गतिविधियों का सक्रिय केंद्र है. बिहार-झारखंड और यूपी का सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली इसी बीजे सेक्टर में आते हैं. इन जिलों में नक्सली गतिविधियां तेज हैं. थ्री-यू सेक्टर, यानी उत्तरी बिहार, उत्तराखंड और अपर तराई बेल्ट के जिलों में नक्सलियों की गतिविधियां वैचारिकी के तौर पर चलाई जा रही हैं और उसे धीरे-धीरे एक्शन के लिए प्रगाढ़ किया जा रहा है. यूपी के बुंदेलखंड, इटावा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में भी नक्सली संगठनों की सक्रियता काफी बढ़ी है. पुलिस कहती है कि यूपी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के नाम से ये सक्रिय हैं, लेकिन कई गैर सरकारी संगठनों का दावा है कि ये लोग नक्सली नहीं हैं.

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में कुख्यात नक्सली कृष्णा (एक लाख का इनामी) की गिरफ्तारी ने भी यह उजागर किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नक्सलियों का नेटवर्क फैल रहा है. एसटीएफ के हाथों बिहार में पकड़े गए नक्सली चंदन उर्फ चनारिक दास ने यह खुलासा किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का इस्तेमाल फरार नक्सली छुपने के लिए कर रहे हैं. गिरफ्तारी से पहले चंदन खुद ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा में रहकर नक्सली गतिविधियों के लिए नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था. चंदन को पश्चिम यूपी में नेटवर्क फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

नक्सलियों के अलावा प्रदेश पुलिस के जवान अपराधियों का भी शिकार हो रहे हैं. नक्सली हमलों के इतर पिछले एक साल में देश के विभिन्न राज्यों में करीब सात सौ पुलिस वाले मारे गए. इनमें डेढ़ सौ के करीब पुलिसकर्मी तो उत्तर प्रदेश के ही हैं. अभी पिछले ही दिनों फर्रुखाबाद में एक अपराधी ने इंसपेक्टर राजकुमार सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी. उत्तर प्रदेश में पुलिस पर हमले की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन इसे रोकने के कोई उपाय नहीं हो रहे. यूपी के पुलिस के जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने की तत्काल जरूरत पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विधान परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज

चौथी दुनिया ब्यूरो

विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव, फिर राज्यसभा के चुनाव की औपचारिकता और अब विधान परिषद चुनाव की सरगर्मियां. उत्तर प्रदेश इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों में मुब्तिला है. प्रदेश में विधान परिषद के लिए खाली होने वाली सीटों पर चयन के लिए सत्ताधारी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य छोटी पार्टियों में भी सरगर्मी तेज हो गई है.

30 जनवरी 2015 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटें रिक्त हो रही हैं. इन सीटों के लिए जनवरी में ही चुनाव होंगे. इन 12 सीटों पर होने वाले चुनाव में बसपा को चार सीटों का नुकसान है, तो सपा को चार सीटों का फायदा होने वाला है. जबकि संख्या बल के हिसाब से भाजपा की एक सीट ही निकल सकती है. कांग्रेस-रालोद गठबंधन को एक सीट पाने के लिए अपने अंदरूनी समीकरण दुरुस्त करने होंगे. जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें बसपा के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अशोक कुमार सिद्धार्थ, प्रताप सिंह बघेल, लोकेश प्रजापति, महेश आर्य, धर्मप्रकाश भारती और डॉ. ओम प्रकाश त्रिपाठी शामिल हैं. सपा के कैबिनेट मंत्री अहमद हसन, डॉ. सरोजनी अग्रवाल और रमेश यादव का कार्यकाल भी 30 जनवरी को समाप्त हो रहा है. खाली होने वालों में भाजपा के विनोद पांडेय और बाबू राम एमकॉम का नाम भी शामिल है. 403 सदस्यों वाली मौजूदा विधानसभा में सपा के पास 235, बसपा के पास 80, भाजपा के पास 41 और कांग्रेस के पास 28 सदस्य हैं. रालोद के आठ, पीस पार्टी के चार (तीन सपा समर्थक), निर्दलीय छः, कौमी एकता दल के दो, टीएमसी, एनसीपी, आईएमसी और अपना दल के एक-एक और एक मनोनीत सदस्य हैं. इन्हीं 403 विधायकों को विधान परिषद के लिए 12 सदस्यों का चुनाव करना है. विधान परिषद सदस्य जाने वाले एक सदस्य के लिए 36 विधायकों का समर्थन जरूरी है. लिहाजा, 235 सदस्यों के समर्थन (वोट) से समाजवादी पार्टी अपने छः लोगों को विधान परिषद पहुंचा देगी. इसके बाद भी उसके पास 19 अतिरिक्त विधायकों के मत बचेंगे. इसी तरह अपने दो सदस्यों को जिताने के बाद बसपा के आठ वोट अतिरिक्त बचेंगे. भाजपा भी अपना एक सदस्य आसानी से जीता ले जाएगी और उसके पास पांच अतिरिक्त मत शेष बचेंगे. ऐसी स्थिति में अगर सपा ने अपना सातवां उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया या किसी ताकतवर निर्दलीय उम्मीदवार ने दावेदारी ठोक दी तो कांग्रेस को अपना उम्मीदवार जिताने में कठिनाई होगी. इससे निर्विरोध निर्वाचन की जगह, चुनाव का रास्ता खुलेगा. छोटी पार्टियों के वोट की खरीद-बिक्री की भी संभावना बढ़ जाएगी.

जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद उनका एक बार फिर विधान परिषद में जाना तय है, उनमें प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन और बसपा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम शामिल माना जा रहा है. सपा जिन अन्य लोगों को विधान परिषद में भेजने पर विचार कर रही है, उनमें समाजवादी छात्रसभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. उमाशंकर सिंह यादव, रामवृक्ष यादव, युवा नेता आनन्द भदौरिया और पूर्व मंत्री सुखदेव रमण सिंह के नाम शामिल होने की संभावना बताई जा रही है. [illegible] लेकिन 2017 के विधान सभा चुनाव को देखते हुए विधान परिषद की एक सीट के लिए भाजपा किसी पिछड़े को भी उम्मीदवार घोषित कर सकती है. [illegible] बहरहाल, समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर चिंतित और गम्भीर दोनों है. इसलिए वह ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जो प्रभावशाली हों और जनाधार वाली जातियों से सम्बन्धित मजबूत वोट बैंक को सपा के समर्थन में जुटाने में सक्षम हो. सपा नेतृत्व को इस बात का एहसास है कि बीते राज्यसभा चुनाव में किसी अति पिछड़े को उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, ऐसी स्थिति में विधान परिषद चुनाव में अतिपिछड़ों को प्रभावी उम्मीदवारी दी जा सकती है. प्रो. बाबू राम निषाद, लौटन राम निषाद, डॉ. राजपाल कश्यप, रामजतन राजभर, संजय लाठर, नानकदीन भुर्जी में से तीन या चार लोगों को सपा की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है. सपा पर अति पिछड़ों को उपेक्षित करने का आरोप भी लगता रहा है. इन शिकायतों या आरोपों से बचने के लिए सपा नेतृत्व अति पिछड़ों को संतुलित प्रतिनिधित्व पर विचार कर सकती है. [illegible]

भाजपा में भी अति पिछड़ों की दावेदारी को परिषद चुनाव में महत्व देने पर विचार चल रहा है. लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को 73 सीटों पर विजय दिलाने में अति पिछड़ों का मजबूत समर्थन भी महत्वपूर्ण रहा था. इन जातियों की तादाद प्रदेश में लगभग 12 प्रतिशत है. [illegible] ■

feedback@chauthiduniya.com

रामदेव का भागवत योग

राजकुमार शर्मा

धर्मनगरी हरिद्वार स्थित बाबा रामदेव पतंजली योगपीठ परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शिविर में बाबा रामदेव का खुलकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गुणगान करना बाबा के धुर विरोधी कांग्रेसियों को उन पर हमला बोलने का एक नया अवसर दे दिया है. बाबा ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सर संघसंचालक मोहन भागवत के सामने संघ का गुणगान किया तो विरोधियों ने बाबा के ऊपर गाना बना डाला. गाना कुछ इस तरह है कि बाबा के धोती के नीचे क्या है यह गीत बाबा रामदेव के हर विरोधियों की जुबान से सुना जा सकता है. विरोधियों का गाना के जरिए ये बताना है कि बाबा रामदेव ने भी संघ की खाकी पैंट पहन रखी है. गांधी परिवार के विरोधी के रूप में अपनी पहचान बना चुके बाबा रामदेव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ अपनी प्रगाढ़ता दिखाई थी. बाबा रामदेव कुछ दिनों पहले सरकारी खर्चे पर केदारधाम की यात्रा किया था और मुख्यमंत्री हीरश रावत की प्रशंसा भी की थी. इस पर बाबा रामदेव ने सफाई देते हुए कहा था कि संत किसी एक का नहीं होता, वह सबका होता है. बाबा पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की सरकार ने वक्र दृष्टि कर रखी थी, जिसका परिणाम रहा कि इनसे जुड़ी संस्थाओं पर सौ से अधिक मुकदमें हो गए थे. मोदी की सत्ता में वापसी के बाद ही बाबा के अच्छे दिन आने के संकेत मिलने लगे थे. बाबा रामदेव ने भागवत सत्ता के प्रभाव में आकर जिस प्रकार अपना योगासन बदला है, वह एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया है. भारत स्वाभिमान सेना से लेकर अपनी संगठन क्षमता के बल करोड़ो भारतीय जनमानस की आंखों का नूर बने बाबा ने जिस प्रकार अपनी ताकत का एहसास कराया था, उससे हिन्दुवादी ताकतों का बटने का खतरा संघ को सताने लगा था. बाबा को अपनी तरफ लाना और संघ के समक्ष नत मस्तक कराना यह पहले से ही संघ के एजेंडे में था. बाबा के संघ के पाले में आना संघ को एक विजय का एहसास करा रहा है. पहले भी बाबा के धुर विरोधी कांग्रेसी बाबा को धोती के नीचे संघ की पैंट पहनने की बात कहते थे, लेकिन बाबा के समर्थक इसे नकार दिया करते थे. बाबा रामदेव भी अब यू-टर्न ले चुके हैं, अब वह कालेधन को लेकर चुप हैं, अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यू-टर्न लेना समय की मांग लगने लगी है. बाबा के अंध समर्थक बने मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर अपने को ठगा-ठगा सा महसूस कर रहे हैं. संघ के इस आयोजन ने बाबा की संघ के प्रति एक निष्ठता तो बे पर्दा कर दिया है. बाबा को पूरी दुनिया में योग ने बड़ी पहचान दिलाई है. ■

हरीश ने अखिलेश से परिसंपत्तियों पर की चर्चा

रेनू शर्मा

उत्तराखंड की परिसंपत्तियों से कब्जा हटाने में चौदह वर्ष से दिलचस्पी न दिखाने वाले उत्तरप्रदेश को अचानक इस उत्तराखंड के हितों का ध्यान आ गया. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीधे देहरादून पहुंच गए. परिसंपत्तियों के बारे में मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ अखिलेश की बातचीत भी हुई, हरीश ने अपनी पूरी सरकार के साथ अखिलेश से मुलाकात की. राजनीतिक कारणों से गत डेढ़ दशक के मतभेद चंद लफ्जों के आदान-प्रदान से कैसे निपटाए जाएंगे. उत्तरप्रदेश के कब्जे में फंसी राज्य की 20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का विवाद कैसे निपटेगा यह कहना अभी मुश्किल है. नौ नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तो पुनर्गठन विधेयक में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि विभाजन के वक्त जो भी परिसंपत्तियां जिस रूप में जहां होंगी, इसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में रहेंगी. बावजूद इसके करीब डेढ़ दशक का वक्त गुजरने वाला है और उत्तराखंड सिंचाई विभाग की 20 हजार करोड़ की लागत की परिसंपत्तियों को वापस लेने के लिए कभी यूपी तो कभी केंद्र का दरवाजा खटखटा रहा है. इस बीच उत्तराखंड द्वारा आयोजित मुख्य सचिव स्तर की बैठकों को भी उत्तरप्रदेश ने कभी गंभीरता से नहीं लिया. इस बारे में राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार का कहना है कि कई बार दिल्ली व लखनऊ में बैठकें हुई, आश्वासन भी मिला, पहल नहीं की गई. हरीश का अखिलेश से बढ़कर गर बहिया करना राज्य के लिए राहत भरा भी है और हैरत भरा भी. राहत इसलिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद चलकर उत्तराखंड पहुंचे हैं और परिसंपत्तियों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री हरीश रावत से बातचीत भी की है. अन्य राज्यों की तरह जल बंटवारे को लेकर भविष्य में कोई विवाद न हो इसके लिए राज्य बनने के साथ ही केंद्र सरकार ने गंगा प्रबंधन बोर्ड गठित किए जाने का आदेश जारी कर दिया था. इसके अनुसार बैराज के रखरखाव व जल बंटवारा दोनों राज्य आपसी समझौते पर करेंगे और बैराज के रखरखाव पर आने वाला खर्च दोनों राज्य वहन करेंगे.

मौजूदा स्थिति यह है कि नदियों पर बने बैराज की मरम्मत उत्तराखंड कर रहा है और बैराज से निकलने वाली नहरों से उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, बैराज की मरम्मत का खर्चा उत्तर प्रदेश से नहीं मिल रहा है. इसमें उत्तराखंड को आपत्ति है. 2400 मेगावाट क्षमता के टिहरी बांध और 400 मेगावाट क्षमता के विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना से मिल रहे 25 फीसद शेयर छोड़ने को उत्तरप्रदेश तैयार नहीं. दोनों परियोजनाओं का जब अनुबंध हुआ, तब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था. वर्तमान में दोनों परियोजनाएं उत्तराखंड में हैं और पुनर्गठन विधेयक 2000 के अनुसार शेयर उत्तराखंड को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा. 9 नवम्बर 2000 के आदेश में कहा गया है कि जब तक गंगा प्रबंधन बोर्ड का गठन नहीं होता, उत्तरवर्ती राज्यों से वार्ता के बाद केंद्र सरकार परिसंपत्तियों के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में तय करेगी. इससे दो दिन पहले, 7 नवम्बर 2000 को जारी आदेश में कहा कि सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य अभियंता मेरठ के पास रहेगा, जबकि एक्ट में लिखा गया है कि उत्तरवर्ती राज्यों से परामर्श के बाद ही परिसंपत्तियों के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में तय होगा. यह आदेश इस तिथि को निकला जब उत्तराखंड अस्तित्व में था ही नहीं. फिर कौन से उत्तरवर्ती राज्यों का परामर्श लिया गया. इसी आदेश की वहज से आज तक इन मसलों का फैसला नहीं हो पाया. उत्तरप्रदेश परिसंपत्तियों से अपना कब्जा छोड़ता है तो इसे टिहरी व विष्णु प्रयाग से शेयर मिलना बंद हो जाएगा. हरिद्वार में वीआईपी घाट व लाखों एकड़ भूमि का अपने हितों के लिए उपयोग करने से वंचित हो जाएगा. उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि केंद्र का दरवाजा खटखटाने से परहेज करते रहे हैं. यही वजह है कि जो स्थिति 14 साल पहले थी वही आज भी है. पिछले 14 साल में उत्तरप्रदेश ने परिसंपत्तियों पर उत्तराखंड की नहीं सुनी मुख्य सचिव स्तर की वार्ताओं को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया.

> **"परिसंपत्तियों को लेकर दोनों प्रदेशों के बीच कोई विवाद नहीं है. उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है और उत्तराखंड छोटा भाई है. यह रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा.**
> **शिवपाल सिंह यादव, सिंचाई मंत्री यूपी"**

अरबों की परिसंपत्तियों का बंटवारा अभी भी लटका हुआ ही है, साथ ही विभिन्न महकमों के कार्मिकों की लगभग एक हजार करोड़ रुपये की पेंशन व जीपीएफ की धनराशि भी उत्तराखंड को हासिल नहीं हो पाई है. इनमें परिवहन और ऊर्जा विभाग की धनराशि सर्वाधिक है. दिलचस्प बात यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के दौरान परिसंपत्तियों के बंटवारे का मसला तो मुख्य रहा, लेकिन पेंशन व जीपीएफ धनराशि पर चर्चा नहीं हुई. उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद सरकारी कार्मिकों का बटवारा तो कर दिया गया मगर कुछ विभागों में उत्तराखंड के हिस्से आए कार्मिकों के पेंशन व जीपीएफ आदि देयकों का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है. उत्तराखंड परिवहन निगम का गठन वर्ष 2003 में किया गया. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मध्य पेंशन दायित्व के विभाजन की स्थिति में इत्तराखंड को 740 करोड़ की धनराशि मिलनी थी. इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 250 करोड़ की धनराशि का तो भुगतान उत्तराखंड को कर दिया गया बाकी 490 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए उत्तराखंड अब भी उत्तर प्रदेश का इंतजार कर रहा है. कुछ ऐसी ही स्थिति ऊर्जा विभाग की भी है. जनवरी 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विघटन के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जलविद्युत निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केस्को के कार्मिकों के जीपीएफ की धनराशि 1634 करोड़ रुपये का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को कर दिया, लेकिन उत्तराखंड को अब तक इसमें अपना हिस्सा नहीं मिला. उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड 160 करोड़ की देय के साथ ही उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन को जीपीएफ का 127 करोड़ रुपये का भुगतान भी अब तक नहीं हो पाया है. यही नहीं, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के कार्मिकों की जीपीएफ की 115 करोड़ की धनराशि भी उत्तर प्रदेश से अब तक उत्तराखंड को नहीं मिली. राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड के सभी देयकों का भुगतान भी जल्द सुनिश्चित करना चाहिए. परिसंपत्तियों और उत्तराखंड को मिलने वाले देयकों के भुगतान के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत ब्योरा एकत्र कर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को श्री भट्ट इस संबंध में पत्र लिख चुके हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों मुख्यमंत्रियों अखिलेश यादव व हरीश रावत के मध्य इस संबंध में हुई वार्ता के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और राज्य को अब जल्द इसका वाजिब हक मिल सकेगा. ■

लालबत्ती हरीश के गले की फांस बन सकती है

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तराखंड की सबसे स्थायी सरकार माने जाने वाली नारायण दत्त तिवारी(एन.डी.तिवरी) की सरकार कभी लालबत्ती के डोंलों के चलते सत्ता गंवा चुकी है, कांग्रेस ने एक बार फिर से इसी आत्मघाती रास्ते पर चलने का मन बना लिया है. कांग्रेस हाईकमान पद के लोभियों के दबाव के समक्ष नतमस्तक होती दिख रही है. हरीश सरकार फिर से बड़े पैमाने पर दायित्व बांटने की तैयारी में है. हरीश को पूरी तरह से यह पता है कि उनका यह कदम आत्मघाती सिद्ध होगा इसी वजह से वह हर एक दिन इस बला से बचना चाहते है. कांग्रेस में गुटीय संघर्ष और कार्यकर्ताओं की ओर से सत्ता सुख भोगने का इतना दबाव है कि सरकार के स्तर पर करीब सौ लोगों की सूची तैयार है जिन्हें चरणवद्ध तरीके से दायित्वों से नवाजा जाएगा. जानकार मानते हैं कि यह कार्य भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए मुद्दा देने वाला सिद्ध हो सकता है.

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी के साथ मंथन के बाद करीब सौ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नाम फाइनल किए गए हैं. इतने कांग्रेसियों को दायित्व देने से राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा. सरकार 2007 की तरह विपक्ष के निशाने पर आ जाएगी. मार्च 2012 में भाजपा से सत्ता झटकने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी दर्जनों को दायित्व बांटे थे. कुर्सी से हटने से पहले जनवरी 2014 में विजय बहुगुणा कई करीबियों को बैकडेट में दायित्व देकर सरकारी सुविधाओं से नवाज गए. बहुगुणा ने अपने कार्यकाल में करीब 55 लोगों को दायित्व दिए. फरवरी में हरीश रावत के सत्ता संभालने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के साथ सभी विधायकों को सभा सचिव बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया. इसके पीछे कांग्रेस में गुटबाजी को थामने की विवशता थी. इसके बावजूद कार्यकर्ताओं को दायित्व देने की मांग उठती रही है. दायित्वधारियों का वेतन मामूली है भत्तों और अन्य सुविधाओं पर हर महीने भारी खर्च होता है. हरीश ने सत्ता संभालने के बाद दो पार्टी नेताओं को बड़े दायित्व दिये हैं. इनमें पूर्व विधायक रंजीत रावत और धारचूला से उनके लिए विधानसभा सीट खाली करने वाले हरीश धामी हैं. रावत पर बहुगुणा गुट की ओर से दबाव है. सूत्रों का कहना है कि विरोधी गुट के विधायक भी करीबियों को सत्ता सुख चखाने के लिए जोड़तोड़ में हैं. यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को विभिन्न आयोगों, बोर्ड और अन्य पदों पर एडजस्ट करने की योजना है. इतना तय है कि इससे कांग्रेस एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ जाएगी.

अब कांग्रेसियों की नजरें एक बार फिर लालबत्तियों के बंटवारे पर टिक गई हैं. प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले दायित्व को लेकर कांग्रेसियों में अच्छे दिन लौटने का अब बेसब्री से इंतजार भी होने लगा है. चमोली जिले में भी तमाम कांग्रेसी सत्ता मिलने के बाद से ही दायित्व को लेकर कसरत में जुटे हुए हैं. इसके लिए वे विधायकों के साथ ही मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक तार जोड़ते रहे हैं, यहां तक कि संगठन के आकाओं पर भी कांग्रेसियों ने दबाव बनाया हुआ है, उन्हें नवंबर में दायित्व मिलने की पूरी-पूरी उम्मीदें थीं, राजनीतिक कारणों से समय पर दायित्व न मिलने से अब उनका सब्र भी डोलने लगा था. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने थोक के भाव दायित्व देने का ऐलान किया तो कांग्रेसियों के चेहरों पर रौनक लौटने लगी है. दायित्व निर्धारण में सरकार ने किस तरह की कैटेगिरी और कसौटी बनाई है, इसका तो कोई संकेत नहीं मिला है, सीएम की घोषणा मात्र से उनके चेहरों की रौनक देखते ही बन रही है. अब जबकि करीब ढाई साल ही सरकार का कार्यकाल रह गया है तो दायित्वों अथवा लालबत्तियों को लेकर लाइन में लगे कांग्रेसियों के सब्र का बांध भी एक तरह से टूटने लगा है. कांग्रेस राज में विभिन्न न्यायालयों में कांग्रेसी पृष्ठभूमि के अधिवक्ताओं को भी कोई जगह नहीं मिल पाई है. इस तरह के हालातों से कांग्रेसी सत्ता सुख का लाभ लेने से अभी तक भी वंचित हैं. ऐसे में अब जबकि मुख्यमंत्री ने लिस्ट तैयार होने की बात कह कर कांग्रेसियों को दायित्वों से नवाजने की घोषणा की है तो कांग्रेसी शिविर में आज यह चर्चा आम रही कि अब इनके भी अच्छे दिन आने वाले हैं.

यह एक सच्चाई है कि पूरे देश में मोदी लहर का परचम लहरा रहा है. इस हिमालयी राज्य की पांच की पांचों सीटे भाजपा की झोली में पहले ही जा चुकी है, कांग्रेस ने अपने समय की नजाकत को पहचान कर उत्तराखण्ड में अपने दाग दार दामन के लिए चर्चा में रहे विजय बहुगुणा को हटा कर जमीन से जुड़े नेता हरीश के साथ न्याय करते हुए मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला लिया वह इतना सफल, सामायिक सिद्ध हुआ की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी हाथ मलते रह गयी. राजनीति के मर्मज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस ने पद लौलूप नेताओं के दबाव में घुटना टेकते हुए लालबत्ती बाटने की भूल किया की विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहावत चरितार्थ हो सकती है. ■

उत्तराखंड में सपा को डिम्पल का सहारा

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तराखंड में जड़ें जमाने के लिए जूझ रही सपा के नेता चाहते हैं कि प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री अशिलेश यादव की पत्नी हिमालय की बेटी सांसद डिंपल यादव संभालें. सपा का स्थानीय नेतृत्व डिंम्पल की सिम्पल क्षवि से पुरी तरह प्रभावित है और मानता है कि सपा को साइकिल हिमालयी राज्य में चलानी है तो इस पर डिम्पल को सवार करना होगा. उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रो. एस.एन. सचान ने इस बाबत अखिलेश यादव से बात भी की तो अखिलेश बोले कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) से बात कर लीजिएगा. इस तरह से हमारा कहना कुछ भी ठीक नहीं है. सपा प्रदेश अध्यक्ष सचान ने बताया कि इस संबंध में हाईकमान से भी बात चल रही है. पार्टी नेतृत्व से तीन-चार दिन पहले भी इस बाबत बात हुई थी. वैसे लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां नहीं आए थे. सूत्रों का कहना है कि सपा नेतृत्व मानता है कि राज्य निर्माण के समय उनकी स्वयं भूमिका के कारण इसके लिए उत्तराखंड में पैर जमा पाना टेढ़ी खीर है. डिंपल को उत्ताराखंड में आगे करने की नेताओं की लगातार अपील का असर दिखता नजर आ रहा है. इसी का परिणाम है कि कार्यक्रमों के बहाने सपा नेता प्रदेश में आवाजाही बढ़ाएंगे.सूत्र तो यहा तक बताते है कि अखिलेश के ससुराल प्रेम के पिछे डिम्पल की मंसा ही चल रही है,निकट भविश्य में अखिलेश उत्तराखंड में एक शानदार आशियाना भी बनाना चाहते हैं. जब उत्तराखंड अलग राज्य बना है तब से सपा वहां कमजोर है और उत्तराखंड में कोई चम्तकार नहीं कर पाई. अब सपा डिम्पल यादव के सहारे पहाड़ पर चढ़ने कोशिश में है. ■